FOCUS NEWS
फोकस न्यूज

facebook.com/fnind
twitter.com/fnind
focusnewsindia.blogspot.in
www.focusnews.co.in
+focusnewsin

...आपका अपना अखबार

राष्ट्रीय संस्करण। नई दिल्ली। सोमवार 16 मार्च 2026। त्रयोदशी, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष। 2081 विक्रम संवत । पेज – 12 । मूल्य 2 रु । वर्ष : 13। अंक : 243

बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा, चार मई को होगी मतगणना

। कृष्णा अग्रवाल ।

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। सभी राज्यों में मतगणना चार मई को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। कुमार ने बताया कि केरल, असम और पुडुचेरी के लिए नौ अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा चुनाव के लिए 824 सीटों पर मतगणना चार मई को होगी। कुमार ने कहा कि चुनाव हिंसा या प्रलोभन से मुक्त होने चाहिए और आयोग किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कुमार के साथ दो निर्वाचन आयुक्त – सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, ''शुद्ध मतदाता सूची हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है; किसी भी पात्र मतदाता को हटाया नहीं जाना चाहिए और किसी भी अपात्र मतदाता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।'' उन्होंने बताया कि पांच राज्य विधानसभाओं के 824 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में कुल 17.4 करोड़ पात्र मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जहां 25 लाख चुनाव अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या ऑस्ट्रेलिया, (शेष पेज दो पर)

भाजपा शासन में बदली असम की स्वास्थ्य व्यवस्था: अमित शाह

गुवाहाटी, फोकस न्यूज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम में 15 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सेवा बजट से प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये ''अपनी जेब में डाल लिए''। शाह ने कहा कि दूसरी ओर, भाजपा ने राज्य में अपने 10 साल के शासनकाल में इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। शाह ने 2,092 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखते हुए कहा, ''10 साल पहले असम की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था बदहाल थी क्योंकि कांग्रेस केवल अपने नेताओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति के लिए काम कर रही थी।'' केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि 2016 तक कांग्रेस के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ था और कहा, ''15 वर्षों तक, हर साल, राज्य के स्वास्थ्य बजट से 150 करोड़ रुपये उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए।'' उन्होंने कहा, ''इन रुपयों को नौ लाख ऐसे बच्चों के इलाज पर खर्च दिखाया गया जो कभी पैदा ही नहीं हुए और 390 आंगनवाड़ी केंद्रों पर खर्च दिखाया गया जिनका निर्माण कभी हुआ ही नहीं।'' शाह ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए काम करती है और उन्होंने राज्य की चिकित्सा सुविधाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के बराबर लाने के लिए (शेष पेज दो पर)

हरियाणा में 2025 तक 35 प्रतिशत पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया

हरियाणा की कुल ग्राम पंचायतों में से लगभग 35 प्रतिशत पंचायतें 2025 में सत्यापन के बाद टीबी–मुक्त घोषित किए जाने के योग्य पाई गई हैं।

वर्तमान की 21 अंक वाली प्रणाली अच्छी, प्रारूप में बदलाव पर सतर्कता बरतनी चाहिए: साइना नेहवाल

ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) से स्कोरिंग में प्रस्तावित बदलाव पर सतर्कता बरतने का आग्रह किया है और उनका मानना है कि वर्तमान की 21 अंक की प्रणाली खेल की गति और दमखम बनाए रखती है।

उपभोक्ता आयोग ने असफल एटीएम लेनदेन मामले में एक्सिस बैंक को मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के नागपुर स्थित उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के मामले में एक्सिस बैंक को फटकार लगाते हुए उसे एक ग्राहक को राशि वापस करने और 10,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

खाना बनाएं हैल्दी

सर्दियों में चटपटा और गर्म खाने का मन खूब करता है। सर्दियों में वजन भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि तले हुए और मीठे व्यंजन खूब खाए जाते हैं।

पेप्सी ने 'सैयारा' के कलाकार अहान पांडेय और अनीत पड्डा को ब्रांड एम्बैसडर बनाया

गर्मियों के मौसम से पहले शीतल पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सिको की भारतीय इकाई ने युवाओं, खासकर नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए फिल्म 'सैयारा' के अभिनेता अहान पांडेय और अभिनेत्री अनीत पड्डा को अपने नए प्रचार अभियानों का चेहरा बनाया है।

आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बदलाव की जरूरत: संसदीय समिति

संसद की एक समिति ने आयकर विभाग से उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने से पहले कर विवाद के मामलों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ मुकदमा समिति गठित करने को कहा है।

अदाणी पावर को महाराष्ट्र में 1,600 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए ठेका मिला

अदाणी पावर ने बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड से 1,600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए 'लेटर ऑफ अवार्ड' (एलओए) मिला है।

राजनाथ ने खेल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को देश की खेल अर्थव्यवस्था को नयी दिशा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने यहां आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप के फाइनल मैच में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''सरकार कई पहलों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जहां खिलाड़ियों और युवाओं को अवसर, संसाधन उपलब्ध हों तथा उन्हें सम्मान मिले।'' सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सरकार, निजी क्षेत्र और विभिन्न सामाजिक समूह मिलकर काम करें तो निकट भविष्य में भारत खेलों, विशेष रूप से पोलो में, अपनी एक मजबूत वैश्विक पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि पोलो देश की खेल परंपराओं में गहराई से निहित है और इसे सही मायने में भारत का ''धरोहर खेल'' घोषित किया जा सकता है।

एलपीजी की कमी को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : रेखा गुप्ता

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलपीजी की संभावित कमी के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए रविवार को कहा कि इस तरह की गलत सूचना लोगों में अनावश्यक दहशत पैदा कर रही है। गुप्ता ने बुधपुर के अपना घर आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही एलपीजी की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं और आम नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व भ्रामक जानकारी फैलाकर भय पैदा करने और जमाखोरी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, जोकि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और साथ ही चेतावनी दी कि गलत सूचना फैलाने या गलत काम में लिप्त पाए जाने (शेष पेज दो पर)

उत्तराखंड में 'बूथ जीता, चुनाव जीता' के मूल मंत्र पर काम करें भाजपा कार्यकर्ता : तरुण चुघ

देहरादून, फोकस न्यूज, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी 'बूथ जीता, चुनाव जीता' के मूल मंत्र के आधार पर करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यहां पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में अपने संबोधन में चुघ ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तराखंड में भी पार्टी का प्रशिक्षण अभियान जारी है। उन्होंने कहा, ''इस प्रशिक्षण अभियान में हमें बूथ क्षमता मजबूत करने पर सर्वाधिक जोर देना है। (शेष पेज दो पर)

रानी पद्मिनी का बलिदान महिलाओं की गरिमा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के संकल्प का प्रतीक: योगी

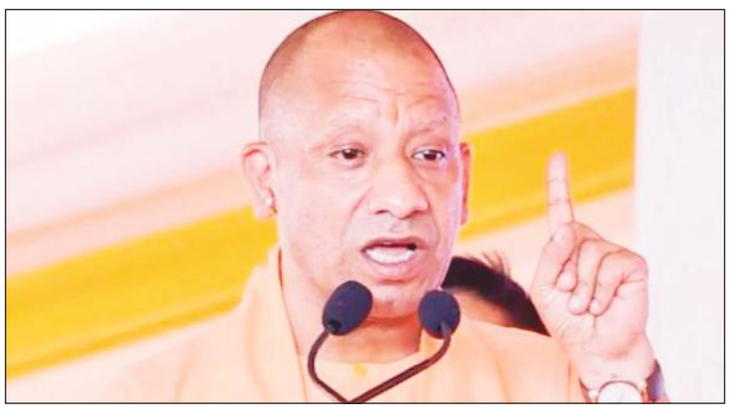

जयपुर, फोकस न्यूज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का बलिदान महिलाओं की गरिमा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित जौहर मेला और श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेवाड़ की महिलाओं द्वारा किया गया ऐतिहासिक जौहर साहस, आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनी तो अपराध और अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतने की नीति अपनाई गई और महिलाओं की गरिमा व (शेष पेज दो पर)

केरल विधानसभा चुनाव: माकपा ने 81 उम्मीदवारों की घोषणा की, मुख्यमंत्री विजयन और 11 मंत्री मैदान में

तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल के 11 सहयोगी सत्तारूढ़ माकपा द्वारा रविवार को घोषित किए गए राज्य में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के 81 उम्मीदवारों में शामिल हैं। नयी दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में सूची जारी की। उन्होंने कहा कि घोषित 81 उम्मीदवारों में से छह पार्टी समर्थित निर्दलीय हैं। पांच निर्वाचन क्षेत्रों (कोडुवल्ली, कोट्टक्कल, कोंडोट्टी, तिरुर और पलक्कड़) के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि 56 मौजूदा विधायक चुनाव मैदान में हैं और मुख्यमंत्री विजयन के अलावा 11 मंत्री भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। गोविंदन ने कहा कि विजयन माकपा पोलित ब्यूरो के एकमात्र सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ए एन शमसीर (वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष) और एम एम मणि (इडुक्की जिले के पार्टी के एक अनुभवी नेता हैं) सूची में जगह पाने में असफल रहे। विजयन उत्तरी कन्नूर जिले के अपने मौजूदा विधानसभा क्षेत्र धर्मदम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के. के. शैलजा कन्नूर के परवूर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाएंगी। विजयन के अलावा चुनाव लड़ रहे मंत्रियों में ओ आर केलू (मनंथावाडी), पी ए मोहम्मद (शेष पेज दो पर)

कटि सौंदर्य खोती महिलाएं

सुन्दर दिखने व सुन्दर बने रहने की चाह प्रत्येक व्यक्ति में हमेशा से रही है। यह लालसा प्राचीनकाल में भी थी, आज भी है। सौन्दर्य प्रकृति की अनुपम देन है। सुन्दर पुरुष की ओर स्त्रियां और सुन्दर स्त्रियों की ओर पुरुष स्वाभाविक ही आकर्षित होते हैं। यह प्राकृतिक स्वभाव ही है। वैसे ही स्त्री के सभी शारीरिक अंग किसी न किसी वस्तु से तुलना करने पर उपमा के काबिल माने जाते हैं जैसे–काले लंबे घुंघराले बाल, सुराहीदार गरदन, तिरछी नजर, पैनी भौंहें, गुलाबी होंठ, पतली कमर, खिलता हुआ चेहरा, धूप सा सफेद रंग इत्यादि लेकिन (शेष पेज दो पर)

जीवन को घेरता अकेलापन

पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित आज के एकल परिवारों में जिस असाध्य रोग का सामना कर पड़ रहा है वह है अकेलापन। एक से तीसरे मुंह यही सुनने में आता है कि बड़ा अकेला महसूस करते हैं। सच भी है जहां संयुक्त परिवारों के विघटन से कुछ हितकारी परिणाम हैं तो वहीं एकाकीपन जैसे लाइलाज रोग का भी घर घर में निवास सा हो गया है।

आज के मशीनीकरण में मानव मन ने दूरियां बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, क्योंकि पहले संपूर्ण कार्य हाथों द्वारा किया जाता था जिससे एक दूसरे का हाथ बांटने के कारण समीपता लाजमी थी लेकिन आज अधिक से अधिक कार्य मशीनों द्वारा संभव है। इसीलिए एक को दूसरे की आवश्यकता की कमी के कारण उपजा है अकेलापन। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि यह रोग स्त्रियों में अधिक देखने में आता है। आइये जीवन को सकारात्मक सोच देते हुए कुछ खास बनाने हेतु सूत्रा बनाने और एकाकीपन से छुटकारे के विकल्प भी तलाश करें। सर्वप्रथम तो जीवन में कुछ रचनात्मकता का समावेश करिए। (शेष पेज दो पर)

बंगाल, तमिलनाडु.... (पेज एक का शेष) फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कनाडा की जनसंख्या के बराबर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 20 देशों के चुनाव निकायों के प्रतिनिधि भारत के ''लोकतंत्र के उत्सव'' का अनुभव प्राप्त करने के लिए चुनाव वाले राज्यों का दौरा करेंगे। कुमार ने बताया कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या 750–900 है। कुमार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अच्छा काम करने के लिए बीएलओ को बधाई भी दी। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत अपलोड करेंगे और चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान के आंकड़े अपलोड किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ ही मिनट पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के बकाया भुगतान तथा पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर, कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अब इस तरह की कोई घोषणा नहीं की जा सकती। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीट हैं, जहां द्रमुक नेता एम. के. स्टालिन सात मई, 2021 से मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में हैं। केरल में कुल 140 विधानसभा सीट हैं, जहां वामपंथी नेता पिनराई विजयन 2016 से मुख्यमंत्री हैं और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। असम में विधानसभा की 126 सीट हैं और पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा 2016 से सत्ता में है तथा हिमंत विश्व शर्मा 2021 से मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी 2021 से सत्ता में हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 33 सीट हैं, जिनमें केंद्र द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल हैं। असम, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनाव अधिसूचना 16 मार्च को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। तमिलनाडु में चुनाव संबंधी अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच सात अप्रैल को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च को, जबकि दूसरे चरण के लिए दो अप्रैल को जारी की जाएंगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अप्रैल है और दूसरे चरण के लिए नौ अप्रैल है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच सात अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 10 अप्रैल को होगी। पहले चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 13 अप्रैल है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीट पर और दूसरे चरण में 142 सीट पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल सात मई को, तमिलनाडु में 10 मई को, असम में 20 मई को, केरल में 23 मई को और पुडुचेरी में 15 जून को समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल में 7.04 करोड़, तमिलनाडु में 5.67 करोड़, केरल में 2.7 करोड़, असम में 2.5 करोड़ और पुडुचेरी में 9.44 लाख मतदाता हैं।

रानी पद्मिनी... (पेज एक का शेष) सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, "पहले लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूर–दराज रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता था लेकिन अब वे अपने घर पर रहकर पांच से दस किलोमीटर दूर स्थित स्कूलों तक जा सकती हैं।" उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बेटियां और बहनें रात की शिफ्ट में भी दफ्तरों व फैक्टरियों में काम करती हैं व सुरक्षित घर लौटती हैं। योगी ने कहा कि यह राज्य में बेहतर सुरक्षा वातावरण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों की प्रेरणा राजस्थान की वीरता और परंपराओं से भी मिली है, विशेषकर मेवाड़ व चित्तौड़गढ़ की विरासत से। उन्होंने कहा कि जब भी चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ की वीरता व शौर्य की चर्चा होती है, तो योद्धाओं के साहस और वीरांगनाओं के बलिदान की कहानियां सामने आती हैं। योगी ने मेवाड़ की महिलाओं के जौहर और मीरा बाई की भक्ति को याद करते हुए कहा कि ऐसी परंपराएं पूरे देश को प्रेरित करती हैं। उन्होंने कार्यक्रम से पहले किले में जौहर स्थल पर जाकर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी और कालिका माता मंदिर में पूजा की। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे।

कटि सौंदर्य... (पेज एक का शेष) जहां तक पतली कमर का प्रश्न है, वह आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। आज की नारी–सौन्दर्य में उसकी कटि धीरे–धीरे सभ्यता के विकास के साथ अपना आकर्षण लुप्त–सा करती जा रही है। शहरी विकास और आधुनिकीकरण से पतली और लचकदार कमर कम ही दिखलाई पड़ती है। शहर के हर क्षेत्र में प्रायः बाजार, होटल, सिनेमाघर, सड़क और पार्कों में जिधर देखो, मोटी कमर और उसके आगे मोटा–सा पेट दिखलाई देता है। पेट मानो ढोल का सा एहसास दिलाता है। महिलाएं मोटापे को सुख, समृद्धि व सौभाग्य की निशानी समझती हैं। स्वयं को खाते–पीते घर की कहती हैं। इस मोटापे का मुख्य कारण अधिक गरिष्ठ भोजन करना, परिश्रम न करना, समय पर न खाना, व्यायाम आदि न करना है। चर्बी जब पेट के चारों ओर जम जाती है तब कमर व पेट को बेडौल बनाती है। इससे धीरे–धीरे चलते–फिरने, सीढ़ी चढ़ने, सांस लेने व दैनिक कार्य करने में अड़चन पैदा होती है। कमर में दर्द इसी कारण होता है। जब कमर की चर्बी का अतिरिक्त वजन कमर की पेशियां संभाल नहीं पाती तो दर्द शुरू हो जाता है। अतः चिकनाई का प्रयोग कम करें। ताजे फल व हरी–सब्जियां लें। भोजन की मात्रा कम करें।

केरल विधानसभा... (पेज एक का शेष) रियास (बेपोर), वी अब्दुरहिमान (तनूर), एमबी राजेश (थ्रिथला), आर बिंदू (इरिंजलाकुडा), पी राजीव (कालामस्सेरी), वी एन वासवन (एट्टुमानूर), साजी चेरियन (चेंगन्नूर), वीना जॉर्ज (अरनमुला), के एन बालगोपाल (कोट्टाराक्करा) और वी. शिवनकुट्टी (नेमोम) शामिल हैं। माकपा द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची में 10 महिला उम्मीदवार हैं। उनमें के के शैलजा, पी के श्यामला, के संथाकुमारी, आर बिंदू, एमबी शाइनी, पुष्पा दास, डालिमा जोजो, यू प्रतिभा, वीना जॉर्ज और ओ एस अंबिका शामिल हैं। इनमें से दो मंत्री और एक पूर्व मंत्री हैं। तालिपारम्बा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही श्यामला, गोविंदन की पत्नी हैं। गोविंदन ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने सभी क्षेत्रों में जनहितैषी कल्याण और विकास सुनिश्चित किया है और पिछले दस साल में कई ऐसी परियोजनाओं को लागू किया गया है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछला 10 साल राज्य में सांप्रदायिकता और संघर्षों से मुक्त रहा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया गया। पार्टी ने पुडुचेरी के माहे निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार टी अशोक कुमार (स्वतंत्र) की भी घोषणा की है। यहां नौ अप्रैल को मतदान होगा।

एलपीजी की... (पेज एक का शेष) वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता ने आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखने की भी अपील की। इससे पहले, दिन में मुख्यमंत्री बुधपुर में अपना घर आश्रम के 12वीं वर्षगांठ समारोह और रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुईं, जहां उन्होंने बेसहारा और परित्यक्त लोगों की सेवा के लिए संगठन के कार्यों की प्रशंसा की।

उत्तराखंड में... (पेज एक का शेष) हमारे राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर हम सबका एक ही मूल मंत्र होना चाहिए 'बूथ जीता, चुनाव जीता'।'' चुघ ने कहा कि पार्टी को राजनीतिक क्षेत्र में अजर–अमर बनाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है, जिसके तहत मजबूत संगठन के साथ ही चुनावी दृष्टि से सक्रिय एवं सक्षम बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) बनाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर संतुष्टि जतायी कि उत्तराखंड में पार्टी शत प्रतिशत बीएलए–प्रथम बना चुकी है जबकि शीघ्र ही बीएलए–द्वितीय भी बना दिए जाएंगे। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट समेत सांसद, विधायक, पूर्व विधायक एवं प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री धामी को चार वर्ष पूरे करने वाले प्रदेश में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए कहा कि धामी आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का निर्माण कर रहे हैं। गौतम ने कहा कि धामी जनता के मन को जीतने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कहे अनुसार सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। उन्होंने पार्टी के विधायकों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जोश और तैयारी बताती है कि नए उत्तराखंड का निर्माण हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता भाजपा की राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विचारधारा के साथ है और उसे केंद्र तथा राज्य की 'डबल इंजन' सरकार के कामों पर पूरा भरोसा है। धामी ने विपक्ष पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हमेशा की तरह सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं में खुलकर सहयोग करना है ताकि मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो। भट्ट ने विश्वास जताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य के बल पर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी।

भाजपा शासन... (पेज एक का शेष) मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''दस वर्षों में असम चिकित्सा देखभाल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है।'' कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करने के उनके प्रयास में देश को ''बदनाम'' करने के उनके कृत्यों का कोई भी भारतीय समर्थन नहीं करता। उन्होंने नयी दिल्ली में हाल में हुए एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के 'शर्ट उतारकर' विरोध प्रदर्शन करने और संसद भवन की सीढ़ियों पर 'चाय–पकौड़ा' खाने के लिए गांधी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, ''हम भी विपक्ष में थे और हमने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, लेकिन इसके लिए एक सही मंच होता है।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''संसद लोकतंत्र की पवित्र जगह है। इसकी सीढ़ियों का इस्तेमाल धरने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए और राहुल गांधी वहां 'चाय–पकौड़ा' खा रहे थे। क्या उन्हें पता नहीं कि नाश्ता कहां करना चाहिए?'' इससे पहले शाह ने यहां 675 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) का परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन किया। उन्होंने 'असम कैंसर केयर फाउंडेशन' (एसीसीएफ) के तहत गोलाघाट और तिनसुकिया में निर्मित कैंसर केंद्रों का भी ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया। इनमें से प्रत्येक केंद्र का निर्माण 135 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उन्होंने दीफू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (220 करोड़ रुपए), जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (310 करोड़ रुपए) और बारपेटा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (284 करोड़ रुपए) में सुपर–स्पेशियलिटी अस्पतालों की ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखी। शाह ने गुवाहाटी में 218 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य भवन और 115 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अभयपुरी जिला अस्पताल की भी आधारशिला रखी। शाह असम के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम को यहां पहुंचे थे। पूर्वोत्तर राज्य का चार महीने में उनका यह चौथा दौरा है।

विधायकों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तारी से भाजपा के 'ऑपरेशन लोटस' का भंडाफोड़: शिवकुमार

बेंगलुरु, (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को दावा किया कि यहां स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को रिश्वत की पेशकश करने के मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी से भाजपा के 'ऑपरेशन लोटस' का भंडाफोड़ हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ओडिशा में 'ऑपरेशन लोटस' की योजना बनाई है और 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों से पहले यहां लाए गए प्रत्येक विधायक को पांच करोड़ रुपये की पेशकश की जा रही है। कांग्रेस की ओडिशा इकाई के कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ आठ विधायक भी रिसॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें राज्यसभा चुनावों के दौरान ओडिशा में सत्तारूढ़ भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए विधायकों की खरीद–फरोख्त की आशंकाओं के बीच बेंगलुरु लाया गया है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभाल रहे शिवकुमार ने कहा कि ओडिशा कांग्रेस विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोप में दो लोगों को निजी रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया गया है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, ''चार लोग आए थे। सुरेश नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने उनकी मदद की। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से उनसे (विधायक से) संपर्क किया। सुबह वे हमारे विधायक को ले गए। हमारे विधायक ने हमें बताया कि उन्होंने प्रत्येक वोट के लिए पांच करोड़ रुपये की पेशकश की थी। उन्होंने (कांग्रेस विधायक) कहा कि वे बिकने वाले नहीं हैं।'' शिवकुमार ने कहा कि पकड़े गए लोगों ने स्वीकार किया है कि वे खरीद फरोख्त करने से आए थे। कांग्रेस 'ऑपरेशन लोटस' का इस्तेमाल कमल चुनाव चिह्न का प्रयोग करने वाली भाजपा पर गैर भाजपाई सरकारों को गिराने के लिए या राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कथित तौर पर विधायकों की खरीद–फरोख्त का आरोप लगाने के लिए करती है। कांग्रेस के एक सूत्र के अनुसार, विधायकों की खरीद–फरोख्त में शामिल व्यक्तियों में से एक लोकसभा चुनाव में हार चुका उम्मीदवार है। सूत्र ने कहा, ''उन्होंने कांग्रेस विधायक को एक 'ब्लैंक चेक' की पेशकश करके उनसे सौदेबाजी करने की कोशिश की। दोनों को पकड़ लिया गया है और बिदादी पुलिस के हवाले कर दिया गया है।'' पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, ओडिशा में राज्यसभा चुनाव सोमवार को होंगे। भाजपा ने विधानसभा में अपने संख्याबल के इतर एक और उम्मीदवार मैदान में उतारा है, जिससे विधायकों की खरीद–फरोख्त की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस और बीजू जनता दल (बीजद) ने अपना–अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है।

जीवन को... (पेज एक का शेष) आपको जिस भी क्षेत्र में रूचि हो, थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी लगन, मेहनत और अभ्यास द्वारा उस क्षेत्र में एक मुकाम खड़ा करें कायम करें। जो भी समाजोपयोगी कार्य आपको आत्मिक संतुष्टि दे, धीरे–धीरे क्षमतानुसार करना प्रारम्भ करें जिससे आपको आत्मसुख के साथ साथ बाहर प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इस तरह आपमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में दायरा भी बढ़ेगा तो आप खुद को 'अकेला' महसूस नहीं करेंगे।

अध्ययन या रूचिनुसार पठन सामग्री अवश्य एकत्र रखें। जहां तक हो सके, दिन में तीन या चार घंटे जरूर अध्ययन में व्यतीत करें। इससे शुद्ध स्वस्थ विचार तो आपके बनेंगे ही, सोच का दायरा भी विस्तृत होगा। साथ ही व्यर्थ के अंर्तद्वंद्व से भी सुरक्षित रह सकेंगे।

उक्त बातों पर अमल करेंगे तो अवश्य ही आप कह उठेंगे–मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया।

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication is merely for reference and must not be taken as having the authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent court and forums in Delhi/New Delhi only

Published, Printed, Edited and Owned by Krishna Aggarwal Published from New Delhi, Tel- 011-43560023 E-mail- info@focusnews.co.in, focusnews9@gmail.com
RNI NUMBER - DELBIL/2013/56173, Printed from Vibha Publication Pvt Ltd- D-160 B, Noida Phase - I, Uttar Pradesh - 201301

रास चुनाव : हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को हिमाचल के कुफरी से कसौली स्थानांतरित किया गया

शिमला, (भाषा) हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नजदीक स्थित कुफरी के दो रिजॉर्ट में ठहरे हरियाणा के 31 कांग्रेस विधायकों को राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले रविवार शाम को बारिश और ओलावृष्टि के बीच सोलन जिले के कसौली में स्थानांतरित किया गया। कांग्रेस विधायक भारी सुरक्षा काफिले के साथ तीन छोटी बसों में सवार होकर शाम लगभग 4.20 बजे कुफरी से रवाना हुए। सूत्रों ने बताया कि चंडीगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित कसौली के एक होटल में उनके लिए 40 कमरे बुक किए गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 16 मार्च को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतों की गिनती उसी दिन शाम पांच बजे से शुरू होगी। कांग्रेस ने विधायकों को प्रभावित करने और क्रॉस–वोटिंग को लेकर चिंताओं के बीच शुक्रवार को अपने हरियाणा के विधायकों को शिमला के बाहरी इलाके कुफरी में स्थानांतरित कर दिया था। इन विधायकों और उनके साथ आए लोगों के ठहरने के लिए दो होटल में 37 कमरे बुक किए गए थे। होटल के कर्मचारियों और कांग्रेस नेताओं को ही अंदर जाने की अनुमति थी, जबकि मीडिया को दूर रखा गया था। हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटें खाली होने वाली हैं, क्योंकि भाजपा सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है। इन सीटों के लिए भाजपा के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मैदान में हैं।

पश्चिम एशिया संकट : जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से बात की

नयी दिल्ली, (भाषा) ईरान और अमेरिका–इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्रियों से पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जयशंकर ने शनिवार रात यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से संबंधित घटनाक्रम पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ चर्चा की। जायद अल नाहयान के साथ हुई बातचीत के बारे में जयशंकर ने कहा, ''क्षेत्रीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान–प्रदान किया।'' माना जाता है कि जयशंकर की दोनों विदेश मंत्रियों के साथ हुई बातचीत में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल था। ईरान द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकरे समुद्री परिवहन मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग अवरुद्ध कर दिए जाने के बाद वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है।

हरियाणा के समालखा में आरएसएस के एबीपीएस की तीन दिवसीय बैठक का समापन

समालखा, (भाषा) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) की तीन दिवसीय बैठक रविवार को यहां समाप्त हो गई। इस बैठक में संगठनात्मक कार्यों के विस्तार, राष्ट्रीय हित में "सकारात्मक शक्तियों" की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। बैठक के अंतिम दिन संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि पिछले एक वर्ष में संगठनात्मक गतिविधियों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि 'संघ शाखाओं' की संख्या करीब 6,000 बढ़कर अब 88,000 से अधिक हो गई है। होसबाले ने कहा कि जिन स्थानों पर शाखाएं संचालित होती हैं, उनकी संख्या भी बढ़कर 55,000 से अधिक हो गई है। इसके अलावा 'साप्ताहिक मिलन' और 'मंडलियों' की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। होसबाले ने कहा कि संगठन के विस्तार को अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, लेह और दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में संघ की बढ़ती उपस्थिति के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जहां अब नियमित रूप से शाखाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में नौ द्वीपों से 13,000 से अधिक लोगों ने एक 'हिंदू सम्मेलन' में भाग लिया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। इसी तरह कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 21 'स्वधर्म सम्मेलनों' में 37,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। होसबाले ने कहा कि संघ 'पंच परिवर्तन' की अवधारणा के माध्यम से समाज की "गुणवत्ता" को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय या हिंदू होना केवल एक विचार नहीं, बल्कि "जीवन जीने की एक पद्धति" है। होसबाले ने कहा कि समाज को जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर महान व्यक्तित्वों के योगदान को स्वीकार करना चाहिए। इसी दिशा में संघ के स्वयंसेवकों ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में 2,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें सात लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

सारनाथ का इतिहास सबसे पहले बाबू जगत सिंह द्वारा कराई गई खुदाई के बाद सामने आया था:एएसआई

वाराणसी (उप्र), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह स्वीकार किया है कि सारनाथ का इतिहास सबसे पहले बाबू जगत सिंह द्वारा कराई गई खुदाई के बाद सामने आया था। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एएसआई महानिदेशक वाई. एस. रावत ने कहा कि सारनाथ में सबसे पहले खुदाई का काम जगत सिंह ने कराया था, जिसके कारण इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व का पता चला। रावत ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया कि जगत सिंह के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने एएसआई को साक्ष्यों के दस्तावेज सौंपे थे, जिनसे यह साबित होता है कि इस स्थल पर पहली खुदाई जगत सिंह ने ही कराई थी। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, फलस्वरूप बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत हुई। प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि सारनाथ का इलाका कभी उनके परिवार की ज़मींदारी के अंतर्गत आता था और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि बाबू जगत सिंह ने 1787–88 में वहां खुदाई का काम करवाया था। उन्होंने कहा, ''जगत सिंह ने उस इलाके में कुछ खुदाई का काम कराया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इस स्थल की खोज हुई।'' रावत ने कहा कि सारनाथ परिसर में लगी पट्टिका (शिलालेख) में अब संशोधन कर दिया गया है, जिसमें जगत सिंह की भूमिका को मान्यता देते हुए उनका नाम भी शामिल किया गया है। यह संशोधन हाल में सारनाथ परिसर में लगाई गई नई पट्टिका में देखा जा सकता है। जहां पहले वाली पट्टिका में इस स्थल के पुरातात्विक महत्व की पहली खोज का श्रेय 1798 में ब्रिटिश अधिकारियों को दिया गया था, वहीं नई पट्टिका में यह बताया गया है कि इस स्थल का महत्व 18वीं सदी के आखिर में तब सामने आया, जब काशी के बाबू जगत सिंह ने निर्माण सामग्री के लिए एक प्राचीन टीले की खुदाई कराई थी, फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण पुरावशेषों की खोज हुई। इस तरह, संशोधित शिलालेख इस जगह पर शुरुआती खुदाई के काम में जगत सिंह की भूमिका को मान्यता देता है। साथ ही, वह यह भी बताता है कि कई पुरातत्वविदों ने बाद में खुदाई की, जिसमें तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक के मठ, स्तूप, मंदिर और मूर्तियां मिलीं। वाराणसी के जगतगंज शाही परिवार के प्रतिनिधि और बाबू जगत सिंह के छठी पीढ़ी के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि उनके पूर्वज के ऐतिहासिक योगदान के बारे में शोध और दस्तावेज़ी सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें लंबे समय से चल रही थीं। उन्होंने कहा, ''अब एएसआई ने औपचारिक रूप से यह मान लिया है कि सारनाथ का इतिहास सबसे पहले बाबू जगत सिंह द्वारा कराई गई खुदाई के बाद ही सामने आया था।'' प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि सारनाथ और उसके प्राचीन अवशेषों की खोज अंग्रेजों ने की थी, लेकिन एएसआई की इस मान्यता से यह साफ़ हो गया है कि जगत सिंह ने उनसे पहले ही यह काम कर लिया था। प्रदीप नारायण सिंह के अनुसार एएसआई की यह मान्यता इस बात का भी संकेत है कि ब्रिटिश काल के दौरान बाबू जगत सिंह के योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया था और उन्हें सारनाथ की खोज का सही श्रेय नहीं मिला था।

एलपीजी ला रहे दो भारतीय जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार किया : अधिकारी

नयी दिल्ली, (भाषा) खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे दो भारतीय जहाजों ने शनिवार सुबह युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने वाले भारतीय ध्यज वाले जहाजों की संख्या तीन हो गई है। जहाजरानी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में बचे हुए 22 जहाज प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि भारत सरकार उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एलपीजी ला रहे जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जहाज 92,700 टन एलपीजी ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिवालिक के 16 मार्च को मुंद्रा जबकि नंदा देवी पोत के 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पर पहुंचने की संभावना है। भारतीय ध्वज वाले जहाजों की निकासी भारतीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होने के साथ–साथ ये इस मायने में भी अहम है कि रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। भारत अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से 85–90 प्रतिशत सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से प्राप्त होता है। ये देश तेल और गैस के परिवहन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग करते हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण मार्च के पहले सप्ताह से यह जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद है। सिन्हा ने कहा कि पश्चिमी हिस्से में बचे भारतीय ध्वज वाले 22 जहाजों में से छह एलपीजी पोत हैं, एक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) वाहक है, चार कच्चे तेल के टैंकर हैं, एक रासायनिक उत्पादों की ढुलाई कर रहा है और तीन कंटेनर जहाज हैं और दो 'बल्क कैरियर' हैं।उन्होंने बताया कि बाकी बचे जहाजों में से एक खाली है, जिस पर कोई माल नहीं है जबकि तीन जहाज 'ड्राई डॉक' यानी नियमित रखरखाव के लिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेसवार्ता में कहा, ''हमारे कई जहाज खाड़ी क्षेत्र में प्रतीक्षा में हैं। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर सभी संबंधित देशों के साथ संपर्क और समन्वय बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके लिए सुरक्षित एवं निर्बाध पारगमन सुनिश्चित किया जा सके।''

बिरला ने नेताओं को पत्र लिखकर सदन में बैनर, तख्तियां दिखाने और अन्य व्यवहार पर चिंता व्यक्त की

नयी दिल्ली, (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कुछ सांसदों द्वारा सदन के अंदर बैनर, तख्तियां, पोस्टर दिखाने और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर "गहरी चिंता" व्यक्त की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपने सदस्यों के बीच अनुशासन और उच्च नैतिक आचरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखे पत्र में, बिरला ने कहा कि सदन की हमेशा से गरिमापूर्ण चर्चा और संवाद की गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से, देश के संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और प्रतिष्ठा को कुछ सदस्यों द्वाराकृसदन के भीतर और बाहर, तथा संसद परिसर के भीतरकृकमजोर किया जा रहा है। बिरला ने कहा, "जिस तरह से बैनर, तख्तियां और पोस्टर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और सदन व संसद भवन परिसर के अंदर जिस तरह का आचरण और व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है, वह हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है।" उन्होंने हिंदी में लिखे पत्र में कहा, "हम सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस स्थिति पर गंभीरता से विचार–विमर्श और विश्लेषण करने की आवश्यकता है।" यह पत्र राजनीतिक दलों के नेताओं को ऐसे समय में भेजा गया है, जब लोकसभा में बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया था। बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए विपक्षी दलों ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि वे उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं। बिरला ने पत्र में कहा कि अतीत में जब भी सदन के भीतर आचरण और व्यवहार के मानकों में गिरावट महसूस की गई, तो सभी राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों द्वारा समय–समय पर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा और प्रतिष्ठा के संरक्षण व संवर्धन पर चर्चा और संवाद आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी चर्चा हुई है और प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बिरला ने कहा, "मैंने कई अवसरों परकृचाहे वह कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठकें हों, राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकातें हों या अन्य अवसरकृ आपसे आचरण और व्यवहार के उच्च मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया है।" उन्होंने कहा, "मेरा विनम्र अनुरोध है कि पूरा देश हमारे आचरण और व्यवहार को देखता है और संसद से जाने वाला संदेश देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थानों में गूँजता है।" अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की उच्च गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अब गंभीर चिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का समय आ गया है उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व और सदन में सभी दलों के नेताओं को सदन व संसद भवन परिसर के भीतर अपने सदस्यों के बीच अनुशासन और उच्च नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि हम सभी इस दिशा में सामूहिक प्रयास करें, तो संसदीय लोकतंत्र में जनता का विश्वास निश्चित रूप से और मजबूत होगा तथा सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा में निरंतर वृद्धि होगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस महान संस्था की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने कहा, "लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मैं यह पत्र आपको केवल एक औपचारिक संदेश के रूप में नहीं लिख रहा हूं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी की भावना के साथ लिख रहा हूं।"

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र से अन्य देशों से एलपीजी का आयात करने का आग्रह किया

बेंगलुरु, (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य के कुछ हिस्सों में रसोई गैस की किल्लत को दूर करने के लिए अन्य देशों से एलपीजी आयात सहित वैकल्पिक उपायों पर विचार करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने विधानमंडल में इस मुद्दे पर पहले ही जवाब दे दिया है और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से भी इस मामले पर बात की है। सिद्धरमैया ने कहा, "सरकार विधानसभा और विधान परिषद दोनों में दो बार पहले ही जवाब दे चुकी है। मैंने भी एक पत्र लिखा है। इस किल्लत के संबंध में मैंने कहा है कि इससे बचने के लिए अन्य देशों से एलपीजी मंगाने जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं अब भी केंद्र सरकार से आग्रह कर रहा हूं।" उन्होंने बताया कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा भोजन के लिए होटलों पर निर्भर है और चेतावनी दी कि एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान से दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, "बहुत से लोग खाने के लिए होटलों पर निर्भर हैं। अगर होटल बंद हो गए तो इससे बहुत परेशानी होगी और पूरा जनजीवन अस्त–व्यस्त हो जाएगा।" मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। भाजपा की राज्य इकाई के नेताओं द्वारा अन्य राज्यों में एलपीजी की किल्लत की शिकायत न किए जाने संबंधी टिप्पणी का जवाब देते हुए सिद्धरमैया ने कहा, "तो उन्हें ही आपूर्ति करने दीजिए। शायद वे कर्नाटक के प्रति सौतेला रवैया अपना रहे हैं। उन्हें ही कर्नाटक को आपूर्ति करने दीजिए। हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे?"

हरियाणा में 2025 तक 35 प्रतिशत पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया

चंडीगढ़, (भाषा) हरियाणा की कुल ग्राम पंचायतों में से लगभग 35 प्रतिशत पंचायतें 2025 में सत्यापन के बाद टीबी–मुक्त घोषित किए जाने के योग्य पाई गई हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने रविवार को दी। मिश्रा ने बताया कि टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है और कुल 6,237 पंचायतों में से 2,157 पंचायतें टीबी–मुक्त घोषित होने के योग्य पाई गई हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर 24 मार्च 2023 को वाराणसी में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को टीबी से जुड़ी समस्याओं को समझने, समाधान के लिए कदम उठाने और पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना है। आधिकारिक बयान के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में टीबी मुक्त अभियान के तहत टीबी–मुक्त पंचायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो जमीनी स्तर पर कार्यक्रम की बढ़ती गति को दर्शाती है। वर्ष 2023 में राज्य में 574 पंचायतों को प्रमाणन मिला था, जो सभी 'ब्रॉन्ज' श्रेणी में थीं और कुल पंचायतों का लगभग नौ प्रतिशत थीं। वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,855 हो गई, जिसमें 1,542 ब्रॉन्ज और 313 सिल्वर श्रेणी की पंचायतें शामिल थीं, जो राज्य की लगभग 30 प्रतिशत पंचायतों को शामिल करती हैं। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 2,157 पंचायतों तक पहुंच गई है, जो कुल पंचायतों का 35 प्रतिशत है। मिश्रा ने बताया कि इस पहल में तीन–स्तरीय प्रमाणन प्रणाली अपनाई गई है। पहली बार टीबी–मुक्त रहने वाली पंचायतों को ब्रॉन्ज, लगातार दो वर्ष तक स्थिति बनाए रखने पर सिल्वर और तीन वर्षों तक इसे बनाए रखने पर गोल्ड प्रमाणन दिया जाता है। प्रमाणपत्र हर साल विश्व तपेदिक दिवस पर जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए जाते हैं और उनकी वैधता एक वर्ष होती है। वर्ष 2025 में पात्र पाई गई 2,157 पंचायतों में से 211 को गोल्ड, 646 को सिल्वर और 1,300 को ब्रॉन्ज श्रेणी के लिए योग्य पाया गया है।

शस्य श्यामला धरा का आधार हैं सदानीरा सरिताएं

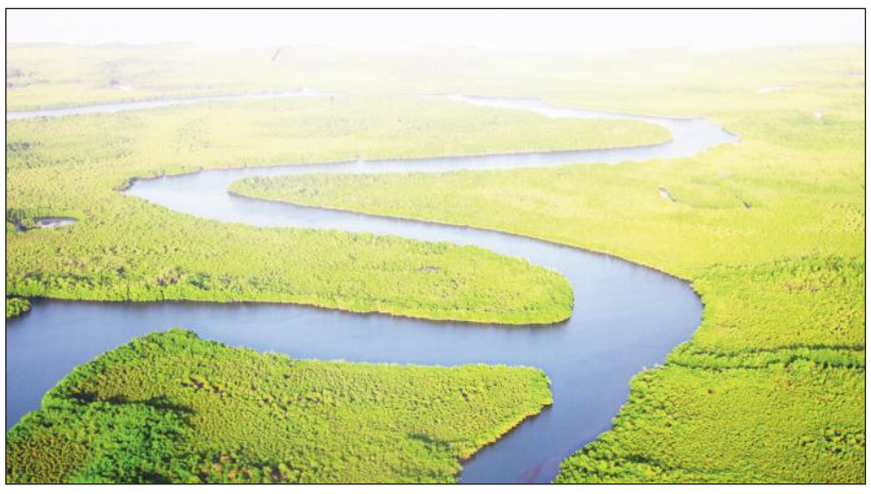

नदियां युगों–युगों से पृथ्वी पर बह रही हैं। धरती पर सुंदर चित्र रचती नदियां आनंद का उत्सव हैं। जीवन में प्राणों का संचार करती नदियों की कल–कल मनोहर ध्वनि अशांत चित्त और अधीर मन को शांति और धैर्य की समिधा प्रदान करती हैं। नदियां धरा की जीवन रेखाएं हैं, जो सुधा सम निर्मल शीतल जल से मानव तन–मन को संतृप्ति दे सुख का प्रसाद वितरित करती हैं। धरती की खुशहाली और बहुरंगी जीवन शुभ सरिताओं की देन है। निश्चित रूप से लोक जीवन में नदियों का महत्व एवं उपयोगिता निर्विवाद सर्वस्वीकार्य है। नदियां न केवल मनुष्यों के लिए अपितु पशु–पक्षियों एवं पेड़–पौधों के पोषण एवं विकास के लिए आवश्यक है। समस्त प्राणिजगत का जीवन यापन धरती पर निर्भर है और धरती की हरीतिमा नदियों पर आश्रित हैं। यदि नदियां न हों तो जल बिना धरती की तरलता छिन जाएगी, उर्वरता का ह्रास होगा, न जंगल बचेंगे और न ही जीवन। तब शुष्क बंजर धरा अनुपयोगी और निरर्थक हो जाएगी। धरती को स्वस्थ, सुवासित, सुफला और समृद्ध बनाती हैं नदियां। कह सकते हैं नदियां वसुधा का श्रृंगार हैं। सदानीरा सरिताएं धरती की देह को जल से तृप्त कर जीवों के लिए फसलों का उपहार भेंट करती हैं। वस्तुतः नदियां पृथ्वी की धमनियां हैं। सतत प्रवहमान नदियां लोकजीवन में खुशियां, उपलब्धियां और समृद्धि का द्वार खोलती हैं। नदियों का संरक्षण अत्यावश्यक है ताकि धरती पर जीवन नर्तन करता रहे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का आयोजन कर जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। किसी देश के निवासियों की सोच, दृष्टि और भावी योजना को समझना हो तो वहां की नदियों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। नदियों का स्वस्थ और सदा जल प्रवाही होना संकेत करता है कि वहां का लोक जीवन का नदियों से आत्मीय एवं मधुर सम्बन्ध है, और वह समाज भविष्य के लिए स्वस्थ नदियों को धरोहर के रूप में भावी पीढ़ियों को सौंपने की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य से परिचित हैं। और यदि किसी देश की नदियां प्रदूषित हैं, नगरीय सीवेज तथा औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट संवहन का माध्यम बन अपना नैसर्गिक रूप खोकर गंदा नाला बनती जा रही हैं, तो कहा जा सकता है कि वहां का समाज जल के महत्व से अनभिज्ञ, आत्मकेंद्रित और निरा स्वार्थी है जो भोगवादी भावभूमि पर भावी संकट से अनजान केवल वर्तमान जी रहा है। अगर वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो हमें उक्त दोनों प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं।अपवाद स्वरूप कुछेक नदियों को छोड़ आज दुनिया भर की नदियां संकट में हैं। न केवल अनियोजित खनन, तटबंधों एवं प्रवाह मार्ग पर अवैध कब्जे एवं निर्माण, धार्मिक गतिविधियों से उपजे कूड़े का बिखराव अपितु विनाशकारी बड़े बांधों के निर्माण से नदियां का सहज जीवन बाधित हुआ है। दैनंदिन कार्य–व्यवहार से उपजा कूड़ा–करकट, उद्योगों का अपशिष्ट, अस्पतालों के रोगियों की प्रयुक्त प्लास्टर, पट्टी–रुई, इंजेक्शन आदि सामग्री और नगरों के बिना शोधित सीवेज का लगातार नदियों में गिरना तथा मानव द्वारा नदियों की अनदेखी के चलते नदियां आसन्नमरण हैं। नदियों की सांसें थम रही हैं, हर वर्ष कहीं न कहीं कोई नदी अपना स्वरूप खो नाले में बदल मर रही है। हम देखते–सुनते भी अनजान बने हुए जीये जा रहे हैं। नदियां स्वस्थ हों, हंसे–मुसकुरायें, धरती पर उनका मोहक कलरव संगीत गूंजता रहे, जल–जीवों की अठखेलियां नवल चित्र रचती रहें, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। नदी कार्रवाई दिवस मनाने का उद्देश्य आमजन को नदियों के महत्व एवं संरक्षण, प्रदूषण से नदियों को बचाने, नदी जल परियोजना के हानिकारक बड़े बांधों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, पशु–पक्षियों एवं मानव को मीठे जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रत्येक व्यक्ति को नदी–प्रेमी बनाने हेतु प्रयास करना है। बड़े बांधों से होने वाले नुकसानों, पारिस्थितिकी तंत्र की हानि एवं खाद्य श्रंखला टूटने, नदियों के सतत प्रवाह बाधित होने से लोकजीवन में पड़ने वाले असर से बचाने हेतु दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधियों ने 1997 में ब्राजील में बैठक कर नदियों के संरक्षण हेतु कार्रवाई करने पर बल दिया तथा प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नदी कार्रवाई दिवस मनाकर जन जागरण करने का संकल्प लिया। तब 14 मार्च, 1998 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला आयोजन किया गया। वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में इस अवसर पर थीम आधारित छोटे–बड़े हजारों आयोजन करके नदियों को बचाने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी के साथ कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025 में थीम थी – हमारी नदियां, हमारा भविष्य, जबकि 2026 में आयोजन हेतु 'नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें' केंद्रीय विषय चुना गया है, जो न केवल प्रासंगिक और समीचीन बल्कि नदियों के संरक्षण, शुचिता एवं सतत प्रवाह को बनाये रखने के लिए प्रेरित करने वाला भी है। उल्लेखनीय है कि नदियां मीठे जल का प्राकृतिक स्रोत है जो धरती पर उपलब्ध कुल जल का 1 प्रतिशत है। नदियां हिमनदों, पहाड़ों और बड़ी झीलों से निकल सागरों में मिलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद ग्लेसियर अधिक पिघल कर लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं जो भयावह संकट का संकेतक है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म एवं विकास नदियों के किनारों पर हुआ। नदियों ने झीलों, घाटियों, उपत्यकाओं एवं आर्द्रभूमियों का निर्माण किया। धरती के फेफड़े जंगलों को विकसित किया। सर्वाधिक नदियों वाली भूमि बांग्लादेश में नारा दिया जाता है– नदियों को बचाओ, देश को बचाओ, जो उनके नदी प्रेम का परिचायक है। भारत नदियों से समृद्ध है, यहां नदियां वंदनीय एवं पूजनीय हैं। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित गंगा को मातृवत सम्मान दिया जाता है। देश की सभी नदियां पश्चिम से पूर्व को प्रवाहित हो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम को बहते हुए अरब सागर में मिलती हैं। गण्डक नदी में भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम और केन नदी, बांदा में शजर पत्थर पाये जाते हैं। शजर पत्थरों के अंदर पशु–पक्षियों एवं वृक्षों की आकृतियां उभरी होती हैं। नदियों के तटों पर मेलों का आयोजन होता है। नदियों को साफ–स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे, नदी उत्सव और स्वच्छ भारत अभियान संचालित हैं। नदी कार्रवाई दिवस के अवसर पर जागरूकता हेतु हम नदियों पर आधारित लघु वृत्तचित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यालयों में वाद–विवाद, भाषण, एकांकी, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। नदी तटों पर सम्मान समारोह आयोजित कर नदियों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित कर प्रेरक वातावरण बना सकते हैं। मुझे लगता है, नदियों की खुशहाली के लिए युवाओं की सहभागिता आवश्यक है। विविध कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण करते हुए हम नदियों को जीवन दें क्योंकि नदियों से हम और हमारी दुनिया बचेगी।**प्रमोद दीक्षित मलय**

मयंक चक्रवर्ती ने इतिहास रचा, पूर्वोत्तर से पहले और भारत के 94वें ग्रैंडमास्टर बने

नयी दिल्ली, (भाषा) प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मयंक चक्रवर्ती ने अपने उभरते करियर की आखिरी बाधा पार करते हुए अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल कर लिया, जिससे वह भारत के 94वें ग्रैंडमास्टर बन गए। वह के पूर्वोत्तर से यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। असम के गुवाहाटी के रहने वाले 17 वर्षीय चक्रवर्ती 2024 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। उन्होंने 'होटल स्टॉकहोम नॉर्थ बाय फर्स्ट होटल्स चेस टैलेंट्स टूर्नामेंट' के आठवें दौर में एक दौर बाकी रहते ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने इस दौर में स्वीडिश आईएम फिलिप लिंडग्रेन को हराया। लिंडग्रेन पर जीत के दौरान चक्रवर्ती अपने खेल के चरम पर थे। उन्होंने जरूरी 6.5 अंक जुटाए जो उनका अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉर्म पक्का करने के लिए काफी थे। आखिरी दौर में उन्होंने इंग्लिश इंटरनेशनल मास्टर जोना बी विलो के साथ एक रोमांचक ड्रॉ खेला और इस तरह अपने अब तक के सबसे यादगार प्रदर्शन पर मुहर लगा दी। इस प्रक्रिया में चक्रवर्ती ने 2500 ईएलको रेटिंग का अहम आंकड़ा भी पार कर लिया। उनकी मौजूदा रेटिंग इस सीमा से कुछ अंक ऊपर है जिससे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) के नियमों के अनुसार उनका ग्रैंडमास्टर खिताब पक्का हो गया है। चक्रवर्ती ने इस दौरान एक बाजी गंवाई, दो ड्रॉ खेले और बाकी छह बाजियां जीती। इस तरह उन्होंने कुल नौ में से सात अंक हासिल किए। साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने नॉर्वे के एक्सेल बू क्वालॉय पर आधे अंक की बढ़त बनाई जिन्हें आखिरी दौर में वॉकओवर मिला था। चक्रवर्ती 2024 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे और अपने आयु वर्ग के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं। अंडर–11 वर्ग में भारत और एशिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी चक्रवर्ती के लिए 2021 का सत्र बेहद शानदार रहा। उस साल उन्होंने यूरोप में कई टूर्नामेंट खेले जिससे उनकी ईएलओ रेटिंग 1800 से बढ़कर 2200 के करीब पहुंच गई। साथ ही वह 2009 या उसके बाद जन्में खिलाड़ियों की ईएलओ रैंकिंग में दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी बन गए। उनकी असाधारण प्रतिभा की बदौलत वह अंडर–9 वर्ग में राष्ट्रीय रजत पदक और अंडर–11 वर्ग में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका में आयोजित एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर–10 वर्ग का रजत पदक भी जीता था। उनकी सफलता में उनके परिवार की अहम भूमिका रही है जिसमें उनकी डॉक्टर मां उनके लिए स्तंभ बनीं जबकि उनके पिता ने टूर्नामेंट के दौरान उनके साथ सफर करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी।

भारत की अंडर–17 महिला टीम ने म्यांमा के खिलाफ मैत्री मैच में जीत हासिल की

यांगून, (भाषा) भारतीय अंडर–17 महिला फुटबॉल टीम ने शनिवार को यहां थुवुन्ना स्टेडियम में खेले गए दूसरे अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच म्यांमा को 3–2 से हराकर शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। पहले हाफ के अंत तक मेजबान टीम 2–1 से आगे थी जिसमें हनिन विंट वार क्याव (12वें मिनट) और मिन हटोन मे जितार (45वें मिनट) ने गोल किए। भारतीय टीम के लिए अल्वा देवी सेनजम (33वें मिनट) ने बराबरी गोल किया। फिर दूसरे हाफ के आखिर में भारत की स्थानापन्न खिलाड़ी अनुष्का कुमारी (88वें मिनट) और जोया (90+1वें मिनट) ने गोल करके जीत पूरी की। यह मैच भारत की आगामी एएफसी अंडर–17 महिला एशियाई कप की तैयारियों का हिस्सा था जो एक से 17 मई तक चीन के सूजौ में होगा। म्यांमा ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है और अपनी तैयारियों के तौर पर ये मैच खेल रहा है। भारत ने इससे पहले बृहस्पतिवार को पहले मैत्री मैच 2–0 से जीत दर्ज की थी।

दीक्षा ऑस्ट्रेलियाई ओपन में संयुक्त 39वें स्थान पर खिसकी

एडीलेड, (भाषा) भारतीय महिला गोल्फर दीक्षा डागर ने लगातार दूसरी बार 74 का कार्ड खेला जिससे शनिवार को यहां महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन में संयुक्त रूप से 39वें स्थान पर खिसक गईं जबकि अवनि प्रशांत ने लगातार दूसरी बार 72 का कार्ड खेला जिससे वह संयुक्त रूप से 47वें स्थान पर रहीं। वाणी कपूर 80 का कार्ड खेलकर पिछड़ गईं और संयुक्त रूप से 63वें स्थान पर रहीं। अभी टूर्नामेंट का अंतिम दौर बाकी है। हन्ना ग्रीन ने एक शॉट की बढ़त बनाई हुई है और वह अपनी घरेलू जमीन पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने की कोशिश में हैं। सात बार की एलपीजीए विजेता ने तीसरे दौर में 68 का कार्ड बनाया जिससे उन्होंने पिछले दौर में शीर्ष पर चल रही सेलीन हर्बिन को पीछे छोड़ दिया।

सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप : पीएसपीबी, आरएसपीबी की दमदार शुरुआत

इंदौर, (भाषा) टेबल टेनिस की दो दिग्गज टीमों पीएसपीबी और आरएसपीबी ने शनिवार को यहां 87वीं यूटीटी सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ कर नॉकआउट चरण में पहुंचने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए। पुरुष वर्ग में पीएसपीबी ने ग्रुप ए में आंध्र प्रदेश और पंजाब को 3–0 के हराकर शुरुआती बढ़त बना ली। इसके बाद आरएसपीबी ने ग्रुप बी में अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने पहले राजस्थान को 3–1 से हराया और फिर गुजरात को 3–0 से मात दी। ग्रुप सी में पश्चिम बंगाल ने भी शानदार शुरुआत करते हुए उत्तराखंड और ओडिशा को लगातार 3–1 के अंतर से हराया। वहीं ग्रुप डी में तेलंगाना ने छत्तीसगढ़ को 3–0 और मध्य प्रदेश को 3–1 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला ग्रुप ई में देखने को मिला जिसमें दिल्ली ने एक कड़े मुकाबले में महाराष्ट्र को 3–2 से हराया। ग्रुप एफ में मिजोरम और असम ने सभी मुकाबले जीतकर अपना दबदबा बनाया जबकि ग्रुप जी में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने 3–0 के शानदार नतीजों के साथ आसानी से अगले दौर में जगह बनाई। ग्रुप एच में हरियाणा और कर्नाटक ने भी शानदार जीत के साथ अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की।महिला टीम स्पर्धा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां मजबूत टीमों ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा।

वर्तमान की 21 अंक वाली प्रणाली अच्छी, प्रारूप में बदलाव पर सतर्कता बरतनी चाहिए: साइना नेहवाल

नयी दिल्ली, ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) से स्कोरिंग में प्रस्तावित बदलाव पर सतर्कता बरतने का आग्रह किया है और उनका मानना है कि वर्तमान की 21 अंक की प्रणाली खेल की गति और दमखम बनाए रखती है। बैडमिंटन की विश्व में सर्वोच्च संस्था बीडब्ल्यूएफ ने वर्तमान तीन गेम वाली 21 अंक की प्रणाली को तीन गेम की 15 अंक वाली प्रणाली में बदलने का प्रस्ताव किया है। इस बदलाव पर सदस्य 25 अप्रैल को डेनमार्क के होर्सेंस में बीडब्ल्यूएफ की वार्षिक आम बैठक में मतदान करेंगे। साइना ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा, ''बैडमिंटन की परंपरा समृद्ध है तथा ऑल इंग्लैंड ओपन और बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की गति और सहनशक्ति की परीक्षा होती है।'' उन्होंने कहा, ''स्कोरिंग या प्रारूप में किसी भी तरह के बदलाव पर सतर्कता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान की 21 अंक वाली प्रणाली अच्छा काम कर रही है और खिलाड़ी इससे अच्छी तरह तालमेल बिठा चुके हैं।'' साइना ने कहा, ''यदि कुछ बदलाव किए भी जाते हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रैलियों की गुणवत्ता और खेल के प्रतिस्पर्धी संतुलन पर कोई असर न पड़े। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और खेल भावना पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए।'' बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर के लिए प्रस्तावित नए प्रारूप के अनुसार एशिया और यूरोप में होने वाले पांच सुपर 1000 टूर्नामेंटों में एकल वर्ग में एक नया प्रारूप लागू किया जाएगा, जिसमें 48 खिलाड़ी ग्रुप चरण में प्रतिस्पर्धा करेंगे और उसके बाद नॉकआउट राउंड होंगे। युगल स्पर्धाओं में 32 जोड़ियों के नॉकआउट ड्रॉ होंगे। प्रत्येक सुपर 1000 टूर्नामेंट 11 दिन तक चलेगा। साइना का मानना है कि बीडब्ल्यूएफ को खिलाड़ियों के कल्याण को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उनका मानना है कि व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के कारण आराम के लिए बहुत कम समय बचता है और इससे खिलाड़ियों के चोटिल होने और उन पर थकान हावी होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा, ''बैडमिंटन शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से मुश्किल खेल रहा है। इसमें लंबी रैलियां होती हैं और खिलाड़ी लगभग प्रत्येक सप्ताह टूर्नामेंट में खेलते हैं। बीडब्ल्यूएफ ने कैलेंडर को व्यवस्थित करने की कोशिश की है लेकिन एक खिलाड़ी के लिए रिकवरी का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। चोटें और थकान प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं और करियर को भी छोटा कर सकती हैं।'' साइना ने लक्ष्य सेन की अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए सराहना की जो पिछले सप्ताह ऑल इंग्लैंड ओपन में पुरुष एकल में उपविजेता रहे थे। यह दूसरा मौका था जबकि लक्ष्य सेन इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने कहा, ''ऑल इंग्लैंड ओपन जैसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में दो बार जगह बनाना बड़ी उपलब्धि है। यह शुरू से बैडमिंटन का प्रमुख टूर्नामेंट रहा है और वहां प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा होता है।'' साइना ने कहा, ''इससे लक्ष्य के खेल में निरंतरता का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फाइनल तक पहुंचने का मतलब है कि कोई भी खिलाड़ी खिताब से अब ज्यादा दूर नहीं है।'' हैदराबाद की यह 35 वर्षीय खिलाड़ी युवा भारतीय शटलरों के प्रदर्शन से भी प्रभावित हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शारीरिक शक्ति, मैच के दौरान धैर्य और रणनीतिक जागरूकता निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। साइना ने कहा, ''शीर्ष स्तर पर निरंतरता बनाए रखने के लिए कई वर्षों तक फिटनेस, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता बनाए रखना जरूरी होता है। खिलाड़ियों को पूरे सत्र में अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। युवा खिलाड़ियों को अपने दमखम, मैच को लेकर धैर्य और रणनीति बनाने में माहिर होना चाहिए।''

श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट को जाने देना केकेआर का गलत फैसला: अनिल कुंबले

मुंबई, (भाषा) महान क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 2024 में खिताब जीतने के बाद श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट को जाने देकर गलत फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब तक तीन बार की आईपीएल चैंपियन टीम अहम खिलाड़ियों को अपने पास बनाए रखने की अहमियत नहीं समझेगी तब तक उसे खिताब का गंभीर दावेदार नहीं माना जा सकता। अय्यर केकेआर छोड़कर पंजाब किंग्स में शामिल हो गए जिसकी कप्तानी करते हुए उन्होंने पिछले सत्र में करीब एक दशक बाद टीम को पहली बार आईपीएल फाइनल में पहुंचाया। वहीं 2024 में केकेआर की सफलता का अहम हिस्सा रहे फिल सॉल्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) चले गए जहां उन्होंने पिछले साल फ्रेंचाइजी को पहली बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। कुंबले ने 'जियो हॉटस्टार' की एक विज्ञप्ति में कहा, ''दो साल पहले केकेआर ने आईपीएल जीता था और अपनी तीसरी ट्रॉफी उठाई थी। उस जीत के दो अहम खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट थे। दोनों ने टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई लेकिन केकेआर ने दोनों को जाने दिया। '' उन्होंने कहा, ''खिलाड़ियों को अपने साथ रखने के मामले में उनमें कोई निरंतरता नहीं है। केकेआर ने श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट को जाने देकर गलत फैसला किया और इस वजह से अब उनके पास आईपीएल जीतने वाला कोई कप्तान नहीं है। '' कुंबले ने कहा कि भले ही केकेआर के पास कप्तान के तौर पर अजिंक्य रहाणे जैसा अनुभवी खिलाड़ी है लेकिन उन्होंने अभी तक कप्तान के तौर पर आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। कुंबले ने कहा, ''अजिंक्य रहाणे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मुंबई और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है। लेकिन उन्होंने अभी तक कप्तान के तौर पर आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। '' इस दिग्गज स्पिनर ने आगे कहा, ''ऐसा कप्तान होना जिसने ट्रॉफी जीती हो, आपको फायदा देता है। उन्हें यह सीखना होगा कि अपने अहम खिलाड़ियों को अपने पास कैसे बनाए रखा जाए। वर्ना वे संघर्ष करते रहेंगे और उन्हें ट्रॉफी जीतने का दावेदार नहीं माना जा सकता। '' भारत के पूर्व कप्तान ने पिछले साल पंजाब किंग्स को आईपीएल फाइनल तक पहुंचाने के लिए अय्यर के नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ''श्रेयस अय्यर निश्चित रूप से कप्तान के तौर पर कम आंके गए हैं। एक फ्रेंचाइजी के साथ ट्रॉफी जीतना और फिर दूसरी फ्रेंचाइजी में जाना आसान नहीं होता। वहां का प्रबंधन, माहौल और टीम सब अलग होते हैं। वहां का दबाव भी अलग होता है। '' कुंबले ने कहा, ''जिस नयी फ्रेंचाइजी में वह शामिल हुआ था, उसने पिछले 10 साल में फाइनल नहीं खेला था और पंजाब किंग्स के साथ अपने पहले ही सत्र में उसने उन्हें फाइनल तक पहुंचा दिया। मैं न सिर्फ उसकी कप्तानी से प्रभावित हुआ, बल्कि जिस तरह से उसने टीम का नेतृत्व किया, उससे भी प्रभावित हुआ। '' उन्होंने कहा, ''कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ता है। श्रेयस भी वैसा ही है। अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी, उस पर सवाल उठते रहते हैं। मुझे लगता है कि उसे कम आंका जाता है, लेकिन वह एक असाधारण नेतृत्वकर्ता है। ''

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर के तौर पर काम नहीं कर पाऊंगा : पीटरसन

नयी दिल्ली, पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स में मेंटोर की भूमिका निभाने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग के आने वाले सत्र में यह भूमिका नहीं निभा पाएंगे। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च को हो रही है और गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा। पीटरसन ने 'एक्स' कहा, ''मैं इस आईपीएल सत्र में दिल्ली कैपिटल्स का मेंटोर नहीं बन सकता। मैं इस काम के लिए जरूरी समय नहीं दे सकता। इस सत्र के लिए सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। '' उन्होंने कहा, ''हालांकि मैं आपको कमेंट्री बॉक्स में फिर मिलूंगा। आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है और मैं आप सभी से जल्द मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। '' दिल्ली कैपिटल्स अपने आईपीएल 2026 सत्र की शुरुआत एक अप्रैल को लखनऊ में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से करेगा। दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान पर पहला मैच चार अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा। पीटरसन पांच आईपीएल सत्र में तीन टीम के लिए खेले हैं और 2025 सत्र की शुरुआत से पहले उन्हें दिल्ली कैपिटल्स का मेंटोर नियुक्त किया गया था। पीटरसन ने आईपीएल में 17 मैचों में कप्तानी भी की है। उन्होंने आईपीएल 2009 में कुछ समय के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी की थी जिसके बाद 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी की। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक आईपीएल का खिताब कभी नहीं जीता है।

चीन ने ताइवान को 2–0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

पर्थ। मौजूदा चैंपियन चीन ने ताइवान को 2–0 से हराकर 2027 विश्व कप में अपनी जगह पक्की करने के साथ महिला एशियाई कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया जिसमें उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। चीन और ताइवान के बीच भू–राजनीतिक तनाव है और दोनों के बीच 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ। इसके बाद अतिरिक्त समय के तीसरे ही मिनट में शाओ जिकिन ने गोल करके मैच का पहला गोल किया और फिर आखिर में एक आत्मघाती गोल से चीन का दूसरा गोल हुआ। वहीं शुक्रवार को हुए मुकाबले में सैम केर ने एक गोल किया और एक गोल में मदद की जिससे ऑस्ट्रेलिया ने उत्तर कोरिया को 2–1 से हराकर विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली।

धोनी का आईपीएल में यह अंतिम सत्र हो सकता है: इरफान पठान

नयी दिल्ली, भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की तरफ से एक खिलाड़ी के रूप में यह अंतिम सत्र हो सकता है। जैसे–जैसे 2026 का आईपीएल करीब आ रहा है, धोनी के संन्यास को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को लेकर अपनी टीम से जुड़ा है जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि धोनी इस बार खेल के मैदान पर कम दिखेंगे और वह मेंटोर (मार्गदर्शक) की भूमिका निभा सकते हैं। इरफान ने जिओ हॉटस्टार से कहा, ''धोनी के बिना सीएसके की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हो सकता है कि इस सत्र में हम उन्हें आखिरी बार पीली जर्सी में देखें। लेकिन उनके बिना सीएसके और आईपीएल की कल्पना करना मुश्किल है।'' उन्होंने कहा, ''आईपीएल शुरू होने के साथ ही हम धोनी को फिर से खेलते हुए देखने लगते हैं। इसका मतलब है कि वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वह काफी फिट भी दिख रहे हैं।'' यह 44 वर्षीय खिलाड़ी इस महीने की शुरुआत में चेन्नई में सीएसके शिविर में शामिल हो चुका है और कप्तान रितुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम के साथ अभ्यास कर रहा है। पठान ने कहा कि धोनी की भूमिका टीम का मार्गदर्शन करने और अगली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने की हो सकती है। उन्होंने कहा, ''इस सत्र में धोनी सबको एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे नहीं पता कि वो कितने मैच खेलेंगे। लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी से काफी मदद मिलेगी।'' पठान ने कहा, ''इससे संजू को फायदा होगा क्योंकि वह भी नेतृत्व समूह का हिस्सा होंगे। रितुराज गायकवाड़ कप्तान हैं। लेकिन इसके लिए दो या तीन खिलाड़ियों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यहीं पर धोनी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि वह कुछ अंतर पैदा करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''उनकी फिटनेस, बल्लेबाजी क्रम और क्या वे सभी मैच खेलेंगे, जैसे सवाल अब भी उठते रहेंगे। सीएसके का टीम प्रबंधन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। वे निश्चित रूप से छठी आईपीएल ट्रॉफी जीतकर उन्हें शानदार विदाई देने की कोशिश करेंगे।'' धोनी ने आईपीएल में अब तक 278 मैच खेले हैं और 5,439 रन बनाए हैं। पिछले सत्र में उन्हें केवल डेथ ओवरों में ही बल्लेबाजी करते हुए देखा गया था। उन्होंने तब 13 पारियों में 196 रन बनाए थे। सीएसके ने रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स को देकर उनकी जगह संजू सैमसन को अपनी टीम से जोड़ा था। राजस्थान रॉयल्स की टीम में जोस बटलर भी नहीं हैं। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बांगड़ का मानना है कि दो स्थापित बल्लेबाजों के जाने के बाद राजस्थान के युवा खिलाड़ियों को अब जिम्मेदारी संभालनी होगी। बांगड़ ने कहा, ''पहले उन्होंने जोस बटलर को जाने दिया और अब संजू सैमसन भी टीम में नहीं हैं। टीम के युवा बल्लेबाजों को ही अब आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालनी होगी।'' भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज अभिनव मुकुंद ने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना चुनौती होगी और इसके अलावा उसके कप्तान पैट कमिंस की उपलब्धता को लेकर भी संशय बना हुआ है। उन्होंने कहा, ''सनराइजर्स हैदराबाद को शुरू में कुछ मुश्किल मैच खेलने होंगे। यह कहना मुश्किल है कि पैट कमिंस पूरी तरह से खेलने के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए इसका इंतजार करना होगा क्योंकि वह टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं।''सनराइजर्स अपना पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद उसका सामना दो अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और पांच अप्रैल को लखनऊ सुपर जॉइंट्स से होगा।

नमन पुरस्कार समारोह में टी20 विश्व कप विजेता टीम को सम्मानित करेगा बीसीसीआई

मुंबई, (भाषा) भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) रविवार को यहां होने वाले अपने वार्षिक नमन पुरस्कार समारोह के दौरान टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को सम्मानित करेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को घोषणा की कि बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का मुख्य आकर्षण हाल के समय में आईसीसी खिताब जीतने वाली सभी पांच भारतीय टीमों को सम्मानित करना होगा। गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम आठ मार्च को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीन बार टी20 विश्व कप जीतने ओर खिताब का बचाव करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। यही नहीं वह घरेलू मैदान पर टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है। इस समारोह में उन अन्य भारतीय टीमों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने हाल के दिनों में आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं। इनमें 2025 में वनडे विश्व कप जीतने वाली सीनियर महिला टीम, 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पुरुष टीम, 2026 में अंडर–19 विश्व कप जीतने वाली टीम और 2025 में अंडर–19 टी20 विश्व कप जीतने वाली महिला टीम शामिल हैं। बीसीसीआई ने इसके साथ ही कुछ व्यक्तिगत पुरस्कारों की भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की, जिनके बारे में इस सप्ताह की शुरुआत में पहले ही पता चल गया था। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को 2024–25 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष) का पॉली उमरीगर पुरस्कार मिलेगा, जबकि स्मृति मंधाना को अपने करियर में पांचवीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) के रूप में सम्मानित किया जाएगा। पूर्व दिग्गज रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को बोर्ड का सर्वोच्च सम्मान कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को बीसीसीआई का महिला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। बिन्नी भारत की 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य और टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने बाद में कोच, चयनकर्ता और 2022 से 2025 तक बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में खेल की सेवा की। द्रविड़ के नाम पर 24,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं।

एलपीजी संकटः दिल्ली के भोजनालयों का मेन्यू हुआ छोटा, बड़ी बुकिंग और कॉरपोरेट समारोह स्थगित

नयी दिल्ली, (भाषा) पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष बढ़ने के बाद गहराए एलपीजी संकट के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तराओं में अब बड़े कॉरपोरेट समारोहों और सामूहिक पार्टियों का आयोजन कम हो गया है। इतना ही नहीं एलपीजी आपूर्ति संकट के कारण रेस्तरां अपने मेन्यू और बुकिंग में कटौती भी कर रहे हैं। कनॉट प्लेस के रेस्तरां मालिकों का कहना है कि बड़े समारोहों के लिए खाना बनाने में काफी गैस की खपत होती है, जिसकी वजह से कई प्रतिष्ठानों ने अस्थायी रूप से बड़ी पार्टियों की बुकिंग रोक दी है और नियमित ग्राहकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। कनॉट प्लेस, शहर के उन सबसे व्यस्त स्थानों में शामिल हैं, जहां बड़े से लेकर सभी प्रकार के भोजनालय हैं। 'फ्लेवर्स ऑफ चाइना' नाम के रेस्तरां की मालिक परमजीत कौर ने बताया कि एलपीजी की खपत को नियंत्रित करने के लिए रेस्तरां ने कुछ व्यंजनों में कटौती की है और सामूहिक बुकिंग सीमित कर दी है। उन्होंने कहा, "हमें स्थिति से निपटने के लिए कुछ बदलाव करने पड़े हैं। उदाहरण के लिए, हम फिलहाल 'सिजलर' नहीं परोस रहे हैं क्योंकि इसके लिए लगातार और तेज आंच की आवश्यकता होती है। हमने अपने मेन्यू में भी कटौती की है और केवल उन बुनियादी व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें कम गैस खपत के साथ तैयार किया जा सकता है।" कौर ने बताया कि ईंधन बचाने के लिए रेस्तरां ने अस्थायी रूप से बड़े आयोजनों को बंद कर दिया है। ग्रेटर कैलाश स्थित 'अमलतास' रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने बताया कि मौजूदा हालात में उनका रेस्तरां भी बड़ी बुकिंग स्वीकार करने में सावधानी बरत रहा है। उन्होंने कहा, "एलपीजी की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता की वजह से हम बड़ी बुकिंग या कॉरपोरेट समारोह स्वीकार करने में सावधानी बरत रहे हैं। बड़ी पार्टियों के लिए खाना बनाने में लगातार गैस का इस्तेमाल होता है, इसलिए फिलहाल हम नियमित ग्राहकों और छोटी पार्टियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।" कनॉट प्लेस स्थित मीनार रेस्टोरेंट के मालिक इंदर ने बताया कि एलपीजी आपूर्ति की स्थिति स्थिर होने तक उनके रेस्तरां ने भी बड़े आयोजनों से बचने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "फिलहाल हम कॉरपोरेट समारोह या बड़े आयोजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे आयोजनों के लिए ज्यादा खाना बनाना पड़ता है, जिसका मतलब है एलपीजी की ज्यादा खपत। आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए बड़ी बुकिंग की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।" हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव और सैन्य संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान की आशंकाओं के मद्देनजर देश के कई हिस्सों में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

महाराष्ट्र में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस जानबूझकर दहशत फैला रही है : फडणवीस

नागपुर, (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के जरिए आपूर्ति बाधित होने की अफवाह फैलाकर लोगों में घबराहट पैदा करने का आरोप लगाया। फडणवीस ने नागपुर में वारी एनर्जीज लिमिटेड की 6,200 करोड़ रुपये की "इंटीग्रेटेड 10 गीगावाट सोलर इंगोट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा" के शिलान्यास समारोह के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर क्षेत्र में नागपुर एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा, "चीन के बाहर इस तरह की यह एकमात्र सुविधा है।" शनिवार सुबह खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे दो भारतीय जहाजों के युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को हमेशा अपने काम के जरिए जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, ''अमेरिका के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि अगर कोई अलग–अलग देशों को एक साथ ला सकता है, तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। जब एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनेता उनके बारे में ऐसा कहते हैं, तो हमारे देश के कुछ बड़बोले नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए और भारत को बदनाम करना बंद करना चाहिए।'' महाराष्ट्र में एलपीजी की कमी के दावों पर फडणवीस ने कहा कि यह वितरण से जुड़ी समस्या नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाए गए डर के कारण हुआ है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ऐसा किया है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों ने बार–बार स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया

इंफाल, (भाषा) मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने शनिवार को हाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एनसीसी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के सात राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट को सम्मानित किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इंफाल में आयोजित एक कार्यक्रम में, सिंह ने कैडेटों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने और एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समृद्ध राज्य के निर्माण में योगदान देने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैडेटों ने नयी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड और एनसीसी प्रधानमंत्री रैली सहित प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सिंह ने बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "नयी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड और एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले मणिपुर के उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को सम्मानित करने के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई।" उन्होंने कहा कि इन युवा कैडेटों ने अपने समर्पण, अनुशासन और अनुकरणीय राष्ट्रीय सेवा भावना से मणिपुर को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी उपलब्धियां वास्तव में देश के युवाओं की अपार क्षमता, प्रतिबद्धता और देशभक्ति को दर्शाती हैं। सिंह ने सम्मानित किए गए प्रत्येक कैडेट को बधाई दी और उनसे एनसीसी द्वारा सिखाए गए नेतृत्व, सत्यनिष्ठा और सेवा के मूल्यों को बनाए रखने और कई और युवाओं को गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

उपभोक्ता आयोग ने असफल एटीएम लेनदेन मामले में एक्सिस बैंक को मुआवजा देने का आदेश दिया

मुंबई, (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर स्थित उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के मामले में एक्सिस बैंक को फटकार लगाते हुए उसे एक ग्राहक को राशि वापस करने और 10,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ग्राहक को आठ वर्ष पहले एक असफल एटीएम लेनदेन में 5,000 रुपये का नुकसान हुआ था। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एटीएम में ग्राहक के बैंक खाते से राशि डेबिट होने के बाद नकदी नहीं मिलने को गंभीर मामला बताया। आयोग ने कहा कि ऐसे लेनदेन की जांच करना और ग्राहक को तत्काल राहत देना बैंक की जिम्मेदारी है। पिछले महीने दिए गए एक फैसले में, आयोग ने पाया कि बैंक ने शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और लोकपाल प्रक्रिया के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने में विफल रहा। यह असफल लेनदेन 19 अगस्त, 2018 का है। नागपुर निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने एक्सिस बैंक के एक एटीएम से 5,000 रुपये निकालने का प्रयास किया था। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष सतीश सप्रे और सदस्य मिलिंद केदार ने एकपक्षीय रूप से की, क्योंकि कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद एक्सिस बैंक आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता की ओर से बार–बार शिकायत किए जाने के बावजूद बैंक यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि उसने मामले की उचित जांच कराई या एटीएम के निगरानी कैमरे की जांच की। आयोग ने कहा कि अभिलेखों से स्पष्ट है कि बैंक ने शिकायतकर्ता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। आयोग ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के बाद भी बैंक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। आयोग ने माना कि खाते से राशि कटने के बावजूद ग्राहक को नकदी नहीं मिलना बैंक की सेवा में कमी को दर्शाता है। आयोग ने बैंक को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये लौटाए और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये मुआवजा दे।

खेती में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए 900 संस्थानों को जोड़ेगा आईसीएआर

नयी दिल्ली, (भाषा) कृषि अनुसंधान निकाय आईसीएआर ने रविवार को कहा कि वह खेती में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए 900 से अधिक संस्थानों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय 'जेंडर प्लेटफॉर्म' विकसित कर रहा है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वै. श्विक गठबंधन का प्रस्ताव अपनाया गया है। 'कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाएं' (जीसीडब्ल्यूएएस–2026) विषय पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक एम एल जाट ने बताया कि यह मंच आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों को जोड़ेगा। इसका मकसद कृषि में महिलाओं पर केंद्रित अनुसंधान, विस्तार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली में आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 18 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन 'दिल्ली घोषणापत्र' को अपनाने के साथ हुआ, जिसमें कृषि–खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर केंद्रित एक वैश्विक गठबंधन स्थापित करने का आह्वान किया गया है। घोषणापत्र के जरिये हितधारकों ने लैंगिक रूप से उत्तरदायी नीतियों को बढ़ावा देने, महिलाओं की भूमि, वित्त, प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार तक पहुंच सुनिश्चित करने और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

पेट्रोल–डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए रिफाइनरी कीमतों पर 'रोक' लगाने की तैयारी

नयी दिल्ली, (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने की वजह से उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के लिए रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयातित दरों से कम कीमत देने पर विचार कर रही हैं। इस कदम से एमआरपीएल, सीपीसीएल और एचएमएल जैसी एकल रिफाइनरी कंपनियों पर बुरा असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया संकट से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थीं, जो अब बढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंच गई हैं। हालांकि, भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को इस बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ओएमसी अब रिफाइनरी हस्तांतरण शुल्क (आरटीपी) पर रोक लगाने या उस पर छूट तय करने के विकल्प पर विचार कर रही हैं। आरटीपी वह आंतरिक कीमत होती है, जिस पर रिफाइनरियां अपने विपणन खंड को ईंधन बेचती हैं। इस कदम का मकसद रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयात–समता लागत से कम भुगतान करना है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया उद्योग जगत को पूर्ण सरकारी सहयोग का भरोसा

मोहाली, (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को उद्योग. पतियों को पूर्ण सरकारी सहयोग और प्रोत्साहन का आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। तीन दिवसीय प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के समापन अवसर पर मान ने कहा कि इस आयोजन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की भागीदारी ने औद्योगिक विकास के लिए सही माहौल तैयार किया है और यह राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सम्मेलन के दौरान आए निवेश प्रस्तावों और तय परियोजनाओं की प्रगति का छह माह बाद फिर मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों का धन्यवाद करते हुए कहा, ''मैं उद्योग जगत का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्य की वृद्धि यात्रा में भाग लिया। हमारी सरकार पंजाब को विश्व स्तर पर एक प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।'' उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान लगभग 30 विचार–विमर्श सत्र आयोजित किए गए, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

एलपीजी बुकिंग घटकर 77 लाख हुईं, ईंधन की कोई कमी नहीं: सरकार

नयी दिल्ली, (भाषा) पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने बताया कि देश में घरेलू एलपीजी रिफिल बुकिंग में गिरावट आई है और यह अब लगभग 77 लाख पर पहुंच गई है, जबकि 13 मार्च को यह 88.8 लाख थी। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह की कमी नहीं है। सरकार ने पश्चिम एशिया की स्थिति के प्रभाव पर जारी दैनिक अपडेट में बताया कि ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग का हिस्सा बढ़कर लगभग 87 प्रतिशत हो गया है, जो पहले 84 प्रतिशत था। इसका श्रेय तेल विपणन कंपनियों द्वारा डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने और लोगों को एलपीजी डीलरशिप पर लंबी कतारों में खड़ा होकर ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने से रोकने वाले अभियान को दिया गया है। सरकार ने बताया कि देश की सभी घरेलू रिफाइनरी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं और पर्याप्त कच्चे तेल का भंडारण बनाए हुए हैं। सरकार ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू मांग पूरी करने के लिए इन ईंधनों का कोई आयात आवश्यक नहीं है। तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन खुदरा बिक्री केंद्रों या एलपीजी वितरकों के पास भंडारण खत्म होने की कोई जानकारी नहीं दी है, और पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की आपूर्ति नियमित रूप से बनाए रखी जा रही है। सरकार ने बताया कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट आई है।

शनिवार को लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई, जबकि 13 मार्च, 2026 को यह संख्या 88.8 लाख थी। साथ ही ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का हिस्सा बढ़कर 84 प्रतिशत से लगभग 87 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देना और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना जारी रहेगा, विशेषकर घरों और प्राथमिक क्षेत्रों जैसे अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए।केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने गैर–घरेलू एलपीजी के आवंटन के लिए निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए कड़ाई से निगरानी और कार्रवाई कर रही हैं। सरकार ने बताया कि आंध्र प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए छापेमारी भी जारी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी भी एलपीजी वितरकों पर अचानक निरीक्षण कर आपूर्ति की सुचारुता सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे घबराकर एलपीजी बुकिंग न करें, क्योंकि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्राथमिक क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर राज्य सरकारों को प्राथमिक वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और अब ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सरकार ने एलपीजी नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है, जिसके तहत पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी कनेक्शन छोड़ना अनिवार्य किया गया है। घरेलू एलपीजी उत्पादन अधिकतम किया गया है और बुकिंग अंतराल को समुचित रूप से निर्धारित किया गया है ताकि समान वितरण सुनिश्चित हो। अद्यतन जानकारी में सरकार ने कहा कि विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। 28 फरवरी के बाद से लगभग 1.94 लाख यात्रियों को भारत लौटाया गया है।

सरकारी तेल विपणन कंपनियां डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा दे रही हैं, घबराकर बुकिंग करने से रोक रही हैं और एलपीजी वितरकों को रविवार को भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपूर्ति सुचारू रहे। सरकार ने कहा कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे घबराकर बुकिंग न करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। इसके अलावा नागरिकों को पीएनजी जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अविवाहित इंजीनियर पुत्र निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी लॉन्चिंग से बिहार की राजनीति में दूरगामी असर पड़ना लाजिमी है। चूंकि वह अपने प्रगतिशील और यशस्वी पिता की प्रगतिशील समाजवादी सियासत को संभालेंगे, इसलिए कुछ बातें स्पष्ट हैं। वह यह कि अब तीन बड़े स्तरों पर इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ेगादृ सत्ता संतुलन, जेडीयू की आंतरिक राजनीति और राज्य की व्यापक सियासी प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा कुछ मौलिक सवाल भी उभरेंगे, जिनकी चर्चा पहले लाजिमी है। स्वाभाविक सवाल है कि क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे? हालांकि इसका जवाब गुजशते वक्त की कोख में पल रहा है, जो समय के साथ स्पष्ट होता जाएगा। पहला यह कि उनके पिता नीतीश कुमार अब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होकर 'विलासितापूर्ण' सदन राज्यसभा की ओर रुखसत हो चुके हैं, जबकि बिहार के पुनर्निर्माण के उनके सपने अभी भली भांति पूर्वक जवान भी नहीं हो पाए हैं। इसलिए उन्हें उचित नीतिगत पोषण प्रदान करते हुए जवान करने की जिम्मेदारी अब टीम निशांत कुमार की होगी। कहना न होगा कि पहले 20 साल तक यानी 1985 से 2025 तक नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत संघर्ष की राजनीति की और बाद के 20 वर्षों तक यानी 2005 से 2025 उन्होंने सत्ता संघर्ष की राजनीति की। इसी कशमकश में बिहार के पुनर्निर्माण के उनके सपने वैचारिक कुपोषण, प्रशासनिक धूर्तता के शिकार हो गए और पूरी तरह से जवान नहीं हो पाए। दूसरा यह कि जनता दल यूनाइटेड की सहयोगी पार्टी भाजपा भले ही राष्ट्रीय समाजवादी राजनीति की तरह ही सूबाई समाजवादी राजनीति के प्रतिबिंब जदयू को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पुनः सियासी धोबिया पाट पर राजनीतिक चोट देते हुए जदयू को देश–प्रदेश में पुनः बड़े भाई का दर्जा दिलवाने के सारे दारोमदार अब निशांत कुमार के कंधे पर होंगे। संदेश स्पष्ट है कि बड़े सपने देखेंगे तो उड़ीसा के नवीन पटनायक की तरह सफलतापूर्वक भविष्य में राज करेंगे, अन्यथा चिराग पासवान की तरह बीजेपी के आगे सियासी दुम हिलाते नजर आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो यही समझा जाएगा कि बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार ने अपनी पुत्र को समुचित राजनीतिक शिक्षा दिए ही उनकी लॉन्चिंग करवा दी। कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के जेहन में उठ भी रहे हैं। तीसरा यह कि जेडीयू और उसके सत्ता समीकरण पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और संभावित नेतृत्व परिवर्तन के साथ निशांत को डिप्टी सीएम/मुख्य चेहरा बनाने की तैयारी है, जिससे जेडीयू में नेतृत्व का खालीपन भरने की कोशिश होगी। यह कदम बीजेपीदृजेडीयू गठबंधन में निरंतरता का संदेश देगा कि नीतीश भले पटना से दिल्ली शिफ्ट हों, पर "उनका आदमी/परिवार" सत्ता में रहेगा, जिससे अचानक अस्थिरता की संभावना घटेगी लेकिन इसके दूरगामी असर नकारात्मक भी हो सकते हैं। चौथा यह कि जेडीयू की आंतरिक राजनीति भी इस घटनाक्रम से प्रभावित होगी। ऐसा इसलिए कि जेडीयू के कई एमएलएदृएमपी ने खुले तौर पर मांग की कि निशांत ही पार्टी को "एकजुट रख सकते हैं", जो यह दिखाता है कि नेतृत्व संकट से बचने के लिए संगठन परिवारवाद को स्वीकार कर चुका है। इससे पुराने कद्दावर नेताओं के बीच पददृप्रतिष्ठा को लेकर खींचतान बढ़ सकती है क्योंकि अचानक एक नए, राजनीतिक रूप से अनुभवहीन चेहरे को शीर्ष पर लाना वरिष्ठों की महत्वाकांक्षाओं से टकराएगा। पांचवां यह कि इस बड़े बदलाव से जदयू के वंशवाद बनाम सुशासन की छवि टकराएगी क्योंकि नीतीश लंबे समय से वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं; और अब बेटे की लॉन्चिंग से उनकी राजनीतिक व वैचारिक साख और "सुशासन बाबू बनाम पारिवारिक राजनीति" वाली नैरेटिव पर विपक्ष को मजबूत हमला करने का मौका मिलेगा। वहीं, आरजेडीदृकांग्रेस सहित विपक्ष इसे "डबल स्टैंडर्ड" कहकर भुनाएगा, जिससे सामाजिक न्याय बनाम परिवारवाद की पुरानी बहस फिर तेज होगी और यादवदृगैर लवकुश ओबीसीदृअल्पसंख्यक वोटों की समीकरण राजनीति और ज्यादा आक्रामक हो सकती है, जिसकी धार नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर कुंद कर चुकी हैं। छठा यह कि जदयू के इस घटनाक्रम का सूबाई युवा और सामाजिक आधार पर भी संभावित प्रभाव पड़ेगा। अब जदयू पार्टी के भीतर से यह तर्क दिया जा रहा है कि निशांत के आने से युवा वोटर और पढ़ादृलिखा मध्यवर्ग जुड़ सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब वे जल्दी ज़मीनी राजनीति सीखकर स्वतंत्र छवि बना पाएं। अभी के लिए उनका पूरा राजनीतिक वैधता पूंजी "नीतीश के बेटे" होने से आती है; अगर प्रशासनिक या संगठनात्मक क्षमता जल्दी साबित न हुई तो वे सिर्फ प्रतीकात्मक वारिस बनकर रह सकते हैं जिससे जेडीयू की गिरती सामाजिक पकड़ नहीं रुक पाएगी। सातवां यह कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग का बिहार की व्यापक सियासत में लंबी अवधि का असर पड़ेगा। निकट भविष्य में यह कदम बीजेपीदृजेडीयू सरकार को स्थायित्व देगा, लेकिन मध्यम अवधि में यह तय करेगा कि नीतीश के बाद जेडीयू स्वतंत्र शक्ति बनी रहती है या भाजपा पर और अधिक निर्भर हो जाती है। ऐसा इसलिए कि यदि निशांत कुमार पार्टी के अंदर स्वीकार्यता बना लेते हैं और संगठन पर पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो वे आने वाले चुनावों में जेडीयू को "पोस्ट–नीतीश" दौर में भी प्रासंगिक रख सकते हैं; वहीं यदि असफल रहे तो बिहार की राजनीति और ज़्यादा द्विध्रुवीय (बीजेपी बनाम आरजेडीदृकांग्रेस) हो सकती है और जेडीयू हाशिये पर जा सकता है। आठवां यह कि निशांत की एंट्री ने नीतीश कुमार के सालों पुराने एंटी–वंशवाद नैरेटिव को सीधे काट दिया और बिहार में लगभग सभी बड़े नेताओं के परिवारवाद को एक साथ एक्सपोज़ कर दिया। इससे यह साफ दिखने लगा कि 'वंशवाद विरोध' ज्यादातर नैतिकता नहीं, बल्कि अवसरवादी राजनीति की भाषा थी। इस मुद्दे पर नीतीश का यू–टर्न और नैतिकता का संकट खड़ा हो गया है। नीतीश खुद को कर्पूरी ठाकुर की परंपरा का मानते रहे, जो बेटे को राजनीति से दूर रख कर वंशवाद के खिलाफ उदाहरण बताए जाते हैं। नौवां यह कि कई दशक तक वे लालू प्रसाद, कांग्रेस और अन्य दलों पर परिवारवाद का हमला बोलते रहे; और अब उसी मॉडल पर अपने बेटे निशांत को सीधे उत्तराधिकारी की तरह आगे कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा जाने और बेटे के लिए स्पेस बनाने के लिए उन्होंने राजनीतिक पटकथा लिखी है, उससे उनकी समाजवादी राजनीति पर भी सवाल उठना लाजिमी है। बताया जाता है कि विपक्ष (जैसे त्श्रव) ने इसे तुरंत पकड़ लिया कि जिसने हमेशा नेपोटिज़्म को कोसा, वही अब "अपने उत्तराधिकारी को सेट" कर रहा है, यानी नैतिक ऊँचाई ढह गई। दसवां यह कि बिहार की ओबीसी/दलित 'राजवंशी' राजनीति अब खुलकर सामने आ चुकी है। पहले से ही तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक आदि खुले तौर पर पिता की विरासत संभाल रहे थे। इसी कड़ी में नीतीश पुत्र निशांत की एंट्री के बाद तस्वीर और साफ हो गई कि लगभग हर प्रमुख सामाजिक–राजनीतिक धड़े का नेतृत्व अब "पॉलिटिकल वंशजों" के हाथ में जा रहा है, यानी पूरा सत्ता–संतुलन परिवारों के इर्द–गिर्द घूम रहा है। ग्यारहवां यह कि प्रशांत किशोर व अन्य आलोचकों ने राजनीतिक पाखंड उजागर किया। प्रशांत किशोर ने सीधे सवाल उठाया कि जो नेता जीवन भर वंशवाद के विरोध का दावा करते रहे, वे आज अपने ही बेटे के लिए जगह बना रहे हैं; यानी 'सिद्धांत' दरअसल सत्ता और परिवार के हिसाब से बदलने वाली चीज़ है। वहीं, राजद नेताओं ने भी कहा कि नीतीश अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, जिसको वे लालू परिवार की राजनीति में दोष बताते थे; इससे "हम अलग हैं" वाला दावा कमजोर हो गया। बारहवां यह कि युवाओं के मुद्दों बनाम राजनीतिक वंश की कशमकश अब तेज होगी क्योंकि निशांत की लॉन्चिंग बहस के साथ ही बेरोजगारी, पलायन और सुशासन बनाम परिवारवाद जैसे सवाल फिर उभरे हैं: क्या नई पीढ़ी के लिए नेतृत्व का मतलब सिर्फ नेताओं के बच्चे होंगे या आम कार्यकर्ता/युवा भी ऊपर आएंगे? वहीं जदयू और सहयोगी इसे "नई पीढ़ी का नेतृत्व" कह कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह तर्क भी उसी समय कमजोर पड़ जाता है जब टिकट, पद और कुर्सी लगभग पूरी तरह परिवारों में सिमटते दिखते हैं। स्वाभाविक सवाल है कि क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे? हालांकि इसका जवाब गुजशते वक्त की कोख में पल रहा है जो समय के साथ स्पष्ट होता जाएगा।

कमलेश पांडेय

संपादकीय

बंगाल की सियासत में उभरते प्रश्नः लोकतंत्र, सुरक्षा और सुशासन

..... उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण राज्य के कई क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव आया है। उनके अनुसार यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि इस चुनौती का समाधान केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं और इतिहास में कई बार इस सीमा के माध्यम से अवैध प्रवेश की घटनाएं सामने आती रही हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों में भी समय–समय पर इस विषय का उल्लेख किया गया है। यही कारण है कि चुनाव के समय यह मुद्दा और अधिक प्रमुखता से उठाया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में इसी संदर्भ को सामने रखते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस समस्या का समाधान आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह राज्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे शासन का समर्थन करें जो कानून के राज को मजबूत करे और विकास को प्राथमिकता दे। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य को ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो पारदर्शिता, सुशासन और विकास को केंद्र में रखे। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और कथित 'कट मनी' की राजनीति का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी जनता तक पहुंच सकता है जब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तो राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई गति मिल सकती है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास भी इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक वामपंथी दलों के शासन के बाद वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और उसके बाद से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बने। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत किया है। यही कारण है कि वर्तमान चुनावी माहौल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की रैली इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच आयोजित हुई और इसने चुनावी माहौल को और अधिक सक्रिय बना दिया। हालांकि इन मुद्दों पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी का दृष्टिकोण अलग है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का यह भी आरोप है कि घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक रूप से बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल की राजनीति में दो अलग–अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं, जिनके बीच लोकतांत्रिक बहस जारी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में संवैधानिक संस्थाओं के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का सम्मान किया जाए और उनकी निष्पक्षता पर अनावश्यक सवाल न उठाए जाएं। उनके अनुसार जब भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का प्रयास होता है, तब कुछ राजनीतिक विवाद सामने आते हैं, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता ही देश की ताकत होती है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए कानून का मजबूत ढांचा अत्यंत आवश्यक होता है। जब नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा मिलता है और प्रशासनिक व्यवस्था निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, तब निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।

उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि राज्य में सुशासन स्थापित होता है तो पश्चिम बंगाल अपनी ऐतिहासिक क्षमता के अनुरूप विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में इस राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और साहित्य, कला, शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्र में भी इसने देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोलकाता कभी भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता था। हालांकि समय के साथ कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आईं, जिनसे निपटने के लिए राज्य को नई नीतियों और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की रैली को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। उनके भाषण में जहां राजनीतिक आलोचना थी, वहीं राज्य के भविष्य को लेकर एक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने वाली शासन व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार जब राज्य में भय और भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण बनेगा, तब यहां की युवा शक्ति और उद्यमिता नई संभावनाओं को जन्म देगी।

आगामी विधानसभा चुनावों के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से लेकर घुसपैठ, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दे इस चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री की रैली ने इन सभी विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। अब यह राज्य के मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वे किस दृष्टिकोण और किस राजनीतिक दिशा को स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। पश्चिम बंगाल के लोग अपनी राजनीतिक जागरूकता और सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि यहां के चुनाव हमेशा पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हैं। कोलकाता की इस रैली ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राज्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर भी है। पश्चिम बंगाल की धरती ने हमेशा से परिवर्तन और विचारों की नई धाराओं को जन्म दिया है। आज जब राज्य एक नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है, तब यह अपेक्षा की जा रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न हो। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनेगा।

कृष्णा अग्रवाल
focusnews9@gmail.com

खाना बनाएं हैल्दी

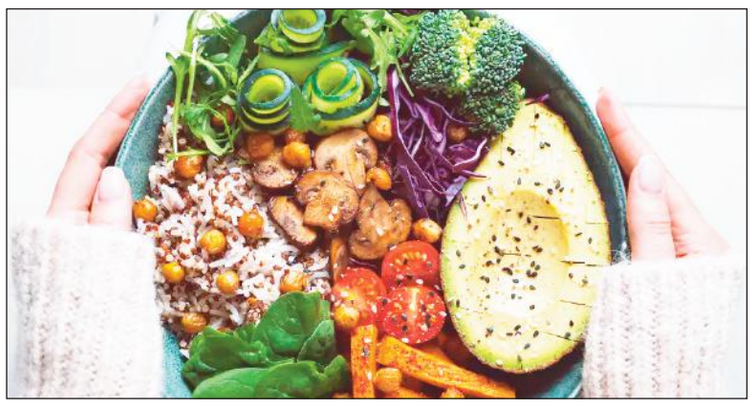

सर्दियों में चटपटा और गर्म खाने का मन खूब करता है। सर्दियों में वजन भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि तले हुए और मीठे व्यंजन खूब खाए जाते हैं। चटपटे और गर्म व्यंजन पसंद हों तो अपने कुकिंग स्टाइल में थोड़ा चेंज लाकर स्वाद को बरकरार रखते हुए और अधिक हैल्दी बना सकते हैं।

एक ही तरह की सब्जी बनाने के स्थान पर मिक्स वेजीटेबल बनाएं और दालों को भी मिलाकर बनाएं।

पनीर के स्थान सोयाबीन की बड़ियों व चूरे का प्रयोग अधिक करें। सब्जियों में सोयाबीन का चूरा भी मिलाकर पकाया जा सकता है जो पौष्टिकता बढ़ा देगा।

सब्जियों में मकई के दाने डालकर सब्जी को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया जा सकता है।

गाजर का हलवा खूब खाएं मगर ध्यान दें कि टोंड दूध का ही प्रयोग करें। मावे का प्रयोग भी न करें।

ग्रेवी वाली सब्जी अधिक बनाएं ताकि तेल का प्रयोग कम हो जिसको हम मोटे अनाज की रोटी के साथ आसानी से खा पाएं।

सर्दियों में खाने की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि भूख अधिक लगती है पर एक बार में ढेर सारा न लें।

अगर आप शौकीन हैं बार–बार चाय काफी पीने के तो ग्रीन टी बिना दूध और बहुत कम चीनी वाली लें। चाहें तो नींबू का रस मिला सकते हैं। स्वाद भी बढ़ेगा और ग्रीन टी नुक्सान भी नहीं पहुंचाएगी। चाहें तो खाना खाने के एक घंटे बाद अच्छा गर्म पानी सिप सिप कर पी सकते हैं। चाय की रिपलेस्मेंट के लिए यह अच्छा और हैल्दी आप्शन है।

सर्दियों में परांठे खाने का खूब मन करता है मसलन मेथी, गोभी, मटर, पालक, गाजर, मूली के परांठे। उन्हें आप आटे में गूंथकर हल्के तेल में बना सकते हैं। चाहें तो आटे में थोड़ा बेसन, अजवायन, नमक, मिर्च डालकर टोंड दूध से या टोंड दूध से आटा गूंथ कर परांठा पका सकते हैं जो नर्म और स्वादिष्ट भी होगा और पौष्टिक भी।

गर्म गर्म मोमोज खाने का मन हो तो स्टीम्ड मोमोज खाएं।

चटपटी दाल बनाने के लिए दाल बनाते समय कुकर में दाल के साथ लहसुन, टमाटर, अदरक व प्याज को डालें। दाल पक जाने के बाद कम तेल में राई, जीरा, साबुत लाल मिर्च का तड़का देकर सर्व करें।

गोभी–पालक, मेथी के पकौड़े खाने का मन हो तो उन्हें लो कैलोरी आयल में तलें और खाने से पूर्व एक बार उन्हें नेपकिन में रखें ताकि तेल और अधिक निकल जाए। उसके बाद खाएं। सास के स्थान पर हरी धनिए की चटनी के साथ खाएं।

कवाब या कोफ्तों को डीप फ्राई न कर उन्हें स्टीम कर बनाएं।

ताकि होंठ हों आकर्षक और स्वस्थ

आदमी हो या औरत, सबसे पहले हमारी नजर उसके चेहरे पर पड़ती है। ऐसे में होंठों पर अनायास ही ध्यान जाता है। अगर होंठ स्वस्थ व सुंदर हों तो आकर्षण बढ़ ही जाता है। जरा खुद को देखिए, क्या आपके होंठ स्वस्थ, आकर्षक और रसीले हैं कि नहीं? अगर आपके होंठों में आकर्षण कम लगता हो तो उन पर ध्यान दीजिए। ध्यान रखिए नारी सौंदर्य में स्वस्थ सुंदर होंठों का बड़ा महत्व है। यहां पेश हैं कुछ उपयोगी टिप्सः

केसर को दूध की मलाई से रगड़ कर रात को होंठों पर लगाकर सोएं।

होंठों को मुलायम व खूबसूरत बनाए रखने के लिए इनकी नियमित रूप से मलाई से मालिश करें। इससे होंठ मुलायम होंगे।

रात को सोते समय इन पर गुलाब की पंखुड़ियों और मलाई का पेस्ट बनाकर लगाने से भी फायदा होगा।

अगर होंठ फट गए हों तो वैसलीन या किसी अच्छी कम्पनी का लिप बाम लगायें।

भोजन में मक्खन को नियमित स्थान दें। अगर होंठ सूख रहे हैं और उनमें से खून निकलता है तो तुरंत किसी डाक्टर से मिलें और फटे होंठों का सही इलाज कराएं।

पानी कम पीने से होंठ फटते हैं। ऐसे में नियम से पानी पीने की आदत डालें। रोज कम से कम आठ–दस गिलास पानी जरूर पिएं।

हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। ऐसे फल खाएं जिसमें विटामिन भरपूर मात्रा में हों।

होंठों को कभी भी दांतों से नहीं चबाएं। इससे होंठों का आकार बिगड़ता है और होंठ देखने में भददे लगते हैं।

अगर होंठ ज्यादा फट रहे हों तो शहद व देशी घी लगाने से भी फायदा होगा।

अगर होंठों पर घी लगाना नहीं चाहती तो रात को सोते समय घी हल्का सा गरम करके नाभि में लगाएं। सुबह तक काफी फायदा होगा।

होंठों पर कभी भी सस्ती लिपस्टिक प्रयोग न करें। इससे होंठों को नुकसान पहुंचता है। मैट लिपस्टिक का भी ज्यादा प्रयोग न करें। इससे होंठ जल्दी रूखे हो जाते हैं और उनकी प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है।

लिपस्टिक कैसे लगाएं?

लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों की आउटलाइन किसी गहरे रंग से लिपलाइनर से बना लें। होंठों को उनके प्राकृतिक आकार से हट कर शेप देना चाहें तो ऐसा करें। बस आउटलाइन बनाते समय सावधान रहें कि कहीं हाथ कांपे नहीं वरना आउटलाइन टेढ़ी बनेगी।

होंठों पर आउटलाइन बनाने से पहले पाउडर लगा लेने से लिपस्टिक अधिक समय तक टिकी रहती है। पाउडर लगाने के बाद होंठों पर अपनी ड्रेस से मेल खाती लिपस्टिक लगाएं।

इसके बाद होंठों को टिश्यू पेपर से ब्लाट करें। इससे अतिरिक्त लिपस्टिक निकल जाएगी। ऐसे दो–तीन बार करें। लिपस्टिक होंठों में अच्छे से जब्त हो जायेंगी। अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुये ही लिपस्टिक के रंग का चुनाव करें। सिर्फ यह न देखें कि क्या चलन में है। आप पर उस चीज का सूट करना भी जरूरी हैं। वैसे ब्राउन रंग हर महिला पर जंचता है। कभी भी कपड़े से रगड़कर लिपस्टिक साफ न करें। हल्के हाथ से हमेशा क्लीजिंग मिल्क से ही साफ करें।

लड़ाई करें, दांपत्य जीवन में ताजगी लाएं

फिल्म लव स्टोरी के एक चर्चित गाने में नायिका नायक से अपने सपनों के घर में लड़ाई वाली जगह के बारे में पूछती है, तब नायक कहता है कि उस ने तो घर में लड़ाई करने वाली कोई जगह बनाई ही नहीं है मगर हर रिश्ते में एक नएपन के लिए और उस में आकर्षण के लिए थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना और रूठना मनाना जरूरी है। उस पर भी जब वह रिश्ता परफेक्ट पति पत्नी का हो तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि उनकी लड़ाई परफेक्ट हो, परफेक्ट यानी संपूर्ण। अक्सर लड़के लड़कियां शादी से पहले अपने जीवन साथी को लेकर बहुत से सपने संजोते हैं। जब उम्मीदों पर खरे उतरने वाले सपनों के परफेक्ट पति–पत्नी मिल भी जाते हैं तो चंद महीनों तक दोनों एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों का खूब ध्यान रखते हैं मगर फिर धीरे–धीरे ये नियम और परफेक्शन पति–पत्नी के जीवन में नीरसता भरने लगते हैं। इस नीरसता को दूर करने के लिए परफेक्ट पति पत्नी भी अगर अपने जीवन में हल्की–फुल्की नोक–झोंक करते रहें तो संबंधों में ताजगी बनी रहती है मगर ध्यान रहे कि यह टकरार गंभीर रूप न ले ले क्योंकि इससे आपका दांपत्य दांव पर लग सकता है, इसलिए अपने आपको परफेक्ट मानने वाले दंपति जब भी लड़ाई करें तो जीवन साथी का स्वाभिमान आहत न करें।

35 वर्षीय शीतल अपने पति जितेन्द्र के बारे में बताती हैं– जितेन्द्र समय के बड़े पाबंद हैं। अपने सामान को लेकर भी बड़े पर्टीकुलर हैं। अगर कोई चीज जगह पर न मिले तो इनका पारा हाई हो जाता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं यहीं सोचती रहती थी कि अगर इनके जैसा परफेक्ट नहीं बन पाई तो क्या होगा मगर मैंने अपने आप को इनके हिसाब से ढाल लिया। इनकी एक आदत ऐसी है कि जिसे लेकर हमारे बीच अक्सर नोक–झोंक हो जाती है और वह है घर में घुसते ही टीवी चला लेने की आदत मगर दूसरे दिन याद ही नहीं रहता कि हमारी पिछली शाम को लड़ाई भी हुई थी। इसी तरह शीतल के पति जितेन्द्र ने बताया–शीतल बहुत अच्छी बहू है, पत्नी है और मां भी मगर परफेक्ट मेकअप के चक्कर में कई बार यह इतनी देर लगा देती है कि हमारी तू–तू मैं–मैं हो जाती है पर हम लड़ाई को इतना तूल नहीं देते कि हमारा रिश्ता दांव पर लग जाए। शादी के शुरू के दिनों में बस एक बार हुआ था जब तलाक शब्द हमारे बीच आ गया मगर वह हमारा बचपना था, यह हम अब रियलाइज करते हैं, इसलिए हम लड़ते भी हैं तो रात गई बात गई वाले अंदाज में। अपनी लाइफ को लाइवली जीने के लिए 'आओ डियर करें लड़ाई' के रूप में हमारी लड़ाई मोल ली हुई होती है जिसमें हल्की फुल्की छेड़छाड़ और रूठना मनाना जरूर चलता है। जरूरी नहीं कि हर पति–पत्नी की सोच शीतल और जितेन्द्र जैसी सुलझी हो। कई बार पति–पत्नी के बीच हल्की–फुल्की नोंक– झोंक के रूप उभरे झगड़े गंभीर लड़ाई का रूप ले लेते हैं। उस पर परफेक्शनिस्ट होने का जुनून उन्हें ज्यादा अहंकारी बना देता है। आप भी कहीं अपने जीवन साथी से बात–बात पर झगड़ने वाले, रोने सुबकने वाले लाइफ पार्टनर तो नहीं बनते जा रहे हैं?

अगर आप अपने जीवन साथी के काम और व्यवहार में बदलाव महसूस करते हैं या फिर मन में उसके चरित्र को लेकर शक का बीज पल रहा हो तो बजाय शक में अपने आपको परेशान करने के उस की जड़ तक पहुंच कर उसे दूर करें जैसा कि शीतांशु और श्वेता की जिंदगी में चल रहा था। टूरिंग जाब करने वाली शीतांशु की पत्नी श्वेता की अचानक बढ़ी व्यावसायिक व्यस्तता ने शीतांशु के मन में उसके चरित्र को लेकर शक पैदा कर दिया था। इसका एक कारण यह था कि शीतांशु के मित्र की पत्नी काम के बहाने पुरूष मित्रों से रोमांस करती थी, इसलिए एक दिन शक से भरा शीतांशु श्वेता के आफिस जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वाकई श्वेता आजकल टूर्स में व्यस्त है। इस तरह शीतांशु की समस्या जड़ से दूर हो गई। इस प्रकार दांपत्य में छा रही समस्या को ढूंढ़ कर उसे हल करने का प्रयत्न करें ताकि मन में उपजा शक का अंकुर विषबेल न बन जाए।

दांपत्य संबंधों में छोटी–छोटी खटपट तो चलती रहती है मगर अपने आप को संपूर्ण समझने वाले दंपति परफेक्शन में डूबे हर बात में अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कई बार उनकी गृहस्थी बिखर भी जाती है। अपने जीवन साथी की छोटी बातों को लेकर टोकना उस की छोटी–छोटी गलतियों को नजर अंदाज करने की बजाय उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बात का बतंगड़ बना देना आपके दांपत्य संबंधों में दरार का कारण बन सकता है इसलिए ध्यान रहे कि छोटी–छोटी बातों को तूल देकर उन्हें दांपत्य के टूटने का कारण न बनाएं। अक्सर लड़के–लड़कियों के दिमाग में अपने भावी जीवन साथी को लेकर एक स्वप्निल छवि अपने जीवन साथी में नहीं दिखती तो बेवजह की बहस शुरू होती है। ऐसे में हर मुद्दा बहस का कारण बन जाता है पर ऐसी बहस का नतीजा वहीं ढाक के तीन पात वाला होता है। हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर होती है। दूसरे की कमियों को उजागर करने से बेहतर है कि अपनी कमियों को समझें और स्वीकारें। बहस के समय शब्दों से कहीं अधिक ताकतवर होती है मौन की भाषा क्योंकि मौन अवस्था में मैं का लोप हो जाता है। पति–पत्नी संबंधों में थोड़ी बहुत कहा सुनी सामान्य बात है पर इस संबंध में परफेक्शन की परिभाषा किसी एक तक ही सीमित नहीं होती बल्कि एक दूसरे को समझने की इच्छा और एक दूसरे के सुखदुख में सहजानुभूति उन्हें परफेक्ट बनाती है। एक दूसरे को समझने की काबिलियत रखने वाले दंपति परफेक्ट माने जाते हैं। ऐसे परफेक्ट दंपतियों की नोक–झोंक और तकरार कभी उनकी गृहस्थी के टूटने का कारण नहीं बनती बल्कि वे जब भी लड़ते हैं तो 'आओ डियर करें लड़ाई' के मूड में जो उनकी रूटीन लाइफ में नई ताजगी भर देती है।

प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए

प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए जहां क्वालिफाइड और काम में एफिशियंट होना जरूरी है वहीं साफ्ट स्किल्स की अहमियत भी कम नहीं क्योंकि एक जरा सी बात को लेकर नासमझी दिखाने पर सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। आपकी प्रमोशन रूक सकती है। अच्छा होगा आप अपने व्यवहार का समय–समय पर विश्लेषण करते रहें। अगर आप स्वभाव से हायपर सेंसिटिव हैं, जरा–जरा सी बात दिल से लगा बैठते हैं तो यह आपकी तरक्की की राह में बाधक बन सकता है। आफिस में आपको प्रोफेशनल बनकर रहना है। इसके लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। आजकल बहुत सी वर्कशाप्स, पर्सनेलिटी डेवलेपमेंट कोर्सेज यह सब भी सिखा रहे हैं। आप अपनी सुविधा से कोई क्रेश कोर्स इस विषय पर कर सकते हैं। इस विषय पर किताबें पढ़ सकते हैं। सेल्फ हैल्प बुक्स भी आपकी हैल्प के लिए हैं।

डायरी मेंटेन करें:– भावनाओं पर नियंत्रण रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसे रैग्युलर प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। एक सरल और सुविधाजनक टेक्नीक है डायरी में अपने प्लस माइनस पाइंट्स नोट करना। अपने गुस्से, इमोशनल आउटबर्स्ट को एनेलाइज करने के लिए उनका रेफेरेंस भी नोटिस में लें। उन स्थितियों को याद करें जिसके होने पर आप अपना आपा भूल जाते हैं। आगे से ऐसी स्थिति आने पर संभल जाएं। दिमाग में बज रही घंटी को सुनें और संभल जाएं।

बास इज आलवेज राइट:– बास से उलझना जल में रहकर मगर से बैर करने जैसा है, इसलिए यह मानकर चलने में ही भलाई है कि बास इज आलवेज राइट। साथ काम करते हुए बास की साइकोलोजी को समझें और उन्हीं के अनुकूल चलते हुए उनके साथ अपना व्यवहार रखें। अगर आप उनकी बात से असहमत हैं, तब भी बगैर रूड हुए विनम्रता से ही पेश आएं।

धैर्य रखें:– कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको प्रोवोक कर जाती है लेकिन तीव्र प्रतिक्रिया देकर भी क्या होगा, सामने वाला समझ पायेगा, अगर समझदार होता तो ऐसी बात ही क्यों करता? उस समय धैर्य रखें और जरूरी समझें तो बाद में धैर्यपूर्वक उसे उसकी गलती का अहसास कराया जा सकता है।

नापसंद होने पर:– कई लोगों की स्ट्रांग लाइक्स और डिस्लाइक्स होती हैं मगर यह मानकर चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सेंट परसेंट अच्छा या बुरा नहीं होता। फिर आपके मन में किसी की कैसी भी बुरी इमेज क्यों न बनी हुई हो, उस पर कभी अपनी नापसंद जाहिर न होने दें। आफिस में ऐसे लोगों से भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। इसी का नाम डिप्लोमेसी है जो आपको आनी चाहिए। हां, इतना कर सकती हैं कि उनसे केवल प्रोफेशनल बातचीत ही रखें और टू द पाइंट बात करें।

पाजिटिव अप्रोच रखें:– जीवन में पाजिटिव सोच बहुत महत्व रखती है। आपकी खुशियां, सुख चैन व कामयाबी उस पर बहुत निर्भर करती हैं। आफिस में आपके साथ बहुत से लोग होते हैं। सब का स्वभाव बात करने का ढंग भिन्न होता है क्योंकि, यहां सभी काम के मकसद से ही आते हैं। इसलिये आप भी उसी को मद्देनजर रख कर चलें। प्रोफेशनल बातों को दिल पर न लें। आफिस की बात वहीं तक सीमित रहे। उसे घर तक न ले जाएं। बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है, यह मानते हुए सदा अच्छा ही सोचने का प्रयत्न करें। इससे आप जो ऊर्जा बचा पाएंगे, उसे अपने काम में इस्तेमाल करें। आप काम के प्रति ज्यादा फोकस्ड रह पाएंगे। इमोशनल फूल बनकर कुछ हासिल न होगा बल्कि सहकर्मियों की हंसी की पात्रा बनेंगे। किस्मत या चांसेज और आपकी अपनी मेहनत लगन, एक्सपर्टाइज के साथ–साथ आपकी प्लीजिंग पर्सनेलिटी भी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए उतनी ही इंपार्टेंट है।

ब्रेकअप में टूटता है दोनों का दिल

दिल का मामला बहुत नाजुक होता है। जब भी किसी परिस्थितिवश दिल टूटता है तो प्रभाव दोनों पर पड़ता है। पहले माना जाता था कि स्त्रियां दिल के मामले में कमजोर होती है लेकिन अब एक अध्ययन के अनुसार यह बात साबित हुई है कि पुरूष भी तनावग्रस्त होते हैं। यह भी सच है कि पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों के कंधों पर यादों का बोझ ज्यादा होता है इसलिए वे अधिक समय तक तनावग्रस्त रहती हैं। ब्रेकअप होने का दुख महिलाओं और पुरूषों दोनों को होता है, फिर भी महिलाएं अधिक तनावग्रस्त होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुरूषों और महिलाओं की प्रायरिटीज भिन्न होती हैं। पुरूषों की प्रायरिटीज बाहर के कामों में, टीवी देखने में, न्यूजपेपर पढ़ने में, आर्थिक मामलों में, राजनीति में होती है। इमोशंज उनमें सबसे अंतिम प्रायरिटी होती है जबकि महिलाओं के केस में एकदम उलट होता है। उनकी इमोशंस की प्रायरिटी पहले होती हैं, बाकी बाद में, इसलिए दिल टूटने पर महिलाएं ज्यादा परेशान होती हैं। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को पहले अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए महिलाएं बंधनों में बंधी रहती हैं जबकि पुरूष के लिए जिंदगी बिंदास होती है।

पुरूष भी होते हैं तनावग्रस्त:– पुरूष भी होते हैं परेशान पर वे अपने आपको दूसरे कामों में व्यस्त रखते हैं और जल्दी उन इमोशंज से बाहर आ जाते हैं। महिलाओं में एक कमी होती है कि जब वे किसी को प्यार करती हैं तो सब कुछ उनसे शेयर करना चाहती हैं और अपने भविष्य को इमोशनल तौर पर सुरक्षित करना चाहती हैं। यही कारण है कि पुरूषों से ज्यादा सपोर्ट चाहती हैं जबकि पुरूष अपना फोकस काम और अन्य चीजों पर रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। वे अपनी बातों को सोचकर अधिक परेशान नहीं होते पर सभी पुरूष एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे पुरूष भी होते हैं जो ब्रेकअप के बाद स्वयं को टूटा हुआ महसूस करते हैं।

अधिक न सोचें उस बारे में:– जितना आप ब्रेकअप रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, उतने अधिक टेंस रहेंगे। अधिक तनाव से आप नकारात्मक होंगे और हेल्पलेस महसूस करेंगे। लंबे समय तक तनावग्रस्त रहने से डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे जो ठीक नहीं, इसलिए पुरानी बातों व यादों से जल्दी छुटकारा पाने का प्रयास करें। स्वयं को किसी काम में व्यस्त रखें। आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि अपने दिल और दिमाग को हल्का रख सकें।

कुछ बातों को समझना होगा आपको:– – एक बात को गांठ बांध लें कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, न रिश्ते, न संबंध, न लोग, न चीजें, सब कुछ बदलता रहता है। इसे स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करें।

– पुराने घावों को भरने के लिए समय लगता है। इस बीच नए रिश्ते, नई इमोशंज को हावी न होने दें। जल्दबाजी में दूसरा कदम गलत हो सकता है।

– अपनी खुशियां ज्यादा जरूरी हैं। दूसरे की गलती की वजह से अपनी खुशियां खराब न करें।

– दूसरे से उम्मीद कम से कम रखें। ज्यादा उम्मीदें निराशा ही देती हैं। लंबे रिलेशंस के लिए उम्मीद का दायरा कम से कम बनाएं।

– किसी के साथ रिलेशनशिप में आपने उसे क्या दिया और बदले में उसने क्या दिया, उस पर विचार करें जो आपने दिया, वो अपनी इच्छा से दिया, जो उसने दिया, उसने अपनी इच्छा से यह सोच आपको खुश रखेगी।

पेप्सी ने 'सैयारा' के कलाकार अहान पांडेय और अनीत पड्डा को ब्रांड एम्बैसडर बनाया

नयी दिल्ली, गर्मियों के मौसम से पहले शीतल पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सिको की भारतीय इकाई ने युवाओं, खासकर नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए फिल्म 'सैयारा' के अभिनेता अहान पांडेय और अभिनेत्री अनीत पड्डा को अपने नए प्रचार अभियानों का चेहरा बनाया है। कंपनी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य युवाओं के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करना है। कंपनी के अनुसार, दोनों कलाकार अपने स्वाभाविक अंदाज और लोकप्रियता के कारण नई पीढ़ी के बीच तेजी से पहचान बना रहे हैं और ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बदलती सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से तुरंत जुड़ जाती है। कंपनी ने कहा कि अहान पांडेय और अनीत पड्डा को पेप्सी परिवार में शामिल कर वह युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की अपनी परंपरा को जारी रख रही है, जो आज की पीढ़ी के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित कर सकती हैं। कंपनी में भारत और दक्षिण एशिया के पेय कारोबार के उपाध्यक्ष एवं महाप्रबंधक नितिन भंडारी ने कहा कि नया प्रचार अभियान पेप्सी की युवा ऊर्जा और जोश को दर्शाता है।

कवि–गीतकार वैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

चेन्नई, (भाषा) तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वह तीसरे तमिल लेखक होंगे जिन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वैरामुथु (72) से पहले 1975 में तमिल उपन्यासकार अकिलन और 2002 में जयकांतन (2002) को सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गीतकार को सम्मानित करने की घोषणा पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि उनकी मुलाकात कवि से दिन में हुई थी और खबर मिलने के कुछ ही समय बाद यह खबर पहुंची, जिससे उनकी मुलाकात की खुशी और बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैरामुथु को पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार की कविता में महारत हासिल है, तमिल साहित्य में अपने नवाचारों के लिए वास्तव में वे इस सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने कहा, ''अगर कलाइग्नार करुणानिधि आज जीवित होते, तो वह कवि को गले लगाकर उनका अभिनंदन करते। मैं उनकी जगह कवि को बधाई देता हूं। पूरा तमिलनाडु इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है।''

माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष, के पॉप स्टार ने गाया 'शिव तांडव स्तोत्रम', देखते ही देखते हुआ वायरल

साउथ कोरियन के–पॉप स्टार और रैपर औरा उर्फ पार्क मिन जून एक बार फिर चर्चा में हैं। बिग बॉस 17 में बतौर वाइल्डकार्ड शामिल हुए औरा अब अपने नए गाने को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। औरा ने 'शिव तांडव स्त्रोत्रम' को एक अनोखे वर्जन में, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। बिग बॉस 17 के दौरान औरा ने अपने अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरी थीं और अब अपने नए गाने से फैंस का दिन बना दिया है। हाल ही में औरा ने ये म्यूजिक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह भारतीय आध्यात्म के सबसे पावरफुल 'शिव तांडव स्त्रोत्रम' पर परफॉर्म करते देखे जा सकते हैं और उनके इस अंदाज ने उनके भारतीय फैंस को भी हैरान कर दिया है।

जाने–माने पॉप स्टार हैं औराः औरा भले ही साउथ कोरियन पॉप स्टार हैं, लेकिन भारत में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इसी का नतीजा है कि उन्हें बिग बॉस सीजन 17 के लिए अप्रोच किया गया और उन्होंने रियेलिटी शो में हिस्सा भी लिया। इस शो ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया और अब उन्होंने 'शिव तांडव स्त्रोत्रम' पर परफॉर्म करते हुए अपने फैंस को हैरान कर दिया है। इस बार 'शिव तांडव स्त्रोत्रम' में औरा ने रैप का भी तड़का लगाया है, जो चर्चा का विषय बन चुका है।

फैंस हुए खुश और हैरानः म्यूजिक वीडियो में औरा अलग–अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष पहना औरा को परफॉर्म करते देखकर उनके फैंस हैरान भी हैं और बेहद खुश भी। कई का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह औरा का ये रूप भी देखेंगे। खास बात तो ये है कि साउथ कोरिया से होते हुए भी औरा ने संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण बिलकुल साफ किया है, जिससे उनके फैंस और भी खुश हैं। उन्होंने भारतीय आध्यात्म के इस सबसे ताकतवर मंत्र को ट्रेडिशनल टोन में गाया है और साथ ही रैप से जोड़ा है, जो यंग जनरेशन को बेहद पसंद आ रहा है।

भारत को लेकर जताया प्यारः औरा ने फरवरी में इस गाने की पहली झलक शेयर की थी, जो अब जाकर पॉपुलर हो रहा है। गाने में औरा बर्फ से ढके पहाड़ों में अलग–अलग गेटअप में दिखाई दिए। गाना शेयर करते हुए उन्होंने भारत को लेकर अपना प्यार भी जाहिर किया था। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उनका भारत को लेकर प्यार साफ झलकता है। अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह 3 साल से भी ज्यादा समय से भारत में हैं और बताया कि कैसे भारत ने उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और काम को लेकर उनके माइंडसेट को बदला है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि उन्हें भारत में रहने का मौका मिला, इसे लेकर वह बहुत ही खुश और ग्रेटफुल महसूस करते हैं।

फिल्म 'नया दौर' से प्रेरित नहीं है 'लगान' : गोवारिकर

मुंबई, (भाषा) फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने कहा कि उनकी फिल्म 'लगान' अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म 'नया दौर' से प्रेरित नहीं है बल्कि इसका विचार लोकप्रिय 'एस्टेरिक्स कॉमिक्स' से मिलता–जुलता है। आमिर खान अभिनीत यह फिल्म आशा, साहस और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जैसे विषयों पर आधारित है। इसकी कहानी मध्य भारत के एक छोटे से गांव के इर्द–गिर्द घूमती है जहां ब्रिटिश सेना का एक घमंडी अधिकारी भारी कर लगा देता है। इसके बाद गांव वालों को कर से राहत पाने के लिए क्रिकेट मैच खेलने की चुनौती दी जाती है। गोवारिकर ने कहा कि उनकी फिल्म 'लगान' अभिनेता दिलीप कुमार अभिनीत 'नया दौर' (1957) से प्रेरित नहीं है। बी आर चोपड़ा द्वारा निर्देशित 'नया दौर' की कहानी शंकर (दिलीप कुमार) नामक एक जोशीले तांगावाले के इर्द–गिर्द घूमती है जो ग्रामीण मजदूरों की आजीविका बचाने के लिए व्यापारी कुंदन के खिलाफ संघर्ष करता है। यह संघर्ष अंततः एक तांगा और बस के बीच रोमांचक दौड़ में बदल जाता है। गोवारिकर ने शुक्रवार शाम 'रेड लॉरी फिल्म महोत्सव' में 'लगान' के प्रदर्शन के बाद कहा, "यह एक मिथक है। मैं नया दौर से प्रेरित नहीं था और मैंने वह फिल्म देखी भी नहीं थी। मैं अपने बचपन की यादों के आधार पर यह कहानी लिख रहा था।" फिल्म 'लगान' इस साल जून में 25 वर्ष पूरे करेगी। निर्देशक ने बताया कि दिवंगत बीआर चोपड़ा को 'लगान' बहुत पसंद आई थी। गोवारिकर ने कहा कि जब उन्होंने बाद में 'नया दौर' फिल्म देखी तो दोनों फिल्मों में आधुनिकीकरण से निपटने के तरीकों में समानताएं दिखाई दीं। फिल्म निर्माता का कहना था कि उनकी फिल्म 'लगान' एक फ्रांसीसी कॉमिक श्रृंखला से अधिक मेल खाती है। उन्होंने कहा, "एस्टेरिक्स ही हमारी मुख्य प्रेरणा थी क्योंकि इसमें एक छोटा सा गांव, रोमन साम्राज्य से लड़ता है और यहां (फिल्म में) एक छोटा भारतीय गांव ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष करता है। इसी वजह से फिल्म ने फ्रांस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।" फ्रांसीसी कॉमिक श्रृंखला 'एस्टेरिक्स' एक गॉलिश गांव की कहानी है जो शक्ति बढ़ाने वाली जादुई औषधि की मदद से जूलियस सीजर की रोमन सेना का विरोध करता है। फिल्म 'लगान' में ग्रेसी सिंह, रेचल शेली, सुहासिनी मुले, कुलभूषण खरबंदा सहित कई कलाकारों ने काम किया है।

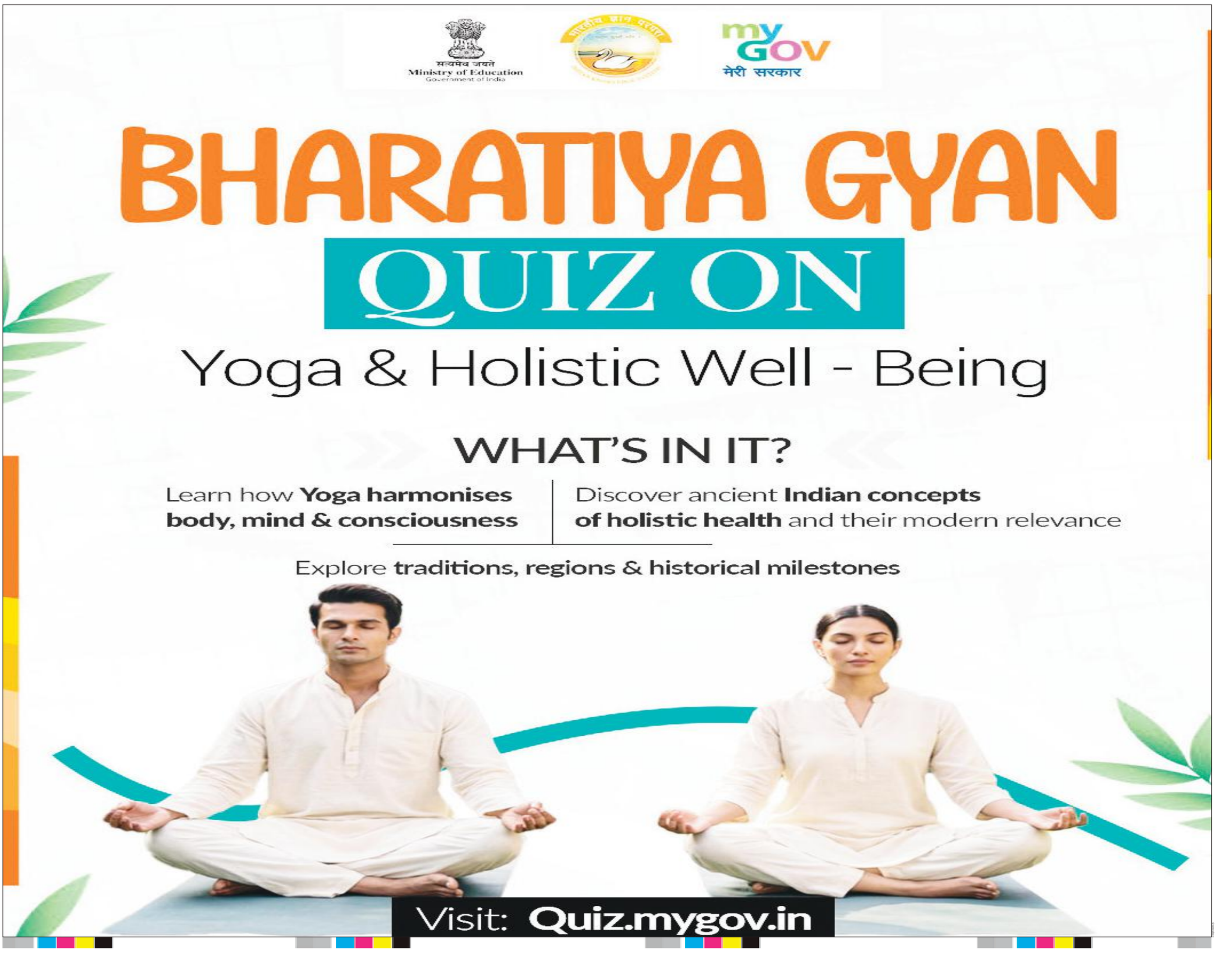

विभाजनकारी शक्तियों के विरुद्ध एकता के लिए काम करें : होसबाले का आह्वान

नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने समाज और देश में एकता का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि कई विभाजनकारी ताकतें वर्ग और जाति के आधार पर समाज के मानस को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। होसबाले ने संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत में ''संतों की गौरवशाली परंपरा'' में उनका एक विशिष्ट स्थान है। आरएसएस के दूसरे शीर्ष नेता ने कहा कि संत रविदास ने जन्म आधारित भेदभाव को खारिज करते हुए कर्मों को ही महानता का एकमात्र आधार माना। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने रूढ़ियों और अप्रचलित रीति–रिवाजों से मुक्ति दिलाने, अप्रासंगिक परंपराओं को त्यागने और बदलते समय के अनुरूप सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सामाजिक विमर्श को आकार देने में ''ऐतिहासिक भूमिका'' निभाई। होसबाले ने कहा, ''वर्तमान समय में, जब कई विभाजनकारी ताकतें वर्ग और जाति के आधार पर समाज के मानस को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तब हम सभी को पूज्य संत रविदास जी के जीवन संदेश के सार को समझते हुए समाज और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करने का संकल्प लेना चाहिए।'' आरएसएस नेता ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को आकार देने में संत परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसने न केवल भक्ति और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि विदेशी शासकों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के लिए समाज को जागृत और तैयार भी किया है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने रविदास को इस्लाम स्वीकार कराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे और उनमें से कई बाद में उनके शिष्य बन गए। होसबाले ने हरियाणा के समालखा स्थित माधव सृष्टि में कहा, ''संत रविदास जी को इस्लाम में परिवर्तित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन संत रविदास जी की भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को देखकर, जो लोग उनका धर्मांतरण कराना चाहते थे, वे उनके शिष्य बन गए।'' समालखा में 13 से 15 मार्च तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आरएसएस नेता ने रेखांकित किया कि संत रविदास का जीवन श्रम की गरिमा और नैतिक आचरण का प्रतीक था। होसबाले ने कहा, ''उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समाज में श्रम की गरिमा और शुद्ध, सदाचारी और पारदर्शी आचरण को पुनः स्थापित किया।'' उन्होंने कहा कि संत रविदास की महानता को उनकी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वीकार किया गया था और मीराबाई सहित कई प्रमुख हस्तियां उन्हें अपना गुरु मानती थीं।

'समृद्धि यात्रा' के दौरान नीतीश ने बेगुसराय, शेखपुरा में 480 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरूआत की

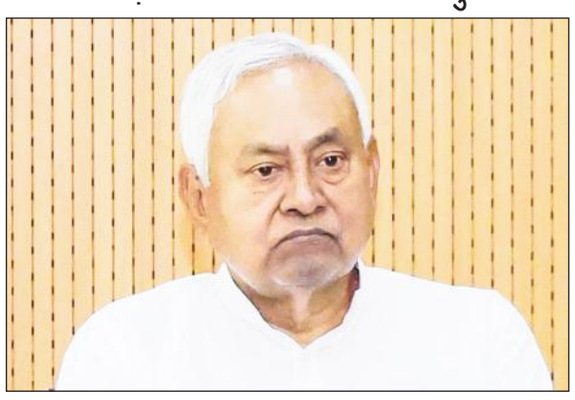

बेगूसराय/शेखपुरा, (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दौरान बेगुसराय और शेखपुरा जिलों में लगभग 480 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं और योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों में जारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, "मुख्यमंत्री ने बेगूसराय में 274 करोड़ रुपये की 400 से अधिक विकास परियोजनाओं/योजनाओं की शुरुआत की। इसमें 165 करोड़ रुपये की 211 परियोजनाओं/योजनाओं का उद्घाटन और 109 करोड़ रुपये की 189 परियोजनाओं/योजनाओं की आधारशिला रखी गई।" मुख्यमंत्री ने बेगूसराय में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह काम तय समय सीमा के भीतर पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल पूरा होने के बाद आसपास के लोगों को बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। नीतीश कुमार ने बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री के बेगुसराय पहुंचने से पहले हेलीपैड पर एक आवारा सांड घुमता दिखा दिया। इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुरक्षा के इंतजाम होने के बावजूद जानवर किसी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया, जिससे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों में अफरा–तफरी मच गई। घटनास्थल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन सांड ने एक पुलिसकर्मी का पीछा करना शुरू कर दिया। बेगूसराय के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह किसी भी तरह की सुरक्षा चूक नहीं है, जैसा कुछ खबरों में बताया जा रहा है। यह पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। जानवर उस क्षेत्र में आया जो हेलिपैड या कार्यक्रम स्थल के पास नहीं था।

कर्नाटक में वन एवं राजस्व भूमि चिन्हित करने के लिए एसआईटी गठित की जाएगी: बैरे गौड़ा

मंगलुरु (कर्नाटक), (भाषा) कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बैरे गौड़ा ने शनिवार को कहा कि वन एवं राजस्व भूमि की पहचान करने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में ऐस जमीन की पहचान कर रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलुरु के नजदीक मुलकी तालुक प्रशासनिक केंद्र "प्रजा सभा" का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि वन एवं राजस्व भूमि के वर्गीकरण का मुद्दा लंबे समय से लंबित रहने के कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सरकार प्राथमिकता के आधार पर इसका हल करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को दी गयी जमीनों में वन एवं राजस्व भूमि की हदबंदी के लिए संयुक्त सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। गौड़ा ने कहा कि कई किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पूर्व में उन्हें दी गई जमीन का औपचारिक रूप से मानचित्रण नहीं किया गया था, अब सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है। मंत्री ने कहा कि 2018 और 2023 के बीच इस जिले में 1,948 लाभार्थियों के लिए मानचित्रण पूरा किया गया था, जबकि पिछले दो वर्षों में 1–5 स्कीम के तहत 60,943 लाभार्थियों के लिए मानचित्रण किया गया। उन्होंने कहा कि ई–पोथी अभियान के तहत करीब 60,000 कानूनी वारिसों को भूमि अभिलेखों में परिवर्तन का अधिकार दिया गया है जिनमें पहले मृत व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। गौड़ा ने कहा कि तालुक प्रशासनिक कार्यालय का नाम प्रजा सभा इसलिए रखा गया है ताकि शासन लोगों के करीब आ सके। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि इस जिले में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में राज्य के बजट में इस जिले के लिए एक वैश्विक क्षमता केंद्र की घोषणा की गई है और इसे लागू करने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 'वेनलॉक' जिला अस्पताल में एक नए ओपीडी खंड के लिए 70 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि मूदबिदरी, बंतवाल, विटला और बेलथांगडी में तालुक अस्पतालों में सेवाएं सुधारने के लिए तीन निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ बातचीत चल रही है। लोकसभा सदस्य बृजेश चौटा ने राजस्व मंत्री से पुत्तुर, सुलिया, कडाबा और बेलथांगडी तालुकों में वन एवं राजस्व भूमि के मुद्दे हल करने का अनुरोध किया।

आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बदलाव की जरूरत: संसदीय समिति

नयी दिल्ली, (भाषा) संसद की एक समिति ने आयकर विभाग से उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने से पहले कर विवाद के मामलों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ मुकदमा समिति गठित करने को कहा है। समिति ने मुकदमेबाजी के प्रति विभाग के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव का आह्वान भी किया है। वित्त मामलों की स्थायी समिति ने 2024–25 में उच्च न्यायालय के स्तर पर आयकर विभाग की सफलता दर महज 12.07 प्रतिशत और आईटीएटी स्तर पर 14.50 प्रतिशत रहने पर चिंता जताई है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि बार–बार आने वाले प्रतिकूल परिणाम प्रणालीगत कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ''इसलिए केवल यांत्रिक तरीके से अपील दायर करने के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है... अक्सर व्यक्तिगत जिम्मेदारी या सतर्कता जांच से बचने के लिए ऐसा किया जाता है।'' आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 तक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष 3.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विवादित राशि वाले 23,230 मामले लंबित हैं। इसी तरह, उच्च न्यायालय में 5.65 लाख करोड़ रुपये के 41,321 मामले और उच्चतम न्यायालय में 25,403 करोड़ रुपये की मांग वाले 6,880 मामले लंबित हैं। कर विभाग ने समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति में कहा था कि वह मुकदमेबाजी को ''राजस्व के हितों की रक्षा के सिद्धांतों को बनाए रखने'' के उपाय के रूप में देखता है। हालांकि, समिति ने कहा कि कानूनी रूप से कमजोर अपीलों को जारी रखने से मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत के माध्यम से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है और न्यायिक बुनियादी ढांचे में बाधा आती है।

युद्धों को रोकने में नाकाम होती विश्व व्यवस्था

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया ने युद्धों से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया था । अपनी स्थापना की शुरुआत में ये संगठन कुछ हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा था। वास्तव में यह शांति इस संगठन की वजह से नहीं थी बल्कि दो शक्तिशाली वैश्विक ध्रुवों के कारण थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो सुपर पावर बन कर सामने आए। धीरे–धीरे विश्व इन दोनों शक्ति केंद्रों में बंट गया जिसके बाद इनके बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ लेकिन एक संघर्ष चलता रहा जिसे दुनिया शीत–युद्ध के नाम से जानती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका और सोवियत संघ के कारण एक संतुलन बना रहा लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र विश्वशक्ति बन गया। तब से लेकर अमेरिका पूरी दुनिया को अपने तरीके से चला रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश मिलकर पूरी वैश्विक व्यवस्था को चला रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने लगा है। देखा जाए तो बात केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की भी नहीं है, अमेरिका ने लगभग विश्व की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इसके कारण ही कई देशों ने अलग से अंतरराष्ट्रीय संगठन और मंचो का निर्माण किया है। विभिन्न देशों द्वारा यूएनओ के विकल्प के रूप में बनाये गए संगठन क्या अपनी कोई भूमिका वैश्विक व्यवस्था में निभा रहे हैं। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका–इजराइल और ईरान के युद्ध ने पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर दिया है । इस संकट के समय यूएनओ तो गायब है ही लेकिन दूसरे संगठन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट आने वाला है और सिर्फ इसका इंतजार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई वैश्विक व्यवस्था बची ही नहीं है, जिसकी जो मर्जी है, वो कर रहा है। दोनों पक्ष अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका दुनिया पर क्या असर होगा, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो दुनिया एक जंगल बन चुकी है, 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली व्यवस्था काम कर रही है। अगर अन्य संगठनों की बात करें तो मुख्य रूप से ब्रिक्स, एससीओ, जी–20 और ओआईसी ताकतवर संगठनों के रूप में सामने आते हैं। इस युद्ध को रोकने की बात तो दूर, इससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की कोशिश भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है।

ब्रिक्स और एससीओ में रूस, चीन और भारत जैसी बड़ी शक्तियां शामिल हैं लेकिन युद्ध को रोकने के लिए दोनों मंचो से कोई आवाज नहीं आयी है। जी–20 देशों में तो लगभग सभी शक्तिशाली देश शामिल हैं लेकिन वो भी चुप है। सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग पूरा मिडल ईस्ट खतरे में आ गया है लेकिन ओआईसी की एक बैठक तक बुलाई नहीं गयी है । जब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब तक तो इस संगठन का चुप रहना समझ आता था, लेकिन इस युद्ध ने जो रूप ले लिया है, इसके बाद भी ये संगठन निष्क्रिय है, ये समझना बहुत मुश्किल है। इस संगठन में दुनिया के लगभग सभी मुस्लिम देश शामिल हैं लेकिन इन्होंने खामनेई और उनके सहयोगियों की हत्या का विरोध नहीं किया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध अमेरिका और इजराइल से ज्यादा अरब देशों के खिलाफ हो गया है। ईरान अरब देशों की अर्थव्यवस्था खत्म करने में लगा हुआ है । जब तक ईरान अरब देशों के अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रहा था, तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब ईरान इन देशों के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है, ऐसे में ओआईसी का चुप रहना अचंभित करता है। जिस तरह से ईरानी नेतृत्व क्रूड ऑयल का दाम 200 डॉलर तक ले जाने का दावा कर रहा है, ये मुस्लिम देशों की बड़ी समस्या बन जाएगा। ईरान की रणनीति अमेरिका को झुकाने की है. वो अपनी जगह सही हो सकता है लेकिन इसके असर से दुनिया में आने वाली बर्बादी से कौन तबाह होगा, इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। ओआईसी मुस्लिम हितों के लिए बनाया गया संगठन है और इस युद्ध से मुस्लिम हितों को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। वास्तव में मुस्लिम नेतृत्व ज्यादातर अमेरिका के पक्ष में है लेकिन मुस्लिम समुदाय ईरान के पक्ष में है। इसकी वजह यह है कि ईरान पर हमला किया गया है, इसलिए वो पीड़ित दिखाई दे रहा है। ईरान जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, उससे पूरे मुस्लिम समुदाय में गर्व की भावना पैदा हो गई है। अमेरिका के झुकने से मुस्लिम समुदाय को आत्मिक शांति मिल सकती है, लेकिन तेल की कमी से पैदा होने वाली समस्याओं की मार सबसे गरीब देशों पर पड़ने वाली है और ज्यादातर मुस्लिम देश पहले ही गरीबी की मार झेल रहे हैं। यूएनओ धीरे–धीरे अपना महत्व खोता जा रहा है क्योंकि वहां वही होता है, जो अमेरिका चाहता है लेकिन इसके विकल्प में बने संगठनों का क्या महत्व रह गया है। क्या ये संगठन सिर्फ बड़े–बड़े आयोजन करने के लिए ही हैं, या जमीन पर भी कुछ असर है। इस युद्ध की मार पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है, इसलिए सबको अपना काम करना चाहिए। ब्रिक्स और एससीओ में चीन और रूस शामिल हैं, ये दोनों अपने प्रभाव का इस्तेमाल ईरान को रोकने में कर सकते हैं, वैसे भी ईरान इनका सहयोगी देश है। इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप में चीन और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है । ईरान की रक्षा करने तक तो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह से अन्य देशों को इस युद्ध में घसीट रहा है, उसे तो रोका जाना चाहिए । बेशक अमेरिका से रूस और चीन की दुश्मनी हो, लेकिन अरब देशों के साथ तो ऐसा नहीं है। तेल महंगा होने से रूस को तो फायदा होगा लेकिन चीन के लिए तो ये बड़ी समस्या होने वाली है। अगर एससीओ, ब्रिक्स और ओआईसी मिलकर काम करें तो ईरान और अरब देशों को इस युद्ध से होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश की जा सकती है । ईरान ने अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी है, लेकिन वो खुद भी बर्बाद हो रहा है। कुछ भी हो जाये, ईरान युद्ध जीतने वाला नहीं है. वो सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान अमेरिकी हितों पर चोट कर सकता है. लेकिन अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। ईरान ने हेम्ब्रुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है जिससे दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। इस संकट की मार अमेरिका और इजराइल से ज्यादा भारत, चीन और दूसरे देशों पर पड़ने वाली है। तेल की कमी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है. ये पूरी दुनिया में होने वाला है। देखा जाए तो ये युद्ध सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान का नहीं रह गया है, ये पूरी दुनिया का युद्ध बन चुका है। अमेरिका को हम कितना भी कोस ले, लेकिन इससे समस्या खत्म होने वाली नहीं है।

ब्रिक्स, एससीओ और ओआईसी आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी मंच हैं, इसलिए इनसे सैन्य दखल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इन संगठनों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव नहीं है, इसलिए इनका चुप रहना सही नहीं है। इन्हें कम से कम इस युद्ध पर अपनी राय तो रखनी चाहिए। ये कम से कम यह मांग तो रख सकते हैं कि इस युद्ध के कारण दूसरे देशों को कम से कम परेशानी हो। अमेरिका की गलतियों की सजा पूरी दुनिया को नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रयास किये जाने की जरूरत है। अमेरिकी व्यवस्था के विकल्प के रूप में अस्तित्व में आए संगठन अगर कुछ नहीं करते हैं तो उनके होने का क्या मतलब है । इन संगठनों के निर्माण कोई मतलब नहीं है, अगर ये इस युद्ध में निरपेक्ष बने रहते हैं । एससीओ के सदस्यों पर इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर होने वाला है, ऐसे में भी ये संगठन कुछ नहीं कर पाता है तो फिर इसका फायदा क्या है। जब ये युद्ध अरब बनाम ईरान बनता जा रहा है तो ओआईसी के होने का क्या मतलब है। इजराइल के अलावा इस युद्ध से ईरान और अरब देशों को नुकसान हो रहा है, इसलिए ये मामला पूरी तरह से मुस्लिम हितों का बन गया है। इसके अलावा इस युद्ध की भारी कीमत गरीब मुस्लिम देशों को चुकानी पड़ेगी, इसलिए ये मुद्दा मुस्लिम हितों से जुड़ गया है। ऐसे में ओआईसी का कुछ न कर पाना , उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से निकल जाए क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल रुक जाएंगे। दोनों देशों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये रुकने वाले हैं। देखा जाए तो सबको प्रयास करने की जरूरत है कि इस युद्ध को यहीं खत्म कर दिया जाए। ईरान को समझना होगा कि वो इजराइल को खत्म नहीं कर सकता। इजराइल एक परमाणु शक्ति है. अस्तित्व पर संकट आने पर वो परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। इजराइल को समझना होगा कि वो ईरान का जितना नुकसान कर सकता है, वो कर चुका है. अब केवल आम जनता को निशाना बना सकता है। अगर ये संगठन प्रयास करें तो दोनों पक्षों को पीछे हटने के लिए मनाया जा सकता है। दोनों ही पक्षों को इस युद्ध में अपूरणीय क्षति पहुँच रही है। ऐसे में कोशिश करने से मामला खत्म हो सकता है।

राजेश कुमार पासी

जितनी जल्दी अमेरिका, भारत के कूटनीतिक संदेशों को समझ लेगा, उसकी तिलमिलाहट दूर हो जाएगी!

वैश्विक सम्बन्धों को नया आयाम देने वाले रायसीना डायलॉग 2026 में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के एक बेबाक से अब यह बात साफ हो चुकी है कि जब भारत के दोस्त अमेरिका जैसे हों, तो उसे बर्बाद होने के लिए चीन जैसे आस्तीन के सांपों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब शायद यूरोप और रूस मिलकर भी भारत को न बचा पाएं। ऐसा इसलिए कि जो जहर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देशों के दिलोदिमाग में भरा हुआ है, उससे न तो ब्रिटेन का कल्याण हुआ, न ही अमेरिका का होगा। हां, इनकी क्षुद्र चालों से भारतीय उपमहाद्वीप और अरब–खाड़ी देशों में भयंकर धार्मिक कलह पैदा होगी। हालांकि भारत सरकार भी इन विदेशों हरामखोर चालों से सावधान है और जो जवाबी कूटनीतिक मोर्चेबंदी करती जा रही है, वैसी बानगी अतीत में कभी नहीं दिखती। इसलिए भारत का भविष्य उज्ज्वल है। वह वीर भोग्या वसुंधरा की तर्ज पर वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवंतु सुखिनः की राह पर अग्रसर है। समकालीन कलह के लिए अमेरिका–यूरोप की साम्राज्यवादी शह–मात के खेल जिम्मेदार हैं। इसमें जिस तरह से अरब व खाड़ी देश पिस रहे हैं, यूक्रेन से लेकर ईरान तक बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है, वह भारतीय कूटनीति के लिए एक अलग ही चुनौती पैदा करती जा रही है। लेकिन हमारी जेन–जेड पीढ़ी इतनी जांबाज और कार्यकुशल है कि निकट भविष्य में एक मजबूत भारत का डंका पीट देगी और दुनिया के मुल्क देखते रह जाएंगे। कहना न होगा कि जिस तरह से रायसीना डायलॉग 2026 में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि अमेरिका, भारत को चीन जैसी आर्थिक सुविधाएं नहीं देगा, क्योंकि इससे चीन प्रतिद्वंद्वी बन गया। उनका तातपर्य यह कि चीन के अभूतपूर्व विकास का दंश झेल रहा अमेरिका अब यह कभी नहीं चाहेगा कि भारत भी उसी वैश्विक स्थिति को प्राप्त करे। हालांकि, हमारे दिग्गजविदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका तगड़ा जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भारत का उदय (अभ्युदय) अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं से होगा, न कि दूसरों की गलतियों पर निर्भर रहकर। इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक बयानबाजी में नहले पर दहले की तरह लिया गया और इसपर गंभीर बहस छिड़ी हुई है। अमेरिकी उपविदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने रायसीना संवाद में चेतावनी दी कि अमेरिका भारत को वह आर्थिक लाभ नहीं देगा जो उसने चीन को दिए थे, क्योंकि इससे चीन वैश्विक प्रतिद्वंद्वी बन गया। उनका यह बयान भारत–अमेरिका आर्थिक संबंधों पर सवाल उठाता प्रतीत होता है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके ईर्ष्यालु बयान के दो दिन बाद दो टूक शब्दों में साफ–साफ कहा कि, "देशों का उत्थान खुद तय होता है। भारत का उदय हमारी ताकत से निर्धारित होगा, न कि दूसरों की गलतियों से।" उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया, और इशारा किया कि यहां सहयोग करने वालों को ही अधिक लाभ मिलेगा। यह वैचारिक घटना मार्च 2026 के रायसीना डायलॉग से जुड़ी है, जहां जयशंकर ने भारत की स्वतंत्र नीतियों को रेखांकित किया। यह रूस, चीन, यूरोपीय–संघ, अरब–खाड़ी देशों, जापान–कोरिया, आशियान देशों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के देशों, दक्षिण अमेरिका के देशों और कनाडा आदि को वह बेवाक कूटनीतिक संदेश है जो वैश्विक संघर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रभुत्वशाली देश भारत के अंतरराष्ट्रीय महत्व को उजागर करता है। अमेरिका जैसे देश भारत की गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की अडिग नीति बौखलाहट दिखा रहे हैं, जो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसा इसलिए कि रायसीना डायलॉग 2026 में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के बयान पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत का उदय अपनी आंतरिक शक्ति से होगा। उन्होंने कहा कि देशों का उत्थान खुद तय होता है, न कि दूसरों की गलतियों पर निर्भर। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाएगा, जहां सहयोग करने वालों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने अमेरिकी चेतावनी को खारिज करते हुए भारत की स्वतंत्र क्षमताओं पर भरोसा जताया। यह जवाब रायसीना डायलॉग के सत्रों के दौरान आया, जहां जयशंकर ने वैश्विक साझेदारियों पर भारत की रणनीति रेखांकित की। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2025 में रूस यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक शब्दों में अमेरिकी विदेश नीति को "पेरप्लेक्सेड"/ (कन्फ्यूजिंग या समझ से परे) कहा। इसका कारण स्पष्ट करते हुए जयशंकर ने बताया कि अमेरिका ने पहले भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रहे। लेकिन बाद में उसी रूसी तेल खरीद पर भारत पर टैरिफ लगाने की नीति अपना ली, जो विरोधाभासी लगती है। इसलिए अतिरिक्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने जोर दिया कि भारत न तो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है (क्योंकि ऐसा चीन है) और न ही एलएनजी (स्छळ) का (क्योंकि ऐसे यूरोपीय देश हैं), फिर भी भारत पर विशेष रूप से टारगेट क्यों? यह अमेरिकी नीति उनकी समझ से बाहर थी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत के प्रति अमेरिका का नजरिया पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन व्यापार, भू–राजनीति और घरेलू नीतियों पर मतभेद तनाव पैदा करते हैं। इससे व्यापारिक विवाद पैदा होते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत के रूसी तेल खरीद पर जो 25% टैरिफ लगाया था, उसे भारत ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। चूंकि अमेरिका भारत से डेयरी और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने की मांग करता रहा है, लेकिन भारत ने अपने स्थानीय हितों की रक्षा की है, इसलिए अमेरिकी बौखलाहट स्वाभाविक है। जहां तक भू–राजनीतिक मतभेद की बात है तो भारत के रूस और ईरान से रक्षा व ऊर्जा संबंध अमेरिका को चिंतित करते हैं, जिसके कारण प्रतिबंधों की धमकियां दी गईं। वहीं ऐतिहासिक रूप से 1974–98 के परमाणु परीक्षणों पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। उसकी मानवाधिकार चिंताएं भी गैरवाजिब हैं क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट्स में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, पत्रकारों और असहमतियों पर 'गंभीर उल्लंघन' की आलोचना की गई। वहीं खालिस्तानी मुद्दे और आंतरिक राजनीति पर भी बयानबाजी ने तनाव बढ़ाया। इससे अमेरिका को कुछ नहीं हासिल होने वाला है क्योंकि उसके यूरोपीय मित्र तक उससे दूर जाने की राह तलाश रहे हैं। भारत–यूरोपीय संघ के नजदीक आने की एक वजह यह भी है। इसकी खिसियाहट में अमेरिका ने बेनेजुएला और ईरान के राष्ट्रपतियों के साथ जो सुलूक किए, उससे उसकी वैश्विक दबंगई भले बढ़ी, लेकिन भारत में एक कहावत है कि हर गुंडा 12 वर्षों के उत्पात के बाद मारा जाता है। शायद रूस–चीन का शह पाकर मुस्लिम देशों का संघ ओआईसी भी अमेरिका के साथ कुछ यही करें। यह उसके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी और इससे यूरोपीय वैभव लौट सकता है। भारत के लिए यह न तो सुखद न ही दुःखद स्थिति होगी। **कमलेश पांडेय**

अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों पर बमबारी की: ट्रंप

दुबई, (एपी) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण एक द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को शुक्रवार को नष्ट कर दिया और चेतावनी दी कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन में हस्तक्षेप करना जारी रखता है तो इसके बाद उसकी तेल अवसंरचना को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान के खार्ग द्वीप पर स्थित ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। खार्ग द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का मुख्य टर्मिनल स्थित है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा था कि यदि ऐसा हमला किया गया तो ईरान की ओर से और भी बड़े स्तर की जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध के लगभग दो सप्ताह बाद पश्चिम एशिया में 2,500 और मरीन एवं एक युद्धपोत भेजा जा रहा है। ईरान इजराइल और पड़ोसी खाड़ी देशों को निशाना बनाकर आक्रामक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है जिससे दुनिया के तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है। वहीं, अमेरिकी और इजराइली युद्धक विमान समूचे ईरान में सैन्य और अन्य लक्ष्यों पर बमबारी कर रहे हैं। लेबनान में मानवीय संकट और गहरा गया है। लेबनान में हमले में लगभग 800 लोग मारे गए हैं और 850,000 लोग विस्थापित हुए हैं क्योंकि इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्ला चरमपंथियों के खिलाफ हमले शुरू किए हैं और चेतावनी दी है कि कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन फिलहाल उसके तेल बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन ट्रंप चेतावनी दी कि अगर ईरान या कोई और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन में बाधा डालता है, तो वह तेल बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलीबाफ ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी कि ईरान की दक्षिणी समुद्री सीमा पर स्थित द्वीपों पर अगर हमले हुए तो ईरान ''संयम नहीं बरतेगा''। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये द्वीप देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

शनिवार को, ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने अपनी इस धमकी को दोहराया कि यदि इस्लामी गणराज्य पर हमला हुआ तो वह क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े तेल और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करेगा। खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने चेतावनी दी कि वे ''क्षेत्र भर में उन सभी तेल, आर्थिक और ऊर्जा अवसंरचनाओं को निशाना बनाएंगे जो अमेरिकी हिस्सेदारी वाली या अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली तेल कंपनियों से संबंधित हैं।'' ईरान की अर्द्धसरकारी 'फार्स' समाचार एजेंसी ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी हमलों से द्वीप पर तेल अवसंरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। समाचार एजेंसी ने बताया कि हमलों के बाद कम से कम 15 विस्फोट हुए, जिनमें एक वायु रक्षा केंद्र, एक नौसैनिक अड्डा, हवाई अड्डे का नियंत्रण टावर और एक अपतटीय तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर हैंगर शामिल था। ईरान की राजधानी में शुक्रवार को एक भीषण विस्फोट हुआ जिससे शहर के केंद्रीय चौक को हिला कर रख दिया। विस्फोट के दौरान वहां हजारों लोग फलस्तीनियों के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक रैली में एकत्रित हुए थे। इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वह मध्य तेहरान के इस इलाके को निशाना बनाएगा।विस्फोट में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि बाद में कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदर्शन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। ईरान ने इजराइल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर व्यापक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित कर दिया है। 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरान सरकार को गिराए जाने के सवाल पर संयमित रुख अपनाते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास हथियार नहीं हैं, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती है।'' उन्होंने ईरान के अर्द्धसैनिक बल बासिज का उदाहरण दिया जिसने हाल में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इजराइल-लेबनान के बीच सीधी वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार : फ्रांस

पेरिस, (एपी) फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के स्पीकर से बात की है, और देश को अराजकता में डूबने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। मैक्रों ने कहा कि हिजबुल्ला को तुरंत 'अपनी आक्रामकता' रोकनी चाहिए जबकि इजराइल को बड़े पैमाने पर अपने हवाई हमलों को रोकना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति के मुताबिक लेबनानी नेताओं ने कहा है कि वे इजराइल के साथ सीधी वार्ता करने को तैयार हैं। मैक्रों ने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे युद्धविराम तक पहुंचने के लिए बातचीत शुरू कर सकें, एक स्थायी समाधान ढूंढ सकें और लेबनान की संप्रभुता के समर्थन में लेबनानी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर प्रदान कर सकें। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ बातचीत करने की तत्परता व्यक्त की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। लेबनान और इजराइल 1948 से ही युद्धरत हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद श्रीलंका में ईंधन आपूर्ति बनी रहेगी: एलआईओसी

कोलंबो, श्रीलंका में लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (एलआईओसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद देश में ईंधन की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। यह बयान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरथ द्वारा अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए किए गए अनुरोध के बाद आया। हेरथ ने इस विषय पर छह मार्च को भारत दौरे के दौरान जयशंकर से चर्चा की थी। शनिवार को यहां प्रबंधन छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए एलआईओसी के प्रबंध निदेशक के रघु ने कहा, "लंका आईओसी के प्रबंध निदेशक के रूप में मैं केवल लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप सभी सुरक्षित हाथों में हैं।" रघु ने कहा, "स्थिति पूरी तरह से सुखद नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि आप सभी सुरक्षित हैं। कंपनियां और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि एलआईओसी श्रीलंका की प्रगति के लिए ईंधन प्रदान करना जारी रखेगी।

उत्तर कोरिया ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए समुद्र की ओर लगभग 10 मिसाइल दागीं

सियोल, (एपी) अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शनिवार को पूर्वी सागर की ओर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागीं। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। दक्षिण कोरिया के 'ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' ने कहा कि मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के निकटवर्ती क्षेत्र से दागी गईं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कितनी दूर तक गईं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हथियार देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर के जलक्षेत्र में गिरे। दक्षिण कोरिया के 'ज्वाइंट चीफ्स' ने कहा कि सेना ने निगरानी बढ़ा दी है और संभावित अतिरिक्त हमलों के खिलाफ तत्परता बनाए रखी है तथा वह अमेरिका एवं जापान के साथ जानकारी साझा कर रही है। यह प्रक्षेपण ऐसे समय में किया गया है, जब उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का जवाब देने की हाल में धमकी दी थी।

सरकार ने रोल्टा इंडिया के लिए अशडन प्रॉपर्टीज की 900 करोड़ रुपये की समाधान योजना को चुनौती दी

नयी दिल्ली, (भाषा) सरकार ने कर्ज में डूबी कंपनी रोल्टा इंडिया के लिए अशडन प्रॉपर्टीज द्वारा पेश की गई 900 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील दायर की है। स्वीकृत समाधान योजना को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी और नियामकीय संस्थाओं के लिए मात्र 10 लाख रुपये ही आवंटित किए गए हैं, जबकि ऋणग्रस्त कंपनी रोल्टा इंडिया का कुल बकाया 5,949.95 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार के वकील शशांक बाजपेयी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के माध्यम से प्रस्तुत, 179.19 करोड़ रुपये के मान्यता प्राप्त सरकारी और वैधानिक दावों के मुकाबले, केवल 10 लाख रुपये का आवंटन मात्र 0.06 प्रतिशत की नगण्य वसूली के बराबर है। दूरसंचार विभाग ने 2005-06 और 2006-07 के लिए लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाने को लेकर 469.09 करोड़ रुपये का दावा रोल्टा इंडिया के खिलाफ दायर किया था। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 15 दिसंबर, 2025 को एशडन प्रॉपर्टीज द्वारा प्रस्तुत 900 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिसे सरकार ने "गंभीर अन्याय" और "कानूनी रूप से अस्वीकार्य" करार दिया है।

भारत का कच्चे तेल का टैंकर यूएई के फुजैराह से सुरक्षित निकला

नयी दिल्ली, (भाषा) तेल टर्मिनल पर हमले के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह से तेल भरने के बाद भारतीय ध्वज वाला कच्चे तेल का एक टैंकर सुरक्षित निकल गया है। सरकार ने रविवार एक अद्यतन सूचना में कहा कि वह पश्चिम एशिया में स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है और स्थिर ईंधन आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। 'जग लाडकी' नाम का यह जहाज, जिसमें लगभग 80,800 टन मुरबन कच्चा तेल है, फुजैराह से भारतीय समय के अनुसार 10.30 बजे निकला और इस पर सवार सभी सदस्य सुरक्षित हैं, और अब यह भारत के लिए रवाना हो गया है। 'जग लाडकी' चौथा भारतीय ध्वजवाहक जहाज है जो युद्ध क्षेत्र से बिना किसी नुकसान के बाहर निकला है। तैयारी के उपायों पर एक अद्यतन सूचना में सरकार ने कहा कि इसके अलावा, सुरक्षित रास्ता भारतीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में पोत परिवहन की दिक्कतों ने भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाला है। इसमें कहा गया, ''14 मार्च, 2026 को, जब भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लाडकी फुजैराह सिंगल पॉइंट मूरिंग पर कच्चा तेल भर रहा था, तो तेल टर्मिनल पर हमला हुआ। जहाज़ आज (रविवार) 10.30 बजे फुजैराह से लगभग 80,800 टन मुरबन कच्चा तेल लेकर सुरक्षित रूप से भारत के लिए रवाना हुआ।'' इसमें कहा गया है कि जहाज और उसमें सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। शनिवार को, दो भारतीय ध्वज वाले एलपीजी जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' – लगभग 92,712 टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गए। सूचना के अनुसार, शिवालिक 16 मार्च को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच. गा, और नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पर लंगर डालेगा। ये दोनों जहाज़ उन 24 जहाजों में शामिल थे जो इस क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे।

पश्चिमी इलाके पर 24 के अलावा, पूर्वी क्षेत्र में चार और जहाज फंसे हुए थे। पूर्वी इलाके में पर चार में से भारतीय ध्वज वाला तेल टैंकर जग प्रकाश, जो ओमान से अफ्रीका पेट्रोल ले जा रहा था, शुक्रवार को युद्ध प्रभावित इलाके को पार कर गया। जग प्रकाश ने ओमान के सोहर बंदरगाह से पेट्रोल लिया था और अब यह तंजानिया के टांगा जा रहा है। यह 21 मार्च को टांगा पहुंचने वाला है। सरकार ने कहा कि इस इलाके में काम कर रहे भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं, और समुद्री परिचालन पर करीब से नजर रखी जा रही है। अभी, फारस की खाड़ी इलाके के पश्चिम की ओर 22 भारतीय ध्व. जवाहक जहाज हैं जिन पर 611 नाविक हैं।

भारत अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 60 प्रतिशत एलपीजी ज़रूरतें आयात से पूरी करता है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले और जवाबी ईरानी कार्रवाई से पहले भारत का आधे से ज़्यादा कच्चा तेल आयात, लगभग 30 प्रतिशत गैस और 85-90 प्रतिशत एलपीजी आयात सऊदी अरब और यूएई जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता था। इस लड़ाई की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्यम बंद हो गया है, जो खाड़ी देशों की ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य रास्ता है। हालांकि, भारत ने रूस जैसे देशों से तेल मंगाकर कच्चे तेल की आपूर्ति में सुधार किया है, लेकिन औद्योगिक ग्राहकों को गैस आपूर्ति कम कर दी गई है। होटल और रेस्तरांओं के लिए भी एलपीजी में कमी की गई है। सरकार ने कहा है कि पोत परिवहन महानिदेशालय जहाज मालिकों, आरएसपीएल एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर स्थिति पर नज़र रख रहा है।

अदाणी पावर को महाराष्ट्र में 1,600 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए ठेका मिला

नयी दिल्ली, (भाषा) अदाणी पावर ने रविवार को बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) से 1,600 मेगावाट बिजली की आप. ूर्ति के लिए 'लेटर ऑफ अवार्ड' (एलओए) मिला है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित 25 वर्षीय बिजली आपूर्ति समझौते (पीएसए) के तहत आपूर्ति वित्त वर्ष 2030-31 से शुरू होगी। अदाणी पावर के सीईओ एस बी ख्यालिया ने बयान में कहा, ''एमएसईडीसीएल का यह एलओए अदाणी पावर की लागत संरचना की प्रति. स्पर्धात्मकता, भरोसेमंद बिजली प्रदान करने की हमारी क्षमता और दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से भारत की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' इसके साथ ही अदाणी पावर ने अब अपनी निर्माणाधीन 23.8 गीगावाट की क्षमता में से 13.3 गीगावाट के लिए दीर्घकालिक पीएसए (पीएसए) हासिल कर लिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने 10,400 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ पांच दीर्घकालिक पीएसए बोलियां जीती हैं।

श्रीलंका में ईंधन संकट से निपटने क्यूआर कोड से वितरण शुरू, कोटा लागू

कोलंबो, (भाषा) श्रीलंका ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण संभावित ईंधन संकट को देखते हुए क्यूआर कोड के माध्यम से ईंधन कोटा प्रणाली लागू कर दी है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, निजी कारों को प्रति सप्ताह 15 लीटर और बसों को 60 लीटर ईंधन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि क्यूआर कोड के माध्यम से ईंधन राशन प्रणाली इसलिए लागू की गई है क्योंकि पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने के बावजूद लोग भंडारण कर रहे थे। श्रीलंका सरकार ने इस सप्ताह यह भी घोषणा की थी कि वह भारत और रूस से ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने की उम्मीद कर रही है।

एयर इंडिया को पश्चिम एशिया संकट के बीच लंबी उड़ानों के लिए डीजीसीए से अस्थायी छूट

मुंबई, (भाषा) पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के कारण हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बीच विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया की लंबी दूरी की उड़ानों के लिए अस्थायी छूट दी है। सूत्रों ने जानकारी दी। पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के कारण एयर इंडिया अब यूरोप और अमेरिका जाने के लिए लंबा मार्ग अपनाकर उड़ानें संचालित कर रही है। सूत्रों के अनुसार, डीजीसीए ने पायलटों के उड़ान और कार्य समय सीमा में अस्थायी ढील दी है, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके तहत लंबी दूरी की उड़ानों में दो पायलटों के लिए उड़ान समय 11 घंटे 30 मिनट और कार्य अवधि 11 घंटे 45 मिनट तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, पायलटों के समय-सारणी में 30 मिनट की अतिरिक्त सुविधा की जरूरत को भी छूट दी गई है। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया की जेद्दा उड़ान में कार्य अवधि 11 घंटे 55 मिनट है, जो अनुमत सीमा से 10 मिनट अधिक है। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि उड़ान समय वह अवधि है जब विमान उड़ान भरने के लिए जमीन से उठकर सुरक्षित लैंडिंग तक चलता है। कार्य अवधि तब शुरू होती है जब पायलट अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है और तब खत्म होती है जब वह अंतिम उड़ान के इंजन बंद होने के बाद अपनी ड्यूटी समाप्त करता है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों में कटौती की है। डीजीसीए ने कहा कि यह छूट पायलटों की सुरक्षा और थकान को ध्यान में रखकर दी गई है, ताकि लंबा मार्ग अपनाने के बावजूद उड़ान संचालन सुरक्षित रूप से किया जा सके।

Department of Fisheries, Government of India will organize first of its kind National Conference on Cold water Fisheries in Srinagar

Srinagar, Focus News: The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries,Animal Husbandry And Dairying, Government of India, is organizing the National Conference on Cold Water Fisheries at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre (SKICC), Srinagar, Jammu & Kashmir on 14th March 2026. The event will be held under the guidance of Hon'ble Union Minister Shri Rajiv Ranjan Singh, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying (MoFAHD) and Panchayati Raj, in the august presence of Shri Manoj Sinha, Hon'ble Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir; Shri Omar Abdullah, Hon'ble Chief Minister, Jammu and Kashmir; Prof. S.P. Singh Baghel, Hon'ble MoS, MoFAHD, GoI; Shri George Kurian, Hon'ble MoS, MoFAHD, GoI; and Shri Javid Ahmad Dar, Hon'ble Minister, Agriculture Production Department, Jammu & Kashmir. This will be a first-of-its-kind national dialogue on sustainably harnessing the potential of India's Cold-Water Fisheries for growth and prosperity. India's Cold Water fisheries form a unique and valuable segment of the country's aquaculture landscape, thriving predominantly in the high-altitude regions of the Himalayas, parts of the Northeast, and select zones of the peninsular highlands. It is spread across Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim, and parts of the Western Ghats, North-east and peninsular regions, collectively covering over 5.33 lakh sq. km of mountainous terrain. This vast geography is enriched with pristine rivers, streams, lakes, and reservoirs, offering ideal ecological conditions for the growth and diversification of Cold Water fish species. With more than 278 identified Cold Water fish species, these ecosystems offer immense potential for livelihood generation, nutrition security, scientific aquaculture and biodiversity conservation. Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), the Department of Fisheries, Government of India has undertaken major initiatives to strengthen the Cold-Water fisheries segment. A dedicated investment of ₹2,299.56 crore has been sanctioned to Cold Water states to modernize infrastructure, expand hatcheries, enhance seed and feed systems, develop raceway facilities, strengthen transport and cold-chain networks, and support livelihood-oriented activities. These interventions are building the foundation for a modern, technology-driven Cold Water aquaculture ecosystem in India. During the Conference, Hon'ble Union Minister FAHD Shri Rajiv Ranjan Singh will release the "Model Guidelines for the Development of Cold Water Fisheries", distribute scheme benefits to Traditional and Progressive Cold-Water fishers, Fisheries Cooperatives under PM-MKSSY, and Kisan Credit Card beneficiaries along with awards distribution to the Best FFPOs and Best Fisheries Start-ups from Jammu & Kashmir. The Technical session will deliberate on key thematic areas including research and innovation, technology adoption, infrastructure expansion, institutional convergence and entrepreneurship development. The event aims to bring together policymakers, experts, researchers and stakeholders from Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka and Kerala to explore collaborative pathways for sectoral advancement.

By fostering knowledge exchange and aligning national and state priorities, the Conference seeks to accelerate sustainable growth in the Cold Water fisheries sector. India's premium Cold Water species such as Rainbow Trout, Brown Trout and Mahseer represent a high-value segment with significant growth potential. Targeted policy interventions have enabled trout production to grow nearly 1.8 times over the past decade. Yet India continues to import Salmon and premium Trout underscoring the need to expand domestic capacity. To address this, the Government of India has laid out the National Vision for Cold Water Fisheries 2030, which aims to double cold water fish production (such as Trout and Mahseer) and generate livelihood opportunities. In this context, the National Conference serves as a timely and strategic intervention, providing a vital platform for dialogue, partnership and roadmap development to accelerate Cold Water fisheries, enhance sustainable livelihoods and strengthen nutritional security in India's hilly and remote regions.

Background – Over the past decade, the Government of India has created a strong investment architecture to support fisheries across the country, including the Cold-Water regions. Beginning with the Blue Revolution scheme and followed by major national programs such as FIDF, PMMSY and PMMKSSY, an investment of over ₹39,272 crore has been envisaged, of which projects worth ₹34,266 crore have already been approved. Under PMMSY, the Department of Fisheries has approved 5,600 raceways, 54 hatcheries, 5,600 trout rearing units, 293 cold storages, 8,044 transport vehicles and 260 feed mills, these activities are directly benefiting the Cold Water Fish farmers and have significantly improved production and distribution networks across states. Along with these activities, Insurance support to 33.78 lakh fishermen and livelihood and nutritional support to 23.51 lakh families have been provided ensuring social security and resilience among mountain communities Among the twelve Integrated Aqua Parks (IAP) approved nationally, four IAPs, namely Anantnag in Kashmir, Udham Singh Nagar in Uttarakhand, Ziro in Arunachal Pradesh and Mokokchung in Nagaland, fall under Cold Water fisheries. Notably, the Aqua Parks provide state-of-the-art facilities support fisheries development and ensure end to end connectivity throughout the value chain. In addition, the Department of Fisheries, Government of India has notified Cold Water fisheries clusters including Jammu and Kashmir with Anantnag as the leading district, Uttarakhand with Pithoragarh as the leading district and Himachal Pradesh with Kullu as the leading district. In order to strengthen supply chain for inland and high-altitude aquaculture in the future, the Department of Fisheries, GoI is also integrating unmanned aerial vehicles into India's aquaculture logistics via Drone technology. A pilot has been conducted which demonstrated that drone transport can reduce spoilage, improve access to markets and significantly enhance farmer returns in remote and infrastructure deficient areas where conventional transport is slow or unreliable.

MSME Ministry Completes 364 MSE-CDP Projects; SFURTI Boosts Traditional Industry Clusters

New Delhi, Focus News: Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme (MSE-CDP) of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India establish Common Facility Centers (CFCs) and create/upgrade Infrastructure Facilities (ID Projects) providing financial support to enhance the productivity and competitiveness of Micro and Small Enterprises (MSEs) in the existing cluster. Total 606 projects have been approved since inception of the scheme out of which 242 projects are ongoing and 364 projects are completed. Under the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), significant progress has been made in promoting cluster-based development, strengthening traditional industries, and enhancing rural livelihoods. A total of 513 clusters has been approved across the country since 2015-16, with a approved committed Government of India assistance of ₹1,332.95 crore. These clusters are proposed to benefit approximately 3.03 lakh traditional artisans engaged in diverse sectors such as handicrafts, handloom, agro-processing, coir, honey, and related activities. Of the total clusters approved, 378 clusters are currently functional, while 135 clusters are under various stages of implementation as on date, contributing to infrastructure development, skill enhancement, value addition, and improved market linkages at the grassroots level. **Under Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme (MSE-CDP), the admissible components/area for setting up of Common Facility Centres (CFCs) inter alia include:**

Industry 4.0 and its Learning Facilities, Additive Manufacturing Facilities, Digital Infrastructure.
Design/Incubation Centres.
Training Centre / Skill Upgradation Facilities.
R&D Centres.
Common Renewable Energy Generation (Solar, Wind, Bio) and Energy Management equipment.
CFC for Greenfield clusters for holistic developments of MSME sector.
MSE-CDP is a demand driven Central Sector Scheme wherein, State Governments send proposals as per common needs of existing cluster in their States/UTs

The industrial landscape in the country has witnessed increased digitalisation in recent years, with enhanced operational efficiency for MSME in value creation and competitiveness. There is increasing participation in digital payments, e-commerce transactions, IOT enabled production tools and AI based technologies for improved business operations. To promote digital upgradation and adoption of emerging technologies for greater productivity and competitiveness among MSME, Government has taken several initiatives. These include Ministry of Electronics and Information Technology platforms like DigiLocker and IndiaAI Datasets Platform aimed at empowering MSME to become resilient, competitive and sustainable by leveraging digital technologies, and Department of Telecommunications networks like BharatNet and PM-WANI for affordable access and last mile connectivity. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is supporting digital empowerment of MSME through digital registration under Udyam, training in Tool Rooms /Technology Centres for technology adoption, incubation of new ideas and technologies through MSME Innovative scheme and MSE Green Investment for Financing Transformation scheme for promoting investment in green technologies. Components of financial incentives, capacity building and awareness are suitably embedded in the design of the above Government funded schemes. The Ministry has launched Trade Enablement and Marketing (TEAM) scheme which aims at facilitating Micro and Small Enterprises for onboarding onto Open Network for Digital Commerce (ONDC) by providing financial assistance to Seller Network participants (SNPs) for onboarding, cataloguing, account management, logistics, packaging material and design. Notably, half of these beneficiary MSMEs will be women-owned enterprises. This information was given by the Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises Sushri Shobha Karandlaje in a written reply in Lok Sabha on 12th March 2026.

Regional Workshop on Tele-Law Programme under DISHA Scheme organised in Chennai, Tamil Nadu

Chennai, Focus News: A Regional Workshop on Tele-Law Programme Activities under the Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice (DISHA) Scheme of the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, was held today at Kalaivanar Arangam, Chennai. The workshop aimed to strengthen technology-enabled justice delivery and deepen stakeholder engagement in ensuring last-mile access to justice. The event was graced by Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Tamil Nadu; Sushrut Arvind Dharmadhikari, Chief Justice of the Madras High Court; and Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice, along with senior officials, members of the judiciary, advocates, representatives of Common Service Centres (CSCs), law schools, students and civil society representatives. Delivering the keynote address, Governor Shri Arlekar highlighted the importance of integrating technology, legal awareness and community participation to ensure effective justice delivery. He emphasised that citizens must understand and respect the law, and that justice must reach even those in remote villages. Strengthening public faith in the judiciary, he noted, is essential for achieving the vision of a Viksit Bharat. Chief Justice Dharmadhikari J stated that access to justice is a fundamental constitutional obligation rooted in Articles 14, 21 and 39A. He appreciated initiatives such as Tele-Law, Nyaya Bandhu and legal awareness programmes, observing that technology-enabled platforms can significantly strengthen citizen engagement with legal institutions. He also described the DISHA initiative as a legal first-aid kit that moves the country from legal aid towards legal empowerment. Addressing the gathering, Union Minister Shri Meghwal underscored the importance of leveraging technology to make justice more accessible, affordable and citizen-centric. He highlighted that initiatives such as Tele-Law, Nyaya Bandhu and legal literacy programmes are strengthening the justice delivery ecosystem and expanding legal services at the grassroots level. Earlier, the Secretary, Department of Justice, briefly outlined the objectives of the DISHA framework and emphasised that awareness is the first step towards empowerment and inclusive justice delivery. A presentation on the progress of the Tele-Law programme in Tamil Nadu highlighted that services are being delivered through more than 12,560 Common Service Centres across all 38 districts and 16 aspirational blocks, along with the toll-free helpline 14454 and the Tele-Law mobile application. During the programme, videos on the Nyaya Oli Project implemented through Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry, and the Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services) Programme were screened. As of February 2026, more than 10,000 advocates have registered under Nyaya Bandhu, with Pro Bono Clubs established in 109 law colleges across the country. Ten e-books documenting customary laws of tribal communities from the North-Eastern region were also launched in collaboration with the Law Research Institute of the Gauhati High Court. The workshop concluded with a vote of thanks by the Joint Secretary (Access to Justice), Department of Justice.

Department of Commerce organizes Chintan Shivir on strengthening India's Medical Devices export ecosystem

New Delhi, Focus News: A Chintan Shivir on "Strengthening India's Medical Devices Export Ecosystem" was organized by the Department of Commerce in collaboration with the Department of Pharmaceuticals and the Export Promotion Council for Medical Devices (EPCMD) at Vanijya Bhawan, New Delhi today. The event brought together policymakers, regulators, industry leaders, exporters and sector experts to deliberate on strategies for strengthening India's global competitiveness in the MedTech sector. The discussions were held under the theme "Achieving 30@2030 – USD 30 Billion Market Size by 2030." The event witnessed participation of over 150 participants from government, industry, regulatory bodies and the broader medical devices ecosystem. The Chintan Shivir served as a platform for structured engagement between the Government and industry stakeholders to identify key policy priorities, address regulatory and infrastructure bottlenecks, and explore emerging opportunities for strengthening India's medical devices manufacturing ecosystem and export capabilities. India's medical devices sector has emerged as a critical component of the country's healthcare and manufacturing landscape. With growing global demand for affordable and high-quality medical technologies, India is increasingly positioning itself as a reliable manufacturing and export hub. In the inaugural session, Forum Coordinator, AiMeD, Shri Rajiv Nath shared the industry perspective and emphasized the need for continued government–industry collaboration to address global regulatory challenges and scale domestic manufacturing. Addressing the gathering, Joint Secretary, Department of Pharmaceuticals, Shri Aman Sharma highlighted the importance of focusing on the quality of medical devices manufacturing in the country and emphasized that both industry and regulators need to work together towards this objective. Delivering the special address, Additional Secretary and Director General, Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Shri Lav Aggarwal emphasized the need to grow faster by addressing structural issues. He highlighted the role of trade policy measures and export promotion initiatives in expanding India's presence in global medical devices markets.

The Chintan Shivir was formally inaugurated by Secretary, Department of Commerce, Shri Rajesh Agarwal. In his inaugural address, he emphasized that India must move beyond its identity as the "Pharmacy of the World" to emerge as a global MedTech manufacturing hub. Noting that India's medical device exports have crossed USD 4 billion in FY25, Shri Agarwal highlighted the need to significantly enhance India's global market share over the next decade with a strong focus on high-value manufacturing, research and development investments, incremental innovation and regulatory harmonization. He also emphasized the broader goal of achieving a USD 30 billion medical devices market by 2030 while leveraging India's significant domestic market for scaling. The Chintan Shivir featured three thematic sessions focusing on key aspects of strengthening India's medical devices export ecosystem. The first session, titled "Global Trade Deals and India's MedTech Exports: New Pathways Opened by Global FTAs," deliberated on opportunities emerging from India's expanding network of trade agreements and strategies for enhancing market access in global markets. The second session focused on "MedTech Export Infrastructure and Global Brand Building," highlighting the need to strengthen manufacturing clusters, expand testing infrastructure and build global brand recognition for Indian medical devices. The third session discussed "Evolving Regulatory Frameworks to Support Medical Device Exports," with emphasis on regulatory harmonization, streamlining approval processes and improving coordination between industry and regulators to facilitate exports. The Chintan Shivir concluded with discussions on actionable pathways for strengthening India's medical devices manufacturing ecosystem and enhancing export competitiveness.

Dr Mansukh Madnaviya and H D Kumaraswamy lays foundation of indoor sports complex in Mandya in Karnataka

New Delhi, Focus News: Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya and Union Minister for Heavy Industries and Steel H.D. Kumaraswamy on Saturday performed the Bhoomi Pooja and laid the foundation stone for a ₹14-crore multi-purpose indoor sports complex sanctioned for Mandya in Karnataka under the Khelo India scheme of the Government of India. The new facility is coming up within the campus of the University of Agricultural Sciences at VC Farm in Mandya. While laying the foundation stone, the two ministers called upon the youth of the district to strengthen sports culture in Mandya in line with the slogan "Khelo India! Vibrant Mandya!", and to produce more champions from the region. On this occasion, both Union Ministers participated in the ceremonial rituals of the foundation-laying programme. Former Minister C.S. Puttaraju, Melukote MLA Darshan Puttannaiah, K.R. Pete MLA Manjunath, along with several public representatives and senior district officials, were present.

Mandya praised for sporting achievements: Addressing the gathering during the stage programme, Union Sports Minister Dr Mansukh Mandaviya said that the Khelo India initiative is a national programme launched by the Central Government to revive sports culture at the grassroots level and transform India into a leading sporting nation. The Sports Minister stated that the establishment of this well-equipped sports complex in Mandya has been made possible through the efforts of his Cabinet colleague and NDA leader H.D. Kumaraswamy. Addressing Kumaraswamy, Mandaviya said that the affection shown by the people reflects the work he has done for them. He also appreciated Kumaraswamy's compassion and commitment toward persons with disabilities. Mandaviya said that he had personally witnessed Kumaraswamy's concern for the specially-abled and described the initiative of distributing electric vehicles as highly commendable. He noted that such efforts not only help persons with disabilities in their daily lives but also contribute positively to environmental protection. Mandaviya further said that Mandya has produced several sportspersons who have brought recognition not only to the state but also to the country at national and international levels. He recalled athletes such as Vikas Gowda and K.P. Shilpa, who have enhanced the reputation of Mandya. In particular, he highlighted wheelchair tennis player Shilpa, who is currently India's number-one wheelchair tennis player and has been bringing glory to the country both nationally and internationally. Expressing hope, he said that many more talented sportspersons should emerge from Mandya in the coming years. The Union Minister also stated that the government led by Prime Minister Narendra Modi has worked extensively over the past eleven years to strengthen the sports ecosystem in India. In the latest Union Budget, ₹4,000 crore has been allocated to strengthen sports infrastructure, compared to ₹1,200 crore a decade ago, effectively increasing the allocation more than threefold.

G. Kishan Reddy, Inaugurates Multiple Projects in WCL

New Delhi, Focus News: Union Minister of Coal and Mines, G. Kishan Reddy, who is on a two-day visit to Western Coalfields Limited (WCL), virtually inaugurated and laid the foundation stone for various important projects and conducted a review meeting of WCL on Friday. During the program, Union Minister virtually flagged off 25 electric vehicles. Shri Reddy also virtually laid the foundation stones for the 'Black Diamond Sports Stadium' in Kamptee, Nagpur area, the 'Swami Vivekananda Eco Park' in Tadali, Wani area, and the First Mile Connectivity Project at Sasti Open Cast Mine in Ballarpur area. These projects will promote infrastructure development, environmental protection, and modernization of mining operations in the region. Subsequently, he reviewed WCL's work related to coal production, safety, sustainable development, environmental protection, and future projects. In the review meeting, Shri Reddy praised Team WCL's work culture and performance, expressing expectations for better results in the current financial year. He elaborated on WCL's role in the changing landscape of the coal industry. During the review meeting, Shri Harish Duhan, CMD of WCL, provided detailed information about the achievements of WCL during the financial year 2025-26. Shri Sanoj Kumar Jha, Additional Secretary, Ministry of Coal; Shri B. Sairam, Chairman, Coal India Limited and other senior officers of the Ministry of Coal, Coal India Limited and WCL were also present. The Minister will visit the Murpar underground mine on March 14, 2026, to inspect the ongoing mine closure process. Following this, the minister will hold a meeting with the District Collector and the Mine Closure Advisory Committee (MCAC). WCL's Mine Closure Nodal Officers, Non-Governmental Organizations (NGOs), consultants, and representatives from local villages will be present during this meeting.

Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia

New Delhi, Focus News: The Government of India today held the fourth inter-ministerial media interaction at the National Media Centre to provide updates on the situation arising from recent developments in West Asia. Similar briefings were earlier held on 11, 12 and 13 March 2026. Senior officials from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of External Affairs, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and Ministry of Information and Broadcasting shared updates on energy supply, maritime operations, the welfare of Indian nationals in the region and related communication measures.

Energy Supply and Fuel Availability: The officer from the Ministry of Petroleum and Natural Gas briefed the media on the fuel supply situation in the country and the arrangements to ensure continued availability of petroleum products and LPG, in view of the prevailing geopolitical developments and the situation relating to the Strait of Hormuz. As per the Ministry:

Crude/Refineries : All refineries are currently operating at high levels and maintaining adequate crude oil inventories. Further, our country is self-sufficient in the production of petrol and diesel, and no imports of Petrol & diesel are required for meeting domestic demand.

Retail Outlets: No cases of fuel dry outs have been reported at any of the ROs by the Oil Marketing Companies. The Government advises the public not to resort to panic buying, as adequate stocks of petrol and diesel are available and supplies are being maintained regularly.

Natural Gas: Priority sectors have been protected for their supplies including 100% supply to PNG and CNG with no cuts. So, there is no need to panic. Supplies to industrial & commercial consumers are being regulated at 80%. GAIL held VC with City Gas Distribution (CGD) entities authorized in major urban centres/cities e.g. Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Lucknow, Kanpur, Jaipur etc. in the country and advised them for expediting and promoting new commercial PNG connections for hotels and restaurants so as to reduce pressure on LPG supplies.

LPG: Supply of LPG is still a concern in view of prevailing geopolitical situation.

No reported dry-out at LPG distributorships.

There has been surge in the number of LPG bookings on account of panic buying. Daily bookings have increased from avg. 55.7 Lakh to 88.8 Lakh yesterday.

Commercial Cylinders for consumers have been put at the disposal of State Government for priority distribution. Commercial LPG have been made available to consumers in 29 States/UTs. Online bookings of cylinders at present is 84%.

Meetings conducted by State Government: The role of State/UT Governments is very important in monitoring supply situation of essential commodities including Petrol, Diesel and LPG. Hon'ble Chief Ministers of Haryana and Goa have conducted meetings with senior government officials and top officials of oil companies to review the demand and supply situation of LPG in the state.Telangana Chief Secretary reviewed the LPG stock position, supply, and distribution to consumers with representatives of oil marketing companies and officials of the Civil Supplies Department. Meeting was also conducted by Oil Companies with Andhra Pradesh's Commissioner of Civil Supplies and appraised him of all the developments w.r.t LPG, PDS SKO and Commercial LPG. 17 States/UTs have setup control rooms to monitor situation and many States/UTs are doing press briefs also.

Enforcement action: State Governments/UTs are playing a key role in preventing hoarding and black marketing of essential commodities including Petrol, Diesel and LPG. In Maharashtra and Rajasthan, joint inspection teams of the Food & Civil Supplies Department and Oil Marketing Companies conducted raids at multiple locations. PSU OMCs also carried out around 1300 inspections at LPG distributorships yesterday. In Uttar Pradesh, enforcement teams inspected 1,483 locations; 24 FIRs were registered (4 against LPG distributors and 20 against individuals), 6 persons were arrested and prosecution initiated against 19 individuals. Raids have also been conducted in several States including Andhra Pradesh (Tirupati), Bihar, Odisha and Karnataka to check hoarding and black marketing of LPG.

INDIAN NAVAL SHIP TRIKAND CONCLUDES PORT CALL AT PORT LOUIS, MAURITIUS

New Delhi, Focus News: INS Trikand concluded her port call at Port Louis, Mauritius on 13 Mar 26. The ship participated in the 58th Mauritius National Day Parade on 12 Mar 26 with a marching contingent, naval band and integral helicopter for the fly-past, at Champ de Mars, Port Louis. This is in keeping with the tradition of Indian warships and aircraft participating in Mauritius National Day celebrations. During the port call, Captain Sachin Kulkarni, Commanding Officer of the ship, called on Mr Rampersad Sooroojebally, PMSM, Commissioner of Police, and H.E Mr Anurag Srivastava, the High Commissioner of India to Mauritius. The ship also hosted a cultural evening onboard, with Dr Mahend Gungapersad, Minister of Education and Human Resources of Mauritius, as the Chief Guest. The event was attended by senior ministers and officials from the Government of Mauritius. The ship also progressed several professional interactions, cultural engagements, sports fixtures and community outreach activities to further strengthen the robust bonds between the two nations. Training capsules were also conducted onboard for Mauritius National Coast Guard personnel on practical aspects of harbour and sea watchkeeping, including firefighting and damage control. The ship was open to visitors on 12 Mar 2026 and hosted over 500 visitors. On departure from Port Louis, INS Trikand undertook a Passage Exercise (PASSEX) and joint Exclusive Economic Zone (EEZ) surveillance with CGS Valiant, and thereafter proceeded for the next phase of her planned operational deployment. The port call reaffirms the longstanding maritime partnership and strengthening bilateral ties between the two countries, aligned with India's vision of MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions, and reaffirms the strong bilateral ties between India and Mauritius.

सिंधिया ने देश के पहले 'समृद्धि केंद्र' का किया उद्घाटन

भोपाल, फोकस न्यूज, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में देश के पहले समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि दूरसंचार विभाग की 'समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवाएं' पहल के अंतर्गत स्थापित यह देश का पहला ऐसा केंद्र है, जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और कृषि से संबंधित विभिन्न सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। बयान के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और भौतिक सेवाओं के एकीकृत माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर सिंधिया ने शनिवार को केंद्र में उपलब्ध सेवाओं और उपकरणों का स्वयं निरीक्षण किया और वीआर (वर्चुअल रियलिटी) उपकरण पहनकर उनके उपयोग का अनुभव लिया और उपस्थित ग्रामीणों को इन तकनीकों के माध्यम से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण भारत को डिजिटल सशक्तिकरण और सेवा सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समृद्धि केंद्र ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

न्यायिक प्रणाली को अस्पतालों की तरह ही सेवा भाव से काम करना चाहिए : सीजेआई सूर्यकांत

मंडी। फोकस न्यूज। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि न्यायिक परिसरों को अस्पतालों की तरह ही सेवाभाव की भावना से काम करना चाहिए, क्योंकि लोग न्याय और राहत की उम्मीद लेकर अदालतों में आते हैं। मंडी के न्यायिक अदालत परिसर की आधारशिला रखने के बाद एक विधि साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सुविधाओं में वृद्धि के साथ न्यायिक प्रणाली की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि चर्चा अक्सर मौलिक अधिकारों पर केंद्रित रहती है, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मंडी न्यायिक अदालत परिसर का निर्माण 9.6 हेक्टेयर क्षेत्र में 152 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। परिसर में चार ब्लॉक होंगे, जो न्यायाधीशों, वकीलों और आम लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय और अधिकार उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान की भावना के अनुरूप समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने लोक अदालतों के माध्यम से लगभग 5.5 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा कि आज की चर्चा न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि न्याय केवल अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अधिकारों के प्रति जागरूकता, कानूनी सहायता की उपलब्धता और समय पर मदद सुनिश्चित करना भी शामिल है।

पश्चिम एशिया संघर्ष के नाजुक माहौल में भी 'नादानी' से बाज नहीं आ रहे राहुल गांधी : मोहन यादव

नेपानगर, (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि वह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के नाजुक माहौल में भी नादानी का परिचय देते हुए रसोई गैस को लेकर अनर्गल राजनीति कर रहे हैं। यादव, बुरहानपुर जिले के नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा,''पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध में तेल के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। युद्ध पूरे एशिया के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन कांग्रेस ऐसे मुश्किल वक्त में भी रसोई गैस के मुद्दे पर अनर्गल राजनीति कर रही है।'' यादव ने कहा कि घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग की रसोई गैस की भारत में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा,''इस मामले में केवल कांग्रेस को कष्ट है जिसके नेता (रसोई गैस के मुद्दे पर) आंदोलन का नाटक कर रहे हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको पता है कि भारत को तेल और गैस के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के नाजुक माहौल में भी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी नादानी से बाज नहीं आ रहे हैं और अनर्गल राजनीति कर रहे हैं। यादव ने कहा कि अगर गांधी इसी तरह राजनीति करते रहे, तो कांग्रेस अगले 50 साल तक सत्ता से दूर रहेगी क्योंकि जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि रूस–यूक्रेन युद्ध छिड़ने पर भी कांग्रेस नेता कथित रूप से अनर्गल बयान दे रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया था। यादव ने कहा,''कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न जाने कहां से ढूंढकर लाए हैं। गांधी लोकतंत्र का जब–तब मजाक बनाते रहते हैं। जब भी भारत में चुनौतियां सामने आती हैं, वह विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हैं। फिर वह कहते हैं कि लोकसभा में उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता है।'' उन्होंने कहा कि गांधी जब भी संसद में बोलते हैं, कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने जनजातीय सम्मेलन के दौरान बुरहानपुर जिले में कुल 363 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर असीरगढ़ के किले के जीर्णोद्धार और किले में पर्यटन सुविधाओं के विकास की घोषणा भी की।

चुनावी राज्यों में कई मतदान केंद्र होंगे अनूठे

नयी दिल्ली, (भाषा) पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में 1,500 से कम मतदाताओं वाले तीन मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम को बक्सा बाघ अभयारण्य की पहाड़ियों से होकर गुजरना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी। कुमार ने विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने के लिए यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित अनूठे मतदान केंद्रों पर प्रकाश डाला। सीईसी ने कहा, ''मतदान टीम असम के माजुली से नौका और सड़क मार्ग से 50–60 किलोमीटर की कठिन यात्रा करती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को पार करती हैं और अंत में ट्रैक्टर से 248 मतदाताओं वाले सुदूर धनेखाना मतदान केंद्र पहुंचती हैं।'' कुमार ने बताया कि केरल के एडामलकुड्डी के आदिवासी क्षेत्र में स्थित एक बूथ पर कुल 693 मतदाता पंजीकृत हैं और यह एक अनूठा दूरस्थ मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी विशेष वाहनों पर ऊबड़–खाबड़ दुर्गम इलाके से होते हुए 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, आठ किलोमीटर पैदल चलकर इस मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। सीईसी के मुताबिक, अलीपुरद्वार जिले में, मतदान टीम बक्सा बाघ अभयारण्य की पहाड़ियों से होते हुए तीन मतदान केंद्रों तक पहुंचती हैं, जहां क्रमशः बक्सा में 759, चुनाभट्टी में 235 और अदमा में 445 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के थेनी जिले में वरुसनद पहाड़ियों में, मतदान अधिकारी वेल्लीमलाई मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए कठिन इलाकों से होते हुए तीन घंटे की यात्रा करते हैं जहां मात्र पांच मतदाता पंजीकृत हैं। कुमार ने कहा, ''पुडुचेरी में 1885 में निर्मित वी ओ चिदंबरम पिल्लई स्कूल को एक मॉडल मतदान केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिसमें क्रमशः 722 और 651 मतदाताओं वाले दो मतदान केंद्र हैं।'' निर्वाचन आयोग ने रविवार को चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की।

कांशीराम को 'भारत रत्न' देने में विलंब न करे केंद्र सरकार: मायावती और राहुल गांधी

लखनऊ/नयी दिल्ली, (भाषा) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार से पार्टी संस्थापक कांशीराम को 'भारत रत्न' देने में अधिक विलंब ना करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को 'भारत रत्न' नहीं देने की कांग्रेस की गलती को न दोहराये। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कांशीराम को 'भारत रत्न' सम्मान देने की गुजारिश की। मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से काशीराम को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने में विलंब ना करने की मांग की। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करने की गलती की थी और वर्तमान में केन्द्र की भाजपा /राजग सरकार भी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को भारतरत्न से सम्मानित करने में देरी ना करे क्योंकि देश में संविधान की मंशा के अनुसार समतामूलक समाज तैयार करने के मामले में उनका योगदान ऐतिहासिक है और इस कारण वह भी लोगों के दिलों में बसते हैं।" मायावती ने अपने शासनकाल में कांशीराम के नाम पर बनाए गए 'मान्यवर श्री कांशीराम उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय' का नाम पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार और वर्तमान में भाजपा नीत सरकार द्वारा बदले जाने की भी आलोचना की तथा कहा कि ऐसी संकीर्ण, जातिवादी, साम्प्रदायिक व द्वेषपूर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों व इनकी सरकारों से 'बहुजन समाज' का वास्तविक हित व कल्याण की आशा करना 'रेगिस्तान में पानी तलाशने' जैसा असंभव है। वहीं नयी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बसपा के संस्थापक कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान होगा, जो कांशीराम को सशक्तीकरण और आशा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। राहुल ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि कांशीराम ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया और अपने आंदोलनों के माध्यम से बहुजनों व गरीबों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पत्र में कहा, "आज (रविवार को) जब हम कांशीरामजी की जयंती मना रहे हैं और उनकी विरासत व योगदान पर विचार कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।" उन्होंने कहा, "कांशीराम जी ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया। अपने आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने बहुजनों और गरीबों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनका मत, उनकी आवाज और उनका प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है और यह देश सभी का समान रूप से है।" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "कई साल से दलित बुद्धिजीवी, नेता और कार्यकर्ता कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते आ रहे हैं। उनकी यह मांग निरंतर और गहरी भावना से भरी रही है। हाल ही में, मैंने लखनऊ में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उपस्थित नेताओं और प्रतिभागियों ने इस मांग को दृढ़ता से दोहराया, जो एक व्यापक भावना को दर्शाता है।" राहुल ने कहा कि कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना देश के प्रति उनके अपार योगदान को मान्यता देगा।